



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1967 (फाल्गुन 13, 1888)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1967 (PHALGUNA 13, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस NOTICE

नीचे लिखा भारत का असाधारण राजपत्र 14 फरवरी, 1967 तक प्रकाशित किया गया :—

The undermentioned Gazette of India Extraordinary was published up to the 14th February, 1967:—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------

29. No. 5-ETC(PN)/67, dt. 14th Feb. 1967. Ministry of Commerce. Export of Raw Jute and Mesta to Nepal.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)		पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	211	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	11
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	199	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	141
		भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
		भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—

	पृष्ठ (Page)		पृष्ठ (Page)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	283	भाग III—खंड 2—एकम्ब कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसे	91
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	523	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	37
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	49	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसे शामिल हैं ..	101
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	117	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसे	37
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	211	पूरक सं० 9—	
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	199	25 फरवरी 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	297
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	11	4 फरवरी 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े ..	313
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	141	PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	523
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	49
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	117
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	283	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	91
		PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	37
		PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	101
		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	37
		SUPPLEMENT No. 9—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 25th February 1967	297
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 4th February 1967 ..	313

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 1967

सं० एफ० 13/12/66-समन्वय—योजना आयोग और उसके सदस्यों से निष्पत्ति तथा निरन्तर सम्बन्ध रखकर कार्य करने के लिए, विशेषज्ञों के एक छोटे दल के रूप में राष्ट्रीय आयोजन परिषद् का, योजना आयोग की अधिसूचना संख्या एफ० 15/1/65-समन्वय दिनांक 26 फरवरी 1965 में गठन किया गया था। इसकी अवधि, जो मूलतः दो वर्ष के लिए थी, में आगे एक वर्ष की और वृद्धि कर दी गई है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सब सम्बन्धित व्यक्तियों/कार्यालयों को भेज दी जाय और इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

के० ए० पी० स्टीवेन्सन, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1967

सं० 20/1/67 ए० आई० एस० (1)—निम्नलिखित सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए, अवतूबर, 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम, संबंधित मंत्रालयों की ओर भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की सहमति से, आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

वर्ग-I

- (i) भारतीय प्रशासन सेवा, और
- (ii) भारतीय विदेश सेवा।

वर्ग-II

- (i) भारतीय पुलिस सेवा, और
- (ii) दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, क्लास II।

वर्ग-III

(क) क्लास-I की सेवाएं :—

- (i) केन्द्रीय सूचना सेवा, (ग्रेड II) क्लास-I,
- (ii) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,

(iii) भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा,

(iv) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,

(v) भारतीय-आय कर सेवा (क्लास I),

(vi) भारतीय डाक सेवा,

(vii) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, और

(viii) भारतीय रेल यातायात सेवा।

(ix) सैन्य भूमि तथा सैन्य छावनी सेवा, क्लास I

(ख) क्लास-II की सेवाएं :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी, ग्रेड, क्लास-II,

(ii) सीमा-शुल्क मूल्य निरूपक (एग्जैर) सेवा, क्लास II,

(iii) दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, क्लास 2।

(iv) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, क्लास II और

(v) सैन्य भूमि और सैन्य छावनी सेवा, क्लास 2।

1. उम्मीदवार उपर्युक्त सेवा-वर्गों में से किसी एक या एक से अधिक के लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकते हैं (देखिये नियम 4) उसे सम्बन्धित वर्ग/वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उन सभी सेवाओं का, जिनके लिए वह विचार किए जाने का इच्छुक है, अपने आवेदन-पत्र में उल्लेख कर देना चाहिए।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा प्रकाशित नोटिस में किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1965 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964।

3. संघ शोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय प्रशासन सेवा आदि में भर्ती के लिए ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता-परीक्षा को इन तीन वर्गों की सेवाओं को, यानी, (i) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा, (ii) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, और (iii) केन्द्रीय सेवाएं और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के लिए, अलग-अलग तीन परीक्षाएं समझा जायेगा।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन, दियू का निवासी न हो या कीन्या, उगांडा, संयुक्त गणराज्य टेन्जानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से न आया हो तो उसे ऊपर नियम 4 में उल्लिखित तीन वर्गों में से प्रत्येक की सेवाओं के लिए प्रतियोगिता-परीक्षा में अधिक से अधिक दो बार सम्मिलित होने दिया जाएगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध 1961 की परीक्षा से लागू है।

नोट :—यदि उम्मीदवार ने वस्तुतः एक या अधिक विषयों की परीक्षा दी हो तो यह माना जाएगा कि वह प्रतियोगिता में बैठ चुका है।

6. (i) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(ii) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी को भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से ऐसा भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) देशों से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए और यदि वह (च) कोटि का हो तो पात्रता प्रमाणपत्र एक वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार की नौकरी तभी जारी रखी जाएगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

लेकिन नीचे लिखे उम्मीदवारों को पात्रता-प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले, पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और तब से आम तौर से भारत में ही रह रहे हों।

(ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो।

(iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान, लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल का क्रम नहीं टूटा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसे 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा में दुबारा नियुक्त किया गया हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता-प्रमाण-पत्र देना होगा।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

7. (क) (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और बाकी सभी सेवाओं के लिए सिवाय पैरा (i) में उल्लिखित भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं में उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त, 1967 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो किन्तु 24 वर्ष की न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1943 से पहले और 1 अगस्त, 1946 के बाद नहीं हुआ हो।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त, 1967 को पूरे 20 साल की हो गई हो, किन्तु 24 साल न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1943 से पहले और 1 अगस्त, 1947 के बाद न हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष;

- (iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष
- (iv) यदि उम्मीदवार सब राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,
- (v) यदि उम्मीदवार अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष
- (vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्टूबर 1964 में भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका में वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति भी हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष
- (vii) यदि उम्मीदवार गोजा, दमन और दियु के सब राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,
- (viii) यदि उम्मीदवार कीनिया, उगांडा, तथा मगुस्त रण राज्य टैंगानिया (मूलपूर्व टंगानिका तथा जर्जिया) में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,
- (ix) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 का या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष, और
- (x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष।
- (xi) यदि उम्मीदवार रक्ष सेवाओं में गिरफ्तार हुआ मूलपूर्व सैनिक हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष, और
- (xii) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं में विद्वान हुआ मूलपूर्व सैनिक हो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़ कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी में छूट नहीं दी जाएगी।

8 उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में उल्लिखित विद्यालयों में से किसी एक की कोई उपाधि होनी चाहिये अथवा उसके पास परिशिष्ट I-क में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए।

नोट—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (यवालीफाइन

एक्जामिनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार को, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो, तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वह अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता, तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

नोट II—विशेष परिस्थितियों में, सब लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षा पास की हो जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

नोट III—यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय में उपाधि ली हो जो परिशिष्ट I में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

9 यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय विदेश सेवा) की किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह केवल उन्हीं सेवाओं के लिए इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तम्भ (ii) में उल्लिखित हैं —

क्रम	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र है
1	2	3
1	भारतीय पुलिस सेवा	(i) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा)। (ii) वर्ग III में, केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I।
2	केंद्रीय सेवाएं, क्लास I	(i) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा)। (ii) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा।
3	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास II, दिल्ली, त्रिमाचल प्रदेश तथा अडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा।	(i) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा) (ii) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा। (iii) वर्ग III में केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I।

10 उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट I में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

11 जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी रूप में पहले से ही सरकारी सेवा करता हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग के अध्यक्ष की अनुमति अवश्य लेनी होगी।

12 परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-प्रमाण-पत्र (मार्तिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए हुए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने के फल-स्वरूप अपराधी घोषित किया है तो उसके विरुद्ध दण्डिक अभियोग के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है —

(क) सजा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए परीक्षा वारित किया जाना —

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अंतर्गत नाकरियों के लिए।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित स्थितियों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

16 जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अंकों (Qualifying Marks) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निर्धारित करे, तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षा (Personality Test) के इंटरव्यू के लिए बुलायेगा।

17 परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम में उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा, उनकी इन गतियों पर नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की जाएगी। यह भर्ती आरक्षित रूप में न होकर इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगी।

लेकिन शर्त यह है कि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जाति आदि जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर

नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उनकी उस सेवा में यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित गतियों पर नियुक्ति के लिये आयोग सिफारिश करेगा।

18 प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

19 उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र देते समय अपना जो अधिमान-क्रम (Preference) बताया होगा, उस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा; परन्तु भारत सरकार को उसे ऐसी कोई भी सेवा सौंपने का अधिकार है जिसके लिए वह उम्मीदवार हो।

लेकिन शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा के आधार पर वर्ग I (भा० प्र० से० अथवा भा० वि० से०) के अंतर्गत आने वाली किसी सेवा में नियुक्त किया गया है, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

एक अन्य शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर नीचे के कालम (ii) में उल्लिखित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है, तो इस परीक्षा परिणाम के आधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्ही सेवाओं में की जा सकेगी, जो उक्त सेवा के सामने कालम (iii) में दी गई हैं:—

क्रम संख्या	सेवा जिसमें नियुक्ति की गई	सेवा जिसमें नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा
(i)	(ii)	(iii)
1	भारतीय पुलिस सेवा	(i) वर्ग I (भा० प्र० से० तथा भा० वि० से०)। (ii) वर्ग III में दी गई क्लास I की केन्द्रीय सेवाएं।
2	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I	(i) वर्ग I (भा० प्र० से० तथा भा० वि० से०)। (ii) वर्ग II में दी गई भारतीय पुलिस सेवा।
3	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-II दिल्ली-हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा।	(i) वर्ग I (भा० प्र० से० तथा भा० वि० से०)। (ii) वर्ग II में दी गई भारतीय पुलिस सेवा। (iii) वर्ग III में दी गई क्लास I की केन्द्रीय सेवाएं।

20. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

21. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें : नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में इन निर्णयों के परिशिष्ट 4 में दिये गए हैं।

रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवा (ओं) की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

22. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किए जाने के कारण अवैध (वायड) हो जाए तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर, नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक प्राप्त नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दी जाए।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण अवैध (वायड) हो कि उक्त विवाह के समय उसके पति की जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, वह उन सेवाओं में नियुक्ति की, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक प्राप्त नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, और उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दी जाए।

23. भारत सरकार को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह किसी ऐसी महिला उम्मीदवार को जो विवाहित है भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा/दिल्ली हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा में नियुक्ति न करे अथवा नियुक्ति के बाद अगर वह विवाह कर ले तो उससे त्यागपत्र मांग ले, यदि ऐसा करना सेवा की कुशलता बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक हो।

24. भारतीय विदेश सेवा की लिए तो कोई महिला उम्मीदवार नभी पात्र हो सकती है जबकि वह अविवाहित हो अथवा विधवा हो और उस पर कोई भार (इन्कम्बरन्स) न हो। यदि कोई महिला उम्मीदवार खुदी गई तो उसे इस स्पष्ट बात पर नियुक्ति किया जाएगा कि यदि उसने विवाह या पुनर्विवाह किया तो उसे सेवा से त्यागपत्र देने को कहा जा सकता है।

भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों का सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जा रही है उनकी संक्षिप्त बयौरा परिशिष्ट III में दिया गया है।

ए० एन० बटव्याल,
अवर सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची
(नियम 8 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम से निर्गमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद के अधिनियम से स्थापित किया गया हो। अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय।

मांडले विश्वविद्यालय।

इंग्लैण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और सेंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।

नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

ठाका विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू।

परिशिष्ट I—क

भारत सरकार ने निम्नलिखित योग्यताओं को उपर्युक्त में प्रत्येक के सामने लिखी डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्रदान की है :—

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये अनुमोदित योग्यताओं की सूची (नियम 8 के अनुसार)

1. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगडी, हरिद्वार की अलकार परीक्षा।
2. काशी विद्यापीठ, वाराणसी, की शास्त्री परीक्षा।
3. फ्रांसीसी परीक्षा (Baccalaureat)।
4. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique)।
5. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल ऑफ़ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
6. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
7. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ऑल इंडिया कौंसिल फॉर टेक्निकल एज्यूकेशन) से वाणिज्य में डिप्लोमा।
8. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियर में डिप्लोमा।
9. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम", यदि "पूर्व छात्र" (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
10. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, के खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।

परिशिष्ट II

खण्ड I

लिखित परीक्षा की रूपरेखा

लिखित परीक्षा के विषय :—

(क) लिखित परीक्षा

- (i) तीन अनिवार्य विषय (सभी सेवाओं के लिए) निबन्ध, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, प्रत्येक विषय के पूर्णांक 150 होंगे। (नीचे खण्ड-ii का उपखण्ड (अ) देखें);
 - (ii) निम्नलिखित खण्ड-ii के उप-खण्ड (ब) में दिए गए ऐच्छिक विषयों में से चुने गए विषय। सेवा श्रेणी-ii को छोड़ (नियम 1 और 4 देखें) शेष सभी सेवाओं के उम्मीदवार, उस उप-खण्ड के उपबन्ध के अधीन, कुल 600 अंकों तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं।
- भारतीय पुलिस सेवा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा श्रेणी-ii के लिए उम्मीदवार कुल 400 अंकों तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर किसी

भारतीय विश्वविद्यालय को अनार्ज डिग्री की परीक्षा के स्तर के लगभग होगा; और

- (iii) निम्नलिखित खण्ड-ii के उप-खण्ड (म) में दिए गए अतिरिक्त विषयों में से चुने गए विषय। उस उप-खण्ड के उपबन्ध के अधीन उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा (श्रेणी-i) के लिये कुल 400 अंकों तक के अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐच्छिक विषय के लिए उप-खण्ड (क-v) में विहित स्तर से ऊंचा होगा।

- (ख) ऐसे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा के साक्षात्कार के लिये (इस परिशिष्ट की सूची के भाग (ग) के अनुसार बुलाए जाएंगे, उसके लिए नीचे लिखे नम्बर होंगे :—

श्रेणी-I

	पूर्णांक
भारतीय प्रशासनिक सेवा	300
भारतीय विदेश सेवा	400

श्रेणी II और III

सभी सेवाएं	200
----------------------	-----

खण्ड II

(अ) अनिवार्य-विषय

[देखिये ऊपर खंड (i) का उपखण्ड (क-i)]

	पूर्णांक
(1) निबन्ध	150
(2) सामान्य अंग्रेजी	150
(3) सामान्य ज्ञान	150

टिप्पणी :—ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिया गया है।

(ब) ऐच्छिक विषय

[देखिए ऊपर खण्ड (i) का उपखण्ड (क-ii)]

सेवा श्रेणी II (नियम 1 और 4 देखें) के उम्मीदवार निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों को और अन्य सभी सेवाओं के उम्मीदवार किन्हीं विषयों को चुन सकते हैं :—

(1) शुद्ध गणित	200
(2) अनुप्रयुक्त गणित	200
(3) सांख्यिकी	200
(4) भौतिकी	200
(5) रसायन	200
(6) वनस्पती-विज्ञान	200
(7) प्राणि-विज्ञान	200
(8) भू-विज्ञान	200
(9) भूगोल	200
(10) अंग्रेजी साहित्य	200
(11) हिन्दी	200

(12) निम्नलिखित में से एक :—

अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, लैटिन, पार्सी,
फारसी, रूसी, संस्कृति और स्पेनी 200

(13) भारतीय इतिहास	200
(14) ब्रिटिश इतिहास	200
(15) यूरोपीय इतिहास	200
(16) विश्व इतिहास	200
(17) सामान्य अर्थशास्त्र	200
(18) राजनीति-विज्ञान	200
(19) दर्शन-शास्त्र	200
(20) मनोविज्ञान	200
(21) विधि	200
(22) लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि	200
(23) वाणिज्य विधि	200
(24) उच्च लेखा शास्त्र और लेखा परीक्षा	200
(25) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	200

शर्त यह है कि विशेष ऐच्छिक विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी :—

- किसी भी सेवा के लिए 1, 2 और 3 विषयों में से दो से अधिक विषय नहीं चुने जा सकते।
- भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के उम्मीदवार ऊपर मद 12 के अन्तर्गत दी गई भाषाओं में से एक से अधिक न चुने। केवल भारतीय विदेश सेवा के लिए उम्मीदवारों को इन भाषाओं में से कोई दो को चुनने की अनुमति है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पानी और संस्कृत दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- किसी भी सेवा के लिए इतिहास के विषयों 13, 14, 15 और 16 में से अधिक नहीं चुने जा सकते। लेकिन किसी भी उम्मीदवार को विश्व इतिहास और यूरोपीय इतिहास दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- संख्या 19 और 20 में उल्लिखित विषयों में से एक सेवा के लिए केवल एक ही विषय लिया जा सकता है।
- किसी भी सेवा के लिए विधि के विषयों 21, 22 और 23 में से दो से ज्यादा नहीं चुने जा सकते।
- सेवा श्रेणी-II के लिए 25 विषय न चुना जाय।

सन 1968 और उसके बाद होनेवाली परीक्षा की योजना में से “उच्च लेखा शास्त्र और लेखा-परीक्षा” के विषय को निकाल दिया जाएगा।

टिप्पणी :—ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट के अनुसूची के भाग ‘ख’ में दिया गया है।

(ग) अतिरिक्त विषय [देखिए ऊपर खण्ड-I का उपखण्ड

(क) iii]

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (श्रेणी-I)

की प्रतियोगिता में बैठने वाले उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय भी अवश्य लेने होंगे।

	पूर्णांक
(1) (अ) उच्च गणित अथवा (ब) उच्च अनुप्रयुक्त गणित	200
(2) उच्च भौतिकी	200
(3) उच्च रसायन	200
(4) उच्च वनस्पति-विज्ञान	200
(5) उच्च प्राणि-विज्ञान	200
(6) उच्च भू-विज्ञान	200
(7) उच्च भूगोल	200
(8) अंग्रेजी साहित्य (1798—1935)	200
(9) (अ) भारतीय इतिहास-I (चंद्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक) अथवा (ब) भारतीय इतिहास-II (महान् मुगल सम्राट (1526—1707)	200
(स) भारतीय इतिहास-III (1772 से 1950 तक) अथवा (द) यूरोपीय इतिहास (1871 से 1945)	200
(10) (अ) उच्चतर अर्थशास्त्र अथवा (ब) उच्चतर भारतीय अर्थशास्त्र	200
(11) (अ) हाब्ज से आज तक का राजनीतिक सिद्धांत अथवा (ब) राजनीतिक संगठन और लोग प्रशासन अथवा (ग) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	200
(12) (अ) उच्चतर तत्वमीमांसा जिसमें ज्ञान- मीमांसा भी शामिल है अथवा (ब) उच्चतर मनोविज्ञान जिसमें प्रयोगिक मनोविज्ञान भी शामिल है	200
(13) (अ) भारत की संविधान विधि अथवा (ब) विधि-शास्त्र	200
(14) (अ) अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य- युगीन सभ्यता (570—1650 ईस्वी) अथवा (ब) फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य- युगीन सभ्यता (570 ईस्वी— 1650 ईस्वी)	200
(स) प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शनशास्त्र	200
(15) मानव-विज्ञान	200
(16) सभाज-विज्ञान	200

विशिष्ट अतिरिक्त विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू माने जाएंगे :—

- (1) किसी भी उम्मीदवार को भारतीय इतिहास [9(क)] तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन [14(ग)] दोनों ही विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास [9(ख)] तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध [11(ग)] दोनों विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी :—ऊपर दिए गए विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूचा के भाग 'ग' में दिया गया है।

भाग III

सामान्य

1. सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे। सिवाय भाषाओं के प्रश्नपत्रों के, जिनके उत्तर, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, अंग्रेजी में या संबंधित भाषा में लिखे जा सकते हैं।
2. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. उपरोक्त धारा II की उप-धारा (क), (ख) और (ग) में दिये पत्रों के उत्तर के लिये 3 घंटे का समय दिया जाएगा।
4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक नम्बर (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।
5. भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिये केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दो अतिरिक्त प्रश्न-पत्रों को जांचा और अंकित किया जाएगा। जो लिखित परीक्षा के अन्य सभी विषयों में एक निश्चित अल्पाधिकतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा।
6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरों में से कुछ नम्बर काट लिये जाएंगे।

7. अनावश्यक ज्ञान के लिए नंबर नहीं दिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कमसे-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक-ठीक की गई है।

9. उम्मीदवारों से तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है। प्रश्नों के उत्तर में जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाए।

अनुसूची

भाग—क

(परिशिष्ट II की धारा II की उप-धारा (क) के अनुसार)

1. निबंध—उम्मीदवारों से अंग्रेजी में एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिए कई विषय दिये जाएंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही

अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति को प्रश्रय दिया जाएगा।

2. सामान्य अंग्रेजी—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जाएंगी जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अंतर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखांग दिए जाएंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

3. सामान्य ज्ञान—सामायिक घटनाओं के, और ऐसी बातों जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

भाग—ख

(परिशिष्ट II के भाग II के उप-भाग (ख) के अनुसार)

1. विशुद्ध गणित—इसमें ये विषय शामिल होंगे—बीजगणित, त्रिकोणमिति (ट्रिगनोमैट्री) और सारणिको (डिटरमिनेन्ट्स) सहित समीकरण सिद्धांत (थ्योरी ऑफ इक्वैशन्स)। विशुद्ध समतल ज्यामिति (प्लेन ज्योमेट्री) और द्विविम और त्रिविम वैश्लेषिक ज्यामिति। अवकलन और समाकलन गणित (डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैल्कुलस) और अवकलन गणित समीकरण (डिफरेंशियल इक्वैशन्स)।

2. प्रयुक्त गणित—इसमें ये विषय शामिल होंगे—स्थैतिकी (स्टैटिक्स) जिसके अन्तर्गत आकर्षण तथा विभव सिद्धान्त द्रवस्थैतिकी हैं कणगतिकी (डाइनेमिक्स आफ पार्टिकल्स) और प्रारम्भिक दृढ़ (रिजिड) गतिकी।

3. सांख्यिकी—बारंबारता बंटन, औसत, प्रतिशतक, प्रसार मापने की सरल रीतियाँ, ग्राफीय रीतियाँ, गुणात्मक आंकड़ों का विवेचन जैसे, अनुपातों की तुलना करके साहचर्य का अन्वेषण, अन्तर्वेशन की ग्राफीय और बीज्य रीतियों का अभ्यास।

कीमतों, मजूरियों और आयों, व्यापार परिवहन, उत्पादन और उपभोग, शिक्षा आदि के आंकड़ों के विश्लेषण और विवेचन में प्रयुक्त व्यावहारिक रीतियों, जनसंख्या और जीवन मरण संबंधी आंकड़ों के उपयोग की रीतियों, प्रयोग या प्रेक्षणों के आंकड़ों के उपयोग में लाने में प्रयुक्त प्रकीर्ण रीतियाँ।

आधुनिक गणितीय सांख्यिकी सिद्धान्त के तत्व, बारंबारता वक्र और सामान्यतः समूहों का गणितीय निरूपण, औसतों, प्रतिशतताओं, मानक विचलन, समूहों के औसतों के बीच में पाए गए अंतरों की साधकता आदि को प्रभावित करने वाले प्रतिचयन की यथार्थता, दो चरों के लिए सहसंबंध-सिद्धान्त।

4 भौतिकी

पदार्थ और यांत्रिकी के सामान्य गुण—एवम तथा आयाम । परिभ्रमण गति तथा जड़ता विमर्षिता । म्वाकृष्टि तथा अभ्याकर्षण, ग्रहीय गति । भ्रम्यास्थजल तथा आयाम सहसंबंध, प्रत्यास्थ आपरिवर्तक तथा उनके पारस्परिक संबंध । तल-आनलि, केशालत्व । असंपीड्य द्रवों का प्रवहण । तरल तथा वाति द्रव्यों का आलगरत्व ।

ध्वनि—बलोत्पादित आवेपन तथा प्रतिस्वन । तरंग गति । आवेपनांक परिवर्तन । द्रोणक तथा वायुस्तम्भ-आवेपन । वारंवारता-मापन, ध्वनि का प्रवेग तथा चुम्बकत्व । स्वर-ग्राम । प्रणाल-ध्वनि-विज्ञान । पारस्वानिकी ।

ऊष्मा तथा ऊष्मा-प्रवैगिकी—वातियों का गतिवाद । आउन का गतिवाद । वान डेर वील का स्थिति का समीकरण । तापमान की माप, आपेक्षिक ऊष्मा तथा भंवाही ऊष्मा । जुल-धामसन वातियों का प्रभाव तथा तरलन । ऊष्म प्रवैगिकी के नियम । ऊष्म यंत्र । कालकाय-विकिरण ।

प्रकाश—रेखिकीय काशिकी तथा साधारण काशित संहिति । दूरक्ष तथा अण्वीक्ष । चाक्षुष प्रतिबिम्ब में दोष तथा उनका सुधार प्रकाश का तरंग सिद्धान्त । प्रकाश । प्रवेग की माप । प्रकाश में बाधक, व्याभंग तथा अभिस्पंदन । साधारण मिथोषट्ट-म-रंगावलीक्षा के तत्व । रमन प्रभाव ।

विद्युत तथा चुम्बकत्व

साधारण सामान्यों में क्षेत्र तथा शयम की गणना । गौम का प्रमेय । विद्युन्मान । पदार्थ के विद्युतीय तथा चुम्बकीय गुण और उनकी माप । विद्युत प्रवाह के कारण चुम्बकीय क्षेत्र । चुवाहमान । विद्युत के वेग तथा मात्रा की माप । शक्यमान । रोच, प्ररोचता तथा धारता ; तथा उनका मापन । तामविद्युत । आवर्ती विद्युत्वाह के तत्व । विद्युज्जतिता तथा विद्युद्धहिल । विद्युदंजन । विद्युच्चुम्बिक तरंगों । नमोवाणी कपाद दीप तथा उनके द्वारा वितस्तु तरंगों की साधारण प्रयुक्ति, पारंपण तथा आदान । दूरवीक्षण ।

आधुनिक भौतिकी के तत्व—विद्युधणु, प्राणु तथा वलीवाणु के प्राथमिक तत्व । क्रिया-ऊर्जाणु-रिश्तरांक । परमाणु का ग्रहवत् परमाणु सिद्धान्त । श्र-रश्मिर्चा तथा उनके गुण । तेजोद्विरेता के तत्व तथा आकार एवं अवर्ण रश्मियों के गुण । परमाणुओं की व्याप्ति । सापेक्षता, पंउज तथा ऊर्जा के विशेष सिद्धान्त के तत्व । विखण्डन तथा द्राव । ब्रह्मांड रश्मियां ।

5. रसायन

अकार्बनिक रसायन—परमाणु की संरचना । रेडियोरग्विवचना समस्यानिक । तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण । नाभिकीय विखंडन । रासायनिक बंधों की प्रकृति । वायुमंडल की अक्रिय गैमें । अपेक्षाकृत अधिक सामान्य और उपयोगी तत्वों तथा उनके योगिकों का रसायन । दुर्लभ मृदा तत्व । हाइड्राइड, आवसाइड, आक्सी अम्ल । पर-अम्ल और पर-लवण तथा कार्बोइड । अकार्बनिक संकर । रासायनिक विश्लेषण के मूलभूत सिद्धान्त ।

कार्बनिक रसायन—पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद । ऐलिफैटिक योगिकों के निम्नलिखित वर्गों का रसायन: संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐल्कोहाल, ईथर, ऐन्डिहाइड, कीटोन, मोनो और डाई-कार्बोक्सीलिक अम्ल, ईस्टर, प्रनिस्थापित कार्बो-

यमीनिक अम्ल, पायो, नाइट्रो और नायनो योगिक । ऐमीन, यूरिया और यरीआइड, कार्ब-धात्विक योगिक, मोनोसेकेराइड (संरचना सहित) । कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन (सामान्य परिचय) । सरल एन्जिमीय योगिक । विकृति सिद्धान्त ।

ऐरोमैटिक—बंजीन, नैफथलीन और ऐन्थामीन तथा उनके मुख्य व्युत्पन्न, कोलनार, आमवन, फिनोल, ऐरोमैटिक ऐल्कोहाल, ऐल्डिहाइड, कीटोन । ऐरोमैटिक अम्ल और हाइड्राक्सी अम्ल । त्रिविमविन्यासी बाधा । एरिल-ऐमीन, डाइऐजो, ऐजो और हाइड्रेजों योगिक । विक्नोन । विषम-चक्रीय योगिक । पाईरोल, पिरिडीन, क्विनोलीन, इन्डोल और नील । ऐजो, ट्राइफेनिल मेथेन और फथेलीन रंजक ।

सरल आपाविक पुनर्विन्यास, समावयता, त्रिविम समावयता और चलावयनवता । बहुलकीकरण ।

भौतिक रसायन—अणुगति सिद्धान्त, गैसों के गुणधर्म, अवस्था-समीकरण, (वान-डेर-वाल का, डाइटेरिमाइ) । क्रान्तिक अवस्था, गैसों का द्रवण । रासायनिक संघटन के सापेक्ष द्रवों के भौतिक गुणधर्म । पारंभिक किस्टनिकी ।

ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम और इन नियमों का सरल भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में अनुप्रयोग । रासायनिक साम्य और द्रव्य-अनुपाती क्रिया का नियम । ला-शाले लिए का नियम । प्रावस्था-नियम और उनका एक-घटक तंत्रों तथा लोह-कार्बन तंत्र में अनुप्रयोग ।

अभिक्रिया की दर और कोटि । प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं । शृंखला अभिक्रियाएं । प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं । उत्प्रेरण । अधिशोषण ।

विद्युत-अपघटनी वियोजन । आयनिक साम्य । अम्ल-क्षारक साम्य और सूचक । विद्यु-अपघटनी चालकता और उसके अनुप्रयोग । इलेक्ट्रोड-विभव । मैल का विद्युन्वाहक बल । विद्युन्वाहक बल के माप और उनके अनुप्रयोग ।

6. वनस्पति-विज्ञान

क्रिप्टोगैम (बैकटीरिया और वाइरस सहित) तथा फेनेरोगैम, विशेषकर आरनीय क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम, के विभिन्न समूहों और उपसमूहों अथवा कुलों और उपकुलों के महत्वपूर्ण निरूपकों के रूप, संरचना, प्रकृति, आर्थिक महत्व, जीवनवृत्त और परस्पर संबंध ।

पादम-फिजियोलोजी के मूल सिद्धान्त और प्रक्रम ।

भारत में मिलने वाले शम्य-पौधों के महत्वपूर्ण रोगों का सामान्य ज्ञान और उन रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन ।

परिस्थितिकी और पादन भूगोल, विशेषतः भारतीय वनस्पति-समूह और भारत के वनस्पतिक क्षेत्रों, से संबंधित मूलभूत तथ्य ।

विकास, कोशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी और पादम-प्रजनन का मूल ज्ञान ।

मानव कल्याण के लिए और विशेषकर खाद्यान्नों, दालों, फलों, शर्कराओं, स्टार्चों, तेल-बीजों, मसालों, पेयों, तन्तुओं लकड़ियों, रबर औषधियों और सगंध तेलों जैसे वनस्पति-उत्पादों में पौधों, विशेषतः पुष्पी पौधों, के आर्थिक उपयोग ।

वगस्पति विज्ञान से संबंधित ज्ञान के विकास का सामान्य परिचय ।

7. पाणिचिज्ञान

अकाइंटों और कार्डेंटों, विशेषकर भारतीय अकाइंटों और कार्डेंटों, का वर्गीकरण, जीव-पारिस्थितिकी, आकारिकी, जीवनचक्र और संबंध ।

अध्यावरण, अतःकाल चलन, भरण, रुधिर-परिसंचरण, श्वसन, आस्मो-रेग्युलेशन, तंत्रिका-तंत्र, ग्राहियों और पुनरुत्पादन की क्रियात्मक आकारिकी (रूप, संरचना और कार्य) । कशेरुकी भ्रण विज्ञान के तत्व ।

विकास :—प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं । मेन्डेलीय आनुवांशिकता, म्यूटेशन । प्राणी-कोशिका की संरचना । कोशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धान्त । अनुकूलन और विचरण ।

8. भूविज्ञान

भौतिक, भूविज्ञान और भूआकृति विज्ञान :—पृथ्वी का उद्भव, संरचना, गर्भ तथा आयु । भू-अभिनति और पहाड़ । समस्थिति । महाद्वीपों और महासागरों का उद्भव । महाद्वीपीय विस्थापन । भूकंप-विज्ञान । ज्वालामुखी-विज्ञान । पृष्ठ एजेन्सियों की भूवैज्ञानिक क्रिया ।

संरचना तथा क्षेत्र भू-विज्ञान—आग्नेय अवसादी और कार्यांतरित शैलों की सामान्य संरचनाएं । बलन, भ्रंश, विषम विन्यासों, संधियों और क्षेत्रों का अध्ययन । भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूमापन की विधियों की प्राग्भिक जानकारी ।

क्रिस्टल-विज्ञान और खनिज-विज्ञान—क्रिस्टल रूप और नमिति के तत्व, क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र और वर्ग, क्रिस्टल प्रकृति, यमलन । विविध प्रक्षेप । खनिजों की भौतिक, रासायनिक और प्रकाशित गुणधर्म । अधिक महत्वपूर्ण शैलकर तथा अधिक खनिजों का इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों, क्रिस्टल संरचनात्मक और प्रकाशित लक्षणों, परिवर्तनों, प्राप्ति और व्यावसायिक उपयोगों के संबंध में अध्ययन ।

स्तरित शैल-विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम । भारतीय स्तरित शैल-विज्ञान । भूवैज्ञानिक अभिलेखों के अर्थ-वैज्ञानिक और कालानुक्रम प्रविभाग । जीवाश्म-प्रकृति, जोर परिरक्षण का ढंग; जैव विकास पर प्रभाव । अकशेरुकी तथा पादप जीवाश्म ।

आर्थिक भूविज्ञान—अयस्क उत्पत्ति के सिद्धान्त, वर्गीकरण, भूविज्ञान, प्राप्ति, भारत के प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के क्षेत्र तथा खोत । भारत में खनिज उद्योग । भूभौतिकीय पूर्वक्षण और अयस्क-प्रमाधन के नियम ।

शैलविज्ञान—आग्नेय, अवसादी और कार्यांतरित शैलों का उद्भव, रचना, संरचना और वर्गीकरण । सामान्य भारतीय शैल प्रकारों का अध्ययन ।

9. भूगोल

संसार, विशेषतः भारत, का प्राकृतिक और मानव भूगोल । प्राकृतिक भूगोल के नियम, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन करना शामिल है । चक्र संकल्पनाओं,

समस्थिति, पर्वत विरचन के प्रक्रमों, मौसम घटनाओं, महासागर-जल की वहिस्तलीय और अधस्तलीय गति, आदि के संबंध में आधुनिक विचारों का ज्ञान भी हो ।

मानव भूगोल के नियम, जिसमें संस्कृति, प्रजाति, धर्म आदि के आधार पर जन-वितरण, वातावरण और जीवन-प्रणाली, जनसंख्या उपनति, जनसंख्या की आवाजाही का विस्तृत अध्ययन करना भी शामिल है ।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें भारत के प्राकृतिक, मानव और आर्थिक भूगोल का विस्तृत ज्ञान हो ।

10. अंग्रेजी साहित्य

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी, कि उन्हें चौसर से लेकर महाराणी विक्टोरिया के शासन के अंत तक अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान हो, तथा निम्नलिखित रचनाओं की कृतियों का विशेष ज्ञान हो:—

शेक्सपीयर, मिल्टन, ड्राइडन, जानसन, बर्ड्सवर्थ, कीट्स, डिकन्स, टेनिसन, आर्नेल्ड तथा हार्डी ।

स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा ।

प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनाए जायेंगे, जिससे उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता की जांच की जा सके ।

11. हिन्दी—उम्मीदवारों को चन्द्रबरदाई से प्रेमचन्द तक के हिन्दी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि नीचे पैरा 2 और 3 में बताया गया है । उन्हें हिन्दी भाषा के विकास के, और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उसका क्या संबंध है इस बारे में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए ।

2. मध्यकालीन हिन्दी साहित्य—विशेष रूप से, कबीर, नानक, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा अब्दुरहीम, खानखाना (रहीम), केशवदास, बिहारी और भूषण की कृतियां ।

3. आधुनिक हिन्दी साहित्य—अल्लूजीखान से प्रेमचन्द तक ।

टिप्पण 1—मूल पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित है । उम्मीदवारों को उस काल में अन्य भारतीय भाषाओं में रची गई मुख्य-मुख्य साहित्यिक कृतियों की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए ।

टिप्पण 2—उम्मीदवारों को सामान्य सामाजिक इतिहास का भी ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे वे पिछले सौ वर्षों में हुए हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों के विकास की भूमिका को समझ सकें ।

12. भाषाएं—उम्मीदवारों को प्रमुख परिनिष्ठित साहित्य-कारों का ज्ञान होना अपेक्षित है और उनमें उस भाषा में रचना करने और उससे अनुवाद करने की योग्यता होनी चाहिए ।

टिप्पण—अरबी, फारसी और संस्कृत लेने वाले उम्मीदवारों से कुछ प्रश्नों के उत्तर, यथास्थिति, अरबी, फारसी या संस्कृत में देने की अपेक्षा की जा सकती है । संस्कृत में लिखे जाने के लिए उत्तर देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिए ।

13. भारतीय इतिहास

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से लेकर भारतीय गणतंत्र की स्थापना तक ।

प्रश्न पत्र में राजनीतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगे ।

14. ब्रिटिश इतिहास

अध्ययनाधीन अवधि 1485 से 1945 तक होगी। प्रश्न पत्र में राजनीतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा साम्प्रतिक विकास पर भी प्रश्न होंगे।

15. यूरोप का इतिहास

अध्ययनाधीन अवधि सन् 1789 से 1945 तक होगी।

प्रश्न पत्र में राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर प्रश्न शामिल होंगे।

16. विश्व-इतिहास—1789 से 1945 तक।

उम्मीदवारों से आशा की जायेगी कि उन्हें विश्व के राजनीतिक और आर्थिक विकास विशेषतः यूरोप, अमरीका, सुदूरपूर्व मध्यपूर्व तथा अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में गहन ज्ञान हो। सार्वभौमिक महत्व की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विशेष बल दिया जायेगा।

उम्मीदवारों से यह भी आशा की जायेगी कि उन्हें विज्ञान, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में प्रवर्धित सम्पूर्ण सभ्यता के योगदान में प्रतिबिम्बित सांस्कृतिक विकास का ज्ञान हो।

17. सामान्य अर्थशास्त्र

उम्मीदवारों से आशा की जायेगी कि उन्हें निम्नलिखित विषयों का सामान्य ज्ञान हो:—

(क) आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत, तथा

(ख) आर्थिक मन्तव्यों का इतिहास।

उनमें अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को वर्तमान भारतीय आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए।

18. राजनीति विज्ञान—उम्मीदवार से राजनीतिक सिद्धान्त और उसके इतिहास का ज्ञान अपेक्षित है। राजनीति सिद्धान्त का तात्पर्य केवल विधान-सिद्धान्त से ही नहीं है अपितु सामान्य राज्य सिद्धान्त से भी है। संविधानिक रूपों (प्रतिनिधि सरकार, संघवाद आदि) और केन्द्रीय तथा स्थानीय लोक प्रशासन संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान भी होना चाहिए।

19. दर्शनशास्त्र—उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पूर्व और पश्चिम के नीतिशास्त्र के इतिहास और सिद्धांत की जानकारी होगी। नैतिक स्तर और उनके अनुप्रयोग की समस्याएं, नैतिक निष्पत्ति, नियतवाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति, नैतिक व्यवस्था और प्रगति, व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच संबंध, अपराध और दंड के सिद्धांत तथा नीतिशास्त्र का धर्म से संबंध।

उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पश्चिमी दर्शनशास्त्र के इतिहास की जानकारी रखेंगे। दर्शनशास्त्र की प्रकृति और उसका विज्ञान तथा धर्म से संबंध, पदार्थ एवं आत्मा, स्थान एवं समय, कारणता एवं विकास तथा मूल्य एवं ईश्वर के सिद्धांत और ईश्वर, आत्म एवं मुक्ति, एवं कारणता, विकास एवं प्रतीति के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ सहित भारतीय दर्शन (धर्मनिरपेक्ष और धर्म विरोधी प्रणालियों सहित) का इतिहास।

20. मनोविज्ञान—

मनोविज्ञान : उसका स्वाभाव, क्षेत्र एवं अध्ययन की विधियां, मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधियां।

मानवीय विकास के कारक—आनुवंशिक की एवं परिवेश।

अभिप्रेरणा भावनाएं एवं संवेग, उनका स्वाभाव एवं विकास, संवेगों के सिद्धांत, चरित्र का विकास।

संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संवेदन, प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिगम, स्मरण शक्ति तथा विस्मरण, और मनन।

प्रज्ञा एवं योग्यताएं—संकल्पना और माप, व्यक्तित्व-स्वभाव, निर्धारक तत्व, सिद्धांत, और मूल्यांकन।

दलगत प्रक्रियाएं एवं दलगत प्रभाव, समूहगत व्यवहार, नेतृत्व एवं मनोबल, अभिवृत्ति एवं अपकृति, सामाजिक-परिवर्तन।

अपसामान्यता की संकल्पना, मनःस्थाप और मनोविक्षिप्ति विकारों के मुख्य रूपों की पहिचान एवं कारण, सामाजिक विकृति विज्ञान और बाल-अपराध—कारण और उपाय, चिकित्सा विधियों के मुख्य रूप।

21. विधि—भारत गणतन्त्र और यूनाइटेड किंगडम की संविधानिक विधि। विधिशास्त्र, वृष्कृति (टार्टर्स) भारतीय संविदा विधि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता।

22. लोक अंतराष्ट्रीय विधि

अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय विधि का संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीय विधि और देश विधि।

अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों के रूप में राज्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अधिग्रहण और हानि। राज्य मान्यता। राज्य उत्तराधिकार।

राज्य के अधिकार और कर्तव्य। समानता का सिद्धांत। राज्यों का क्षेत्राधिकार।

संधिया

अंतर्राष्ट्रीय संसर्ग के एजेंट। राजनयिक एजेंटों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय विधि। अन्य देशीय निवासी। राष्ट्रिकता। देशीकरण। राष्ट्रहीनता। प्रत्यर्पण। युद्ध-अपराधी।

अंतर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने का ढंग।

युद्ध। घोषण। प्रभाव।

स्थल-जल और वायु-युद्ध के नियम।

आत्म रक्षा के लिए युद्ध: सामूहिक सुरक्षा। क्षेत्रीय समझौते।

युद्ध को अवैध घोषित करना। युद्धकारी दखल के नियम। युद्ध-कारिता और राज्य प्रतिरोध।

युद्ध के ढंग। युद्ध-कैदी। निरीक्षण और तलाशी का अधिकार।

नौजिनमाल न्यायालय।

नाकाबंदी और विनिषिद्ध।

तटस्थता और तटस्थीकरण। युद्ध में तटस्थ देशों के अधिकार और कर्तव्य। अतटस्थ सेवा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन तटस्थता।

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और राष्ट्रसंघ का प्रतिज्ञापत्र संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग । विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन ।

उम्मीदवादी में आशा की जाती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दिए गए फैसलों सहित मामलों की जानकारी दे सकेंगे ।

23. **वाणिज्य विधि**—निम्नलिखित विषयों से संबंधित विधि के मुख्य सिद्धांत :—

करार

संविदा

उपनिधान

गिरबी

माल बिक्री

एजेंसी

भागिता

क्षतिपूर्ति और गारंटी

परक्राम्य लिखत

कम्पनी-विधि और कम्पनियों का परिसभापन ।

जीवन, अग्नि, समुद्री बीमा ।

सामान्य वाहक और भूमि, जल और वायु मार्ग से माल-परिवहन ।

दिवाला ।

24. **उच्च लेखा विधि और लेख परीक्षा**—

(क) **इन से संबंधित लेखे**—भागिता, संयुक्त स्टाक कम्पनी, समामेलन, अन्तर्लयन तथा पुननिर्माण, नियंत्रक और नियंत्रित कम्पनियाँ, दिवाला, सभापन, दोहरी, लेखा-पद्धति, अवक्रय-खरीद और किस्त पद्धतियाँ, और अव्यापारिक संगठन, शाखा लेखे, बैंक लेखे, संविदा लेखे, बीमा लेखे, स्वामिस्व से लेखे, प्रकाशित लेखों की समीक्षा, कीर्तिस्व, मूल्य ह्रास और आरक्षित निधियों आदि से संबंधित समस्याएँ ।

(ख) **लागत लेखे**—लागत निर्धारण के उद्देश्य और लक्ष्य । विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए लागत परिनिर्धारण की मुख्य पद्धतियाँ और उनकी विशेषताएँ । व्यय के अनुभाजन की पद्धतियाँ । सामग्री, भंडार और स्टाक का हिसाब और नियंत्रण । मजदूरी और अन्य खर्चों का हिसाब । भंडार और स्टाक की कीमत का निर्धारण । लागत खाता-बही, भंडार खाता-बही, खरीद जर्नल, भंडार मांगपत्र, प्राप्त माल बही, बिल कार्ड, समय पक्षक, मजदूरी संक्षेप, लागत-पत्रक और अन्य आवश्यक व्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अधीन लागत और "कारखाने पर" कीमत का अभिनिश्चयन । लागत लेखा से संबंधित व्यावहारिक समस्याएँ ।

(ग) **लेखापरीक्षा के सिद्धांत और प्रक्रिया**—फर्मों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों, और जनोपयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा, लेखा-परीक्षकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, आंतरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षक की नियुक्ति और अर्हताएँ । लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट, अन्वेषण और उसका संचालन । विभाज्य लाभ और लाभांश । लेखा-परीक्षा संबंधी मामलों पर हुए वैध विनिश्चय, लेखा-परीक्षा संबंधी समस्याएँ ।

(घ) **आयकर**—आयकर अधिनियम का लागू होना और छूटें । आयकर प्राश्निकारी । आय के भाँप और उनका निर्धारण । गत वर्ष, निर्धारण वर्ष, मूल्य ह्रास । कर-मुक्त और करदत्त । प्रतिमादन । कुल आय और निर्धारितियों द्वारा देय कर की गणना, व्यक्तियों, फर्मों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों व्यक्तियों की संस्थाओं के लिए कर-निर्धारण । अधिकार-निर्धारण की पद्धति और उनके सिद्धांत । व्यावहारिक समस्याएँ ।

25. **प्रयुक्त यंत्रिका**

निर्माण

छतकैची के सन्निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विचार । इस्पात और इमारती लकड़ी । छतकैचियों के प्रतिफल का विभिन्न पद्धतियों से निर्धारण । अबल भार और वायु दाब क्षेत्र और कार्डीकारी प्रतिबल के घटक ।

छतकैचियों का डिजाइन—विभिन्न प्रकार की छतकैचियाँ और छतछादन, कालरबीम और अधगोल कैचियाँ । स्तम्भों के डिजाइन में यूलर, गोरडन, रैकिन, फिडलर, जान्सन और सरल रेखा के सूत्रों का उपयोग, स्तम्भों का बहुकावकारक, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त स्तम्भों की तुलनात्मक सामर्थ्य को दर्शाने वाले वक्र । कांटों के आधार का चयन । इस्पाती कार्य की परिसज्जा जोड़, एंडवेयरिंगों का डिजाइन, सिरों को जमाने के सत्रारे देने की पद्धतियाँ ।

संरचनाओं के डिजाइन में प्रतिफल के वृत्तों और दीर्घवृत्तों तथा क्लेयप्रान प्रमेय का अनुप्रयोग ।

ठले लोहे और इस्पात के स्तम्भ—इस्पाती स्तम्भों के साथ प्लेज और वेब कनेक्शन : टोपियाँ, आधार स्तम्भों की तिर्थक तान ।

नीव—भुरक्षित दाब, स्तम्भों की नीव । पटिया नीव, बाहुधरन, नीव, झंझरीदार नीव । कूप । स्थूणा ।

पुश्ता दीवार और मिट्टी के दाब—रैकिन सिद्धांत, वेज सिद्धांत, विकर और ब्लाई की ग्राफीय रचनाएँ, संशोधनों सहित । चिनाई में विभिन्न प्रकार की पुश्ता दीवारों का डिजाइन ।

झंजी चिनाई और इस्पाती छिमनियाँ—सिद्धांत और डिजाइन ।

इस्पाती और पक्के जलाशयों का डिजाइन—वायु दाब के विचार से ।

ढांचेदार संरचनाओं के विक्षेप और अतिरिक्तांगी ढांचों में प्रतिबल आदि का अवधारण ।

कैचियों, आवद्ध धरनों और तीन पिनी परबलयिक, अर्ध-दीर्घवृत्ताकार तथा अर्ध-वृत्ताकार डाटों पर समान रूप से वितरित और अनियमित भार के वक्रन धूर्णन और कर्तन के प्रभाव-आरेख ।

गुम्बद डिजाइन के सामान्य सिद्धांत ।

निर्माण डिजाइन के सिद्धांत, निर्माणों पर भार का विचार, इस्पात, कर्म, गड्डे आदि ।

पुन

ऊपरी ढांचे का डिजाइन । चरमारो और वायु दाबों के कारण हुए बंकन धूर्णन का ग्राफीय और वैश्लेषिक पद्धतियों से निर्धारण । पक्के पुलों और पुलियों का डिजाइन ।

प्लेट बेब गर्डर । प्रतिबलों का वि-लेपण ।

वारेन और जालदार गर्डर ।

तीनपिनी डाट, दोपिनी और दृढ़ डाट ।

भूला, बाहुधरन और नक्षिवाकर पुलो के डिजाइन परमाण्विक विचार इस्पाती डाटदार पुल ।

शून्यता पुल

प्रबलित कंक्रीट

वजन, बंध और विकर्ण तनाव, डगका स्वरूप, प्रयोग वा मूल्यांकन और स्थान ।

सरल और दोहरी प्रबलित धरन और अनुकूलित धरन का डिजाइन ।

प्रबलित कंक्रीट स्तम्भों और स्तूनाओं का सिद्धांत और डिजाइन ।

पटिया नीचों का डिजाइन ।

गरल बाहुधरन और पुस्तदार धारक दीवारों का डिजाइन ।

प्रबलित कंक्रीट काटों के लिए तुल्य जड़ता-घूर्ण

प्रत्यास्थ विक्षेप का सिद्धांत और प्रबलित कंक्रीट डाटों में प्रतिबलों के अन्वेषण की रूप-रेखा ।

सामान्य

प्रतिबल विश्लेषण, विकृति प्रत्यास्थता सीमा और चरम सामर्थ्य का विश्लेषण । प्रत्यास्थ स्थिराकों में परस्पर संबंध । किसी संरचना अवयव में कार्यकारी प्रतिबलों के लिए सानहार्ट--वेरोध सूत्र और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का अवधारण । प्रतिबलों की पुनरावृत्ति । अचल मारों के लिए बंकन घूर्णन और कर्तन-बल के आरेख ढांचों में प्रतिबलों का ग्राफीय अवधारण वायुदाब का प्रभाव, काटों की पद्धति । बंकन $(M/I-F/Y-E/R)$ के कारण धरन की अनुप्रस्थ काट में प्रतिबल, मिश्रित, और संयुग्मित प्रतिबल । मिट्टी के दाब का रैकीन सिद्धांत, नीचों की गहराई खसकों की सामर्थ्य । संसारीदार नीच, मिट्टी के दाब का कूलाम सिद्धांत रेवान के कारण परिवर्तन ।

चलमारों के लिए बंकन घूर्णन वर्तन बल के आरेख । समान और समान रूप से बदलते हुए प्रतिबल का विश्लेषण धरनों के बंकन का प्रत्यास्थता-सिद्धांत, धरनों में बंकन और कर्तन प्रतिबल, काट का मापांक और तुल्य क्षेत्र । उत्केंद्र भारता के कारण जोड़ में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल । बांधो और चिमनियों में प्रतिबल । ग्लाक की स्थिरता, कार्य संरचनाएं । वाष्पित खोलों में प्रतिबलों और रिबेटदार जोड़ों का डिजाइन : धाम के संबंध में आयलर का सिद्धांत, रैकिन, गाडर और अन्य सिद्धांत के कारण परिवर्तन । ऐंठन, संयुक्त ऐंठन और बंकन विक्षेप । आवद्ध धरने, अनेकालंब धरने और त्रिपूर्ण प्रमेय । डाटों का प्रत्यास्थता-सिद्धांत, फरकी डाटे ।

भाग ग

परिशिष्ट के भाग II के उप भाग (ग) के अनुसार

1. (क) उच्च शुद्ध गणित--

अनन्त श्रेणी और गुणफल--अभिसरण के लिए परीक्षण । अनन्त श्रेणी (वास्तविक और सम्मिश्र) का निरपेक्ष, सापेक्ष और एक-समान अभिसरण । अनन्त श्रेणी (सम्मिश्र) का अवकलन और

समाकलन । घात श्रेणी के मूल गुण-धर्म । द्वि-श्रेणी । अनन्त गुणन कलों का निरपेक्ष और एक-समान अभिसरण ।

विश्लेषण

वास्तविक-धर के फलन--डिफरेंशियल संभरण । अनुक्रमों के परिबंध और सीमाएं । संतत फलनों का सातत्य और गुण धर्म । रोल प्रमेय, टेलर प्रमेय । दा या अधिक चरों के फलनों का उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ । अवतलतायता और अवकल । अस्पष्ट फलन । जेकोबियन के गुण-धर्म । सीमान्त समाकलन । माध्यमान प्रमेय । समाकल-चिह्न के अर्थात् अवकलन और समाकलन । विषय सहाकल । द्विक, त्रिक और पृष्ठ समाकल । ग्रीन-मेय और स्टोक प्रमेय । फलनों का फूरियर-प्रसार । असातत्य बिन्दुओं पर श्रेणी का संकलन फल । बिन्दु-समुच्चय । माप । माध्य फलन । परिवर्तन फलन का लीबेन्सट्रु समाकल ।

सम्मिश्र चरों के फलन--द्वि-कवाची क्वास्तरण । विश्लेषिक फलन । कोशी प्रमेय और उसका विलोम । चोर्ग समाकल सूत्र । टेलर और लोरा श्रेणी । ल्यूवील प्रमेय । विचित्रताएं । शून्य । अवशेष सिद्धांत । कंटूर-समाकलन और बीर्णाय समीकरणों के मूलों का अनुप्रयोग । अनुकोण निरूपण । विश्लेषिक सातत्य मिटाज-लैफलर-प्रमेय । बीयरहूडस गुणनखंडन-प्रमेय । अधिकतम माड्यूलस नियम । हमदर्द-विवृत्त-प्रमेय ।

उच्चतर ज्यामिति--द्विघाती के समतल परिच्छेद और जनक रेखाएं द्विघाती पृष्ठ और उसका विश्लेषण । अनंतस्य वृत्त । संनामि द्विघाती । द्विघाती कृचिकाओं का प्रारंभिक सिद्धांत ।

समष्टि में वक्र । वक्रता और मरोज । फ्रैने सूत्र । अन्वालोपी । विकासनीय पृष्ठ । वक्र से संबंधित विनासनीय पृष्ठ । रेखज पृष्ठ । पृष्ठों की वक्रता । वक्रता रेखा । संयुग्मी रेखाएं । उपगामी रेखाएं । अल्पान्तरीय ज्यामिति ।

1. (ख) उच्च प्रयुक्त गणित

स्थैतिकी, जिसमें आकर्षण और विभव भी शामिल हैं । द्रव-स्थैतिकी, तरल दाब, वायुमण्डलीय दाब, कैणिकत्व ।

कण और दृढ़ पिण्डों की गतिकी ।

कण गतिकी--सकेंद्र कक्षाएं । प्रतिबंधित गति । प्रतिरोधी माध्यम में गति । तीन विभाजो में गति ।

दृढ़ गतिकी--दो विभाजों में गति । संवेग और गतिक ऊर्जा ।

लैंग्रेजे की गति--समीकरण और अल्पदोलनों में उनका अनुप्रयोग । द्रव गतिकी, जिसमें किसी तरल में से होकर ठोसों की कति की प्रारंभिक सिद्धांत और पृष्ठ तरंगों का अध्ययन भी शामिल है ।

विद्युत और चुम्बकत्व ।

ऊष्मागतिकी, गैसों का अणुगत सिद्धांत, विकिरण ।

2. उच्च भौतिकी

द्रव्य और ध्वनि के सामान्य गुण धर्म--विरूपण्य पिण्डों की यांत्रिकी । कुंडलिनी कमानी कैणिका घटनाएं । श्यानता । ध्वनिक मापन पराश्रयिकी ।

ऊष्मा और ऊष्मागतिकी--थर्मो गति । गैसों का अणुगत सिद्धांत । निम्न दाब पर गैसों में मिलने वाली अभिसरण-घटनाएं ।

ऊष्मागतिक कार्य और उनके अनुप्रयोग । घनाकृतियों और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा । निम्न तापमान साना और उन्हे मापना । विकिरण और ऊर्जा वितरण का प्लैक नियम ।

प्रकाश-विज्ञान—समाक्ष सममित प्रकाशित तंत्रों का सिद्धांत । प्रायोगिक स्पेक्ट्रम-विज्ञान । विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत । प्रकाश प्रकीर्णन । रामन-प्रभाव । विवर्तन । ध्रुवण ।

विद्युत और चुम्बकत्व—गाउस-प्रमेय । विद्युतमार्पी । चुम्बकीय शैथिल्य । स्थायी चुम्बकों का सिद्धांत । वैद्युत राशियों का मापन । प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत । साइक्लोट्रान और उच्च वोल्टता के उत्पादन की अन्य विधियाँ । बेतार तरंगों का प्रेषण और अभिग्रहण । टेलीविजन ।

आधुनिक भौतिकी—आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत । प्रकाश और द्रव्यों की द्वैत प्रकृति । श्रोडिंजर समीकरण और साधारण मामलों में उसके हल । हाइड्रोजन और हीलियम स्पेक्ट्रा जीवन और स्टार्क प्रभाव । बोली नियम और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण । एक्स किरण और एक्स-किरण स्पेक्ट्रम-विज्ञान । कॉम्पटन प्रभाव । धातुओं में चालन । अतिचालकता । तापीय आयनन । परमाणु नाभिकों के गुणधर्म । 'द्रव्यमान स्पेक्ट्रम-विज्ञान । मूलकण और उनके गुणधर्म । नाभिकीय अभिव्रियाएँ । अंतरिक्ष-किरणें । नाभिकीय विखंडन और संलयन ।

3. उच्च रसायन

आकार्बनिक रसायन—परमाणु-संरचना । रेडियोऐक्टिवता, प्राकृतिक एवं कृत्रिम । नाभिकों का विखण्डन तथा संलयन । मयस्थानिक । रेडियोऐक्टिवसूचक । रेडियोऐक्टिव श्रेणियाँ । पराचूरे-नियम तत्व । तत्वों और उनके मुख्य यौगिकों, विशेषतः Be, W, Ti, V, MO, HF, ZV तथा दुर्लभ मृदा तत्वों और उनके मुख्य यौगिकों, का रसायन ।

उपसहसंयोगकता-यौगिक । अंतराअवशी तथा अतत्त्व-योगमितीय यौगिक । मुक्त मूलक । विश्लेषण की पुराने भौतिक-रासायनिक विधियाँ ।

कार्बनिक रसायन—अनुवाद तथा हाइड्रोजनबन्ध विरचन सहित कार्बनिक रसायन के सिद्धांत । महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिव्रियाओं की क्रियाविधि । समनुरूपण सहित विन्यास-रसायन ।

विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के वर्गों, विशेषतः निम्नलिखित वर्गों का रसायन: बहु-शर्कराएँ, टर्पीन, प्राकृतिक रंजक द्रव्य, ऐलकेलाइड, विटामिन, महत्वपूर्ण हार्मोन, मलेरिया रोधक, बक्सीरीन कीट-नाशी, मुख्य पतितैविक, तथा संश्लिष्ट बहुलक ।

भौतिक-रसायन—अणु-गतिक सिद्धान्त, ऊष्मागतिकी की विज्ञान के तीन नियम तथा भौतिक रसायनिक प्रक्रमों में उनका अनु-प्रयोग आणविक संरचना से संबंधित तथा उसका स्पष्टीकरण करने वाले भौतिक-रासायनिक गुणधर्म । क्वान्टम-सिद्धान्त तथा रसायन में इसका अनुप्रयोग ।

रासायनिक तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि तथा बलागतिकी । उत्प्रेरण । अधिशोषण । पृष्ठ-रसायन । कोलायड । विद्युत-रसायन ।

4. उच्च वनस्पति-शास्त्र

उष्मीयवारों की भारतीय वनस्पति समूह पर विशेष ध्यान दते हुए, वर्तमान और विलुप्त दोनों प्रकार के वनस्पति-अणु के

मुख्य समूहों (अर्थात् शेवाल, कवक, त्रयोफाइटा, टेरिडो-फाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजिओस्पर्म) का उच्च ज्ञान होना चाहिए ।

शरीर—पादप ऊतकों का उद्भव, स्वरूप और विकास और पारिस्थितिक तथा कार्याकीय दृष्टि से उनका वितरण ।

पारिस्थितिकी—भारत की वनस्पति के मुख्य प्रकार, उनका वितरण और वनस्पतिक अध्ययन का महत्व ।

कार्यिकी—पादम कार्य के महत्वपूर्ण कार्यिकीय प्रक्रम का उच्च ज्ञान ।

पादम रोग विज्ञान—जीवाणु, कवक, विषाणु, द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण पादम रोगों तथा कार्यिकी रोगों और उनके नियंत्रण की विधियों का उच्च ज्ञान ।

आर्थिक वनस्पति विज्ञान—भारत के आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का अध्ययन और उनका वितरण ।

सामान्य जीव विज्ञान—विभिन्नता, आनुवंशिकता क्रम विकास, कोषिका—विज्ञान तथा आनुवंशिकी के मूलतत्वों और आधुनिक विकास एवं पादम प्रजनन के सिद्धान्तों का ज्ञान ।

5. उच्च प्राणिविज्ञान

आकार्डेटो और कार्डेटो, विशेषकर भारतीय प्राणि समूहों, का वर्गीकरण, जीवपरिस्थिति की, आकारिकी, जीवनवृत्त तथा संबंध ।

अग-तंत्र का क्रियात्मक आकृतिविज्ञान (रूप, संरचना तथा कार्य) । कशेरुकी भूगणविज्ञान की रूपरेखा ।

प्राणियों का वर्गीकरण, व्यक्तिवृत्त, अनुकूलता समाभिरूपता तथा विषाभिरूपता, पशु-परिस्थिति की, प्रवास तथा रंजन ।

विकास: प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं । अनुकूलन, अंतरिक्ष में प्राणियों का वितरण ।

कोशिका, कोशिका-विज्ञान, आनुवंशिकी, लिंग-निर्धारण तथा अंतःसाव-विज्ञान के ज्ञान में नवीन प्रगतियाँ ।

भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों के समिश्र के रूप में वातावरण तथा व्यक्ति, जनसंख्या और समुदाय के रूप में जीवों की आधुनिक संकल्पना ।

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध: प्रोटोजोआ तथा रोग, कीट तथा मानव, परजीवी, विज्ञान, अलवण जल तथा समुद्री जीव विज्ञान, मरीचर-विज्ञान तथा भ्रूत-जीवविज्ञान, ज्ञान तथा मध्यता के लिए महान जीव-वैज्ञानिकों का योगदान ।

6. उच्च भूविज्ञान

सामान्य भूविज्ञान—भूविज्ञान का इतिहास तथा विकास इसकी विभिन्न शाखाएँ तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं में इसका संबंध । पृथ्वी का उद्भव, विकास, संरचना, रचना, गर्भ तथा आयु । भूआकृति-विज्ञान, रेडियोऐक्टिवता तथा भूविज्ञान, भूकंप, विज्ञान, ज्वालामुखी-विज्ञान, भू-अभिनतियों, समस्थितियों में उसका अनुप्रयोग । महाद्वीपीय तथा महासागर द्रोणियों का विकास । पृष्ठ एंजेंसियों और अंतः भूमिका एंजेंसियों की भवजानिक क्रिया । महाद्वीपीय विस्थापन ।

संरचना तथा क्षेत्र भूविज्ञान-पटलविरूपण—शैल विरूपण, पर्वतों का उद्भव, स्थल-आकृति तथा खनन सम्बन्धी संरचनाएं । भारत का विवर्तनिक इतिहास । भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूमापन की विधियां ।

स्तरित शैल-विज्ञान तथा जीवाश्म-विज्ञान—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम तथा सह सम्बन्ध । भारतीय स्तरित शैल विज्ञान का विस्तृत अध्ययन तथा विश्व स्तरित शैल विज्ञान की रूपरेखा । विभिन्न कालों में पृथ्वी, समुद्र, प्राणी समूहों तथा वनस्पति समूहों का विभाजन । जीव-विश्वास के सिद्धांत । जीवाश्म—उनका महत्व । प्रतिरूपी इन्डैक्स जीवाश्म तथा सह सम्बन्ध, भारत के विशेष संदर्भ में अकशेरुकी का विस्तृत अध्ययन । और भूवैज्ञानिक इतिहास ।

क्रिस्टल-विज्ञान तथा खनिज-विज्ञान—क्रिस्टल-आकारिकी, क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र तथा वर्ग, प्रकृति, यमलन । क्रिस्टलों का कोपामर्प । तथा ऐक्स-किरण अध्ययन । परमाणु-संरचना । शैल कर तथा आर्थिक खनिजों का, भारत में उनके अस्तित्व के विशेष संदर्भ में विस्तृत अध्ययन ।

शैलविज्ञान—आग्नेय, अघरादी तथा कायांतरित शैलों का उद्भव और विकास, संरचना, खनिज घटक, गठन तथा वर्गीकरण । कायांतरण सहित शैलजनन । शैल रसायन । उत्का पिण्डों का अध्ययन । मुख्य भारतीय शैल प्रकारें ।

आर्थिक भूविज्ञान—अयस्क-उत्पत्ति, आर्थिक खनिजों का वर्गीकरण तथा अयस्क-स्थान निर्धारण । भारत के विशेष संदर्भ । में आर्थिक खनिज निक्षेपों का भूविज्ञान । खनिज उद्योगों का स्थान-निर्धारण । गुणधर्मों का मूल्यांकन, खनिज-अर्थशास्त्र, खनिजों का संरक्षण तथा उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति स्ट्रैटेजिक खनिज भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय तथा भूरासायनिक पूर्वोक्षण तकनीकों तथा उनके अनुप्रयोग । खनन, प्रतिचयन, अमस्क-प्रसाधन तथा अयस्क सज्जीकरण की मुख्य विधियां । भूमि तथा भौम जल । सामान्य इंजीनियरी समस्याओं में भूविज्ञान का अनुप्रयोग ।

7. उच्च भूगोल

पर्वों के दो भाग होंगे :—पहले भाग के अंतर्गत भारत के विशेष संदर्भ में भौतिक, मानव तथा आर्थिक भूगोल का प्रगत अध्ययन होगा ।

दूसरे भाग में निम्नलिखित विशेष विषयों का प्रगत अध्ययन शामिल होगा और उम्मीदवार से आशा की जाती है कि उसे कम-से-कम दो विषयों का ज्ञान होगा :—

भूआकृति विज्ञान । जलवायु विज्ञान (मौसम के पूर्वानुमान तथा विश्लेषण की नई विधियों सहित) । मानचित्रबला (समकोणीय गोलीय त्रिकोण के हल, थियोडोलाइट के उपयोग, त्रिकोण विमध्य जाल जैसे प्रगत प्रक्षेप, आदि सहित) । ऐतिहासिक भूगोल । राजनैतिक भूगोल । भौगोलिक विचार तथा खोजों का इतिहास ।

8. अंग्रेजी साहित्य

प्रश्न पत्र अंग्रेजी साहित्य (1798—1835) के अध्ययन पर आधारित होगा, जिसमें निम्नलिखित रचनाकारों का विशेषाध्ययन अपेक्षित होगा :—

रड्सवर्थ, कोलरिज, शैली, कीट्स, लेम्ब, जैन औरस्टन,

कारनाइल, पोस्वान, रीकर, राबर्ट ब्राऊनिंग, जर्ज हॉलियट, जॉन एम. होपकिंस, शां, रबर्टयू. बी. सीट्स, गार्सवर्दी, जे. एम. थिच ई. एम. फोर्म्टर तथा टी. एस. हॉलियट ।

स्वयं पुस्तकों पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा ।

प्रश्न पत्र इस प्रकार के बनाये जायेंगे जिनसे इस अवधि की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का ज्ञान ही नहीं, अपितु उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन की जांच भी की जा सके । इस में उस अवधि की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित प्रश्न भी शामिल किये जा सकते हैं ।

9. (क) भारतीय इतिहास—(चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक)

मौर्यवंश—साम्राज्य का अभ्युदय तथा दृढ़ीकरण प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था । साम्राज्य का पतन ।

यगध का पतन—

शुंग तथा कण्व वंश—चोल, चेर तथा पाण्ड्य ।

पश्चिम से सम्पर्क उत्तर भारत-भारतयूनान ।

दक्षिण-भारत-रोमन व्यापार ।

मध्य एशिया तथा भारत ।

क्षत्र वंश । कुशान वंश ।

शतवाहन वंश ।

एशियाई देशों से भारत का सम्पर्क—बौद्ध मत का प्रसार ।

गुप्त साम्राज्य

भारतीय गारतीय संस्कृति का निर्माण । भारत के और समुद्रपारिय सम्पर्क । गुप्त वंश का पतन । हूण जाति ।

उत्तर भारत में बदलती हुई अर्थ व्यवस्थाएं तथा राजनीति पर उनका प्रभाव ।

वाकटक तथा चालुक्य वंशों का अभ्युदय ।

पल्लवों का अभ्युदय । हर्षवर्धन ।

हर्षवर्धन

9(ख) भारतीय इतिहास (मुगल साम्राज्य 1526—1707)

राजनीति इतिहास—

भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसका दृढ़ीकरण तथा विस्तार । सूर राज्यान्तराल । मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष । अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ । मुगलों के फारस तथा मध्य एशिया से सम्बन्ध । प्रशासनिक पद्धति का विकास । मुगल दरबार में यूरोप के लोग, प्रारम्भिक पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों बस्तियां । पतन का आरम्भ । औरंगजेब, उसके युद्ध तथा नीतियां ।

सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन—

सांस्कृतिक जीवन तथा कला का विकास, वास्तुकला तथा साहित्य ।

धार्मिक आन्दोलन : भक्ति आन्दोलन, सूफीमत, दीने-इलाही । मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति ।

आर्थिक जीवन, कृषि, जीवन। भूधारण पद्धतियाँ। उद्योग। वाणिज्य तथा व्यवसाय। आयन तथा निर्यात। परिवहन व्यवस्था। भारत का भविष्य।

सामाजिक जीवन : दरबारी जीवन। नागरिक जीवन, ग्रामीण जीवन। वैश्यधूषा। रीति-रिवाज, खाद्य तथा पेय, मनोरंजन तथा मेले, त्योहार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति।

(ग) भारतीय इतिहास III (1772 से 1950)

बंगाल तथा दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का दृढ़ीकरण। भारत में ब्रिटिश सत्ता का विकास। ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश राज्य। सिविल सर्विस, न्याय पद्धति, पुलिस तथा सेना का विकास। लैंड भूमिकर पद्धति तथा भूधारण पद्धति का विकास। ब्रिटिश व्यावसायिक नीति। भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। 1९५७ का विद्रोह। भारतीय राज्यों के साथ सम्बन्ध। विदेश नीति, तथा ब्रह्मा व अफगानिस्तान के साथ सम्बन्ध। आधुनिक उद्योग तथा संचार साधनों का विकास। आधुनिक शिक्षा का विकास, प्रेम का विकास।

भारतीय पुनः आगुति :—राजा राम मोहन राय, ब्रह्मसमाज और विद्याभारत, आर्य समाज, फ्रियोमोफिस्ट, रामकृष्ण तथा विवेकानन्द, सैयद अहमद खां सामाजिक सुधार आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास।

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का अभ्युदय : इण्डियन नेशनल कांग्रेस (1885 से 1905) दादाभाई नारोजी, राणाडे, गोखले, उग्र राष्ट्रवाद का विकास, विभाजन विरोधी आन्दोलन, स्वदेशी तथा बायकाट आन्दोलन, गान्धे व भगवन्दास घोष, होमरूल लीग तथा लखनऊ समझौता।

संवैधानिक विकास :—1861 तथा 1892 के अधिनियम, मिन्टो पार्ले सुधार, मौंट फोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम।

सहायता शाही का राजनीति में प्रवेश तथा स्वतन्त्रता संग्राम। गन्ता-हस्तान्तरण : क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन, स्वतन्त्रता अधिनियम तथा विभाजन। 1950 का संविधान। स्वतन्त्र भारत : विदेश नीति, तटस्थता, धर्मनिरपेक्षता तथा योजना।

9. (घ) ब्रिटिश संविधान का इतिहास (1601 से 1950 तक)

ताज बनाम संसद—

जम्स I. तथा संसद के बीच सम्बन्ध। अधिकारवाचिका। चार्ल्स तथा परमाधिकार बनाम सामान्य कानून। (गृह युद्ध)

संविधान प्रवर्तक—

लाग में नु की सरकार। लिट्स संसद। प्रोटेक्टोरेट। पुनः स्थापन। ग्लोरियस रिवोल्यूशन (ब्लिग आफ एड्जम्)।

ताज कार्यवाहिका तथा संगद।

राजा तथा उसके मंत्री। ताज का प्रभावाधिकार। मन्त्रिमण्डल तथा संसद : 1936 का राजतन्त्रीय आपातकाल।

संसद का सुधार

सुधार अधिनियम तथा हाऊस आफ कामन्स। हाउस आफ कामन्स तथा हाउस आफ लार्ड्स। हाऊस आफ लार्ड्स का सुधार।

कामनवेल्थ (राष्ट्रमण्डल)

कामनवेल्थ का उद्गम तथा विकास। वेस्टमिन्स्टर का परि-नियम। कामनवेल्थ सहयोग का कार्यान्वयन। कामनवेल्थ में ताज की स्थिति।

9. (ङ) यूरोपीय इतिहास (1871-1945)

यूरोप का औद्योगिक विकास—राष्ट्रवाद तथा लोक तांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों का विकास।

जर्मन साम्राज्य, 'तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य', हैब्सबर्ग राजवंश राजतंत्री रूस। संधियों और मैत्रियों की नीति।

पूर्व संबंधी (ईस्टर्न) प्रश्न।

साम्राज्यवाद का उत्थान तथा निवृत्त पूर्व, मध्यपूर्व अफ्रीका और सुदूर पूर्व में यूरोप के साम्राज्यवादी हित।

प्रथम विश्व युद्ध का उद्गम तथा परिणाम।

रूस की क्रान्ति तथा उसके परिणाम।

वर्साई समझौता, राष्ट्र संघ (लीग आफ नेशंस), विश्व व्यापी निरस्त्रीकरण के प्रयत्न, सुरक्षा की खोज, फासिज्म तथा नाज़िज्म का उदय और उसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम।

द्वितीय विश्व युद्ध।

10. (क) उच्च अर्थशास्त्र

आर्थिक विश्लेषण के कृत्य।

मूल्य का सिद्धान्त। खपत और भांगका सिद्धान्त। उत्पादन का संगठन। एकाधिकार का सिद्धान्त। एकाधिकार का नियन्त्रण।

वितरण का सिद्धान्त। किराया। पूंजी का सिद्धान्त। धन तथा व्याज का सिद्धान्त, बचत तथा विनियोजन। बैंकिंग तथा उधार सम्बन्धी नियम। मजदूरी तथा नियोजन सम्बन्धी सिद्धान्त। सामूहिक सौदाबाजी तथा औद्योगिक शान्ति।

राष्ट्रीय आय। आर्थिक प्रगति तथा वितरणात्मक न्याय।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त। विदेशमुद्रा। अदायगियों का शेष।

व्यापारिक चक्र तथा उनका नियन्त्रण। सरकारका आर्थिक योग। आर्थिक कल्याण। लोक (हित) के माधन मूल्यांकन तथा नियमन।

10. (ख) उच्च भारतीय अर्थशास्त्र—

युद्धकालीन तथा युद्धोत्तर अवधि में आर्थिक विकास। प्राकृतिक साधन सामाजिक संस्थाएं। कृषि उत्पादन तथा वित्त। अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारण तथा वितरण। भूमि सुधार। किसी विकासमयी अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों का स्थान। आधुनिक संगठित उद्योग का विकास। लोक कम्पनियों का नियमन। औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रम (दल) की समस्याएं। मिश्रित अर्थ व्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र तथा दक्षता। भारतीय पूंजी तथा प्रत्यय पद्धति। रिजर्व बैंक का योगदान। जनसंख्या, समस्याएं तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीति। बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी। भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धारण। विदेशी व्यापार का नियमन। अदायगियों का शेष। भारतीय

करारोपण पद्धति। संवीय वित्त। आर्थिक विकास के मिये योजना। कमबद्ध योजनाओं का आकार तथा ढांचा। स्त्रोत तथा कार्यन्वयन की समस्याएँ।

11. (क) हाथ से लेकर आज तक के राजनीतिक सिद्धान्त ठेका (गान्धेय) तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त-ह्यूम्स, लॉक, रूसो। प्रभुता के मन्तव्य का विकास। इतिहासकार-वीको, मोन्टेस्क तथा बर्क। उपयोगितावादी। विकासवादी। आदर्शवादी-कान्ट, हेगल, ग्रोस, ब्राउले तथा वोसक्वे। रूढ़ीवाद तथा उदारवाद। मार्क्सवाद तथा समाजवाद व साम्यवाद की धाराएँ। बहुलवाद। फासिज्म। मनोविज्ञान का प्रभाव। पूर्वी देशों में बीसवीं शताब्दी की विचारधाराएँ।

11. (ख) राजनीतिक संगठन तथा लोक प्रशासन—
राजनीतिक संस्थाएँ—आधुनिक राष्ट्रों का विकास ससदीय तथा राष्ट्रपति सहित सरकारें। एक सत्ता तथा सघीय सरकारें। विधानांग कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। प्रतिनिधित्व के प्रकार। साम्यवादी तथा एक सत्ताधारी सरकारें।

लोक प्रशासन—आधुनिक सरकार में लोक प्रशासन। नीति-निर्धारण तथा उच्चतर नियन्त्रण-न्यायपालिका तथा कार्यपालिका। संगठन, प्रबंध, प्रकार तथा माध्यम। नियामक आयोग तथा लोक निगम। कर्मचारी वर्ग प्रशासन-सिविलसेवा तथा इसकी समस्याएँ। बजट तथा वित्तीय प्रशासन। प्रशासनिक अधिकार। न्यायानुयों द्वारा नियन्त्रण। लोक सेवाएँ तथा जनता।

11. (ग) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भाग I

राष्ट्रीय शक्ति का आधार और सीमाएँ।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति, सिद्धान्त तथा नैतिकता का स्थान।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्थान।

विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित का योग।

शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का स्वरूप और उनके कार्य।

संयुक्त राष्ट्र संघ, उद्देश्य, संरचना और कार्य प्रणाली।

भाग II

प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारण तथा शांति समझौते का स्वरूप।

राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) तथा दोनों युद्धों के बीच के वर्षों में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए किए गए प्रयत्न।

द्वितीय विश्व युद्ध के मूल कारण।

परमाणु युग तथा परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका प्रभाव।

“शीत युद्ध” तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव।

नए राष्ट्रों का अभ्युदय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिमान में परिवर्तन।

संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत तथा निम्नलिखित में से किसी एक देश की विदेश नीति —

ग्रेट ब्रिटेन, जापान, अफ्रीका तथा फ्रांस।

12. (क) उच्च अमूर्त विषय विज्ञान (शास्त्रशास्त्र सहित)

उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे कान्ट से लेकर आज तक के प्रमुख दार्शनिकों (नामन कान्ट, हीगल, ब्राउले, रायस, कोचे, मूर, रसल, जेम्स, शिल्सर, ड्यूई, बर्गरन, एल्वेराण्डर ह्वार्टहेड, विटगनस्टाइन, अयर, हार्पडगमर तथा मार्सेल)।

निम्नलिखित विषयों में से किसी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं

ज्ञान के स्त्रोत, तत्त्व विज्ञान-भेद रूप। उसकी सीमाएँ, मापदण्ड तथा समाजविज्ञान।

सत्य, मिथ्या, ल

वास्तविकता के सिद्धान्त। दार्शनिकता। जीवन और श्री अस्तित्व। एकत्ववाद, द्वैतवाद, बहुलवाद, प्रकृतिवाद, अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद, ऐतवाद और रक्ष्यवाद। हगनोतर आदर्शवाद। नवीन यथार्थवाद। मौलिक अनुभूतिवाद। उपयोगितावाद।

उपकरणवाद। मानववाद-प्रकृतिवादी और धार्मिक।

नाकिक प्रत्यक्षवाद। अस्तित्ववाद-अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी। आगमन की समस्याएँ, प्राकृतिक नियम, सापेक्षवाद, ईश्वर और अनिश्चयवाद के सम्बन्ध में दर्शनों के क्षेत्र में नवीन विचारधाराएँ।

12. (ख) उच्च मनोविज्ञान-प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सहित

मनोविज्ञान का विषय-वस्तु, क्षेत्र और पद्धतियाँ, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध।

आनुवंशिकता और परिवेश संबंधी दिवादान-नाम के विकास पर इन दोनों के सापेक्षिक प्रभाव संबंधी प्रयोगात्मक अध्ययन।

अभिव्यक्ति। एवं संबंध की समस्याएँ। कुठ और विग्रह, विग्रहों के प्रकार। अन्तरजातत्व—अभिव्यक्ति गतिविधियों में संबंधित अध्ययन, मनोधारागुक्रिया (P. G. R.), अवस्था परिचयन।

संवेदन और अनुभूति—मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ, देश-प्रत्यक्ष ज्ञान, शाश्वत संगठन के कार्य, सत्यात्मक, व्यक्तित्व तथा सामाजिक कारकों का योग, अंतर्व्यक्तिक अनुभूति।

अधिगम, स्मृति, विमर्श और चिन्तन के अध्ययन का प्रायोगिक पद्धतियाँ—अधिगम और सिद्धान्त—अर्थ का स्वभाव।

व्यक्तित्व मनोविज्ञान—निर्धारक तत्व, गुण, क्रिस्म, परिभाषा, और सिद्धान्त, व्यक्तित्व का मूल्यांकन—व्यक्तित्व के आचरण-मूलक माप-क्रम निर्धारण-मान, साम-निर्देशन, तकनीक, प्रभावलिता तथा तालिकाएँ, अभिवृत्ति-मान, प्रक्षेपीय पराक्षण।

व्यक्तिगत भेद—प्रज्ञा और अभिवृत्तता का स्वभाव एवं माप। परीक्षण विन्यास—इकाई विश्लेषण। परीक्षण मान और मानक-मापों की विश्वमनोयता और वैधता-कारक विश्लेषण-सिद्धान्त।

मनोविज्ञान के मत और संहिताएँ—मनोविज्ञान के परंपरावादी मत और मुख्य समकालीन संहिताएँ, फ्रायडवादी, नव-फ्रायडवादी, नव-आचरणवादी, पूर्णकार (गेस्टाट) और प्रयोग-क्षेत्रीय सिद्धान्त।

13. (क) भारत की संविधान विधि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—भारत के संविधान का विकास जिससे 1861 के इंडियन काउंसिल ऐक्ट से 1950 तक के भारतीय संविधान में प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी सरकार के विकास पर विशेष रूप से प्रश्न होंगे। सामान्य तत्व : वर्याणवारी राज्य का आदर्श, भारतीय संविधान का प्राक्कथन तथा राज्य की नीति के मार्ग दर्शन सिद्धांत, केन्द्रवर्ती तथा संघात्मक शासन पद्धतियों की मान्यताएं, संसिम्पण्डलीय पद्धति, विधिनियम की द्वायवत पद्धति, न्यायिक पुनरेक्षण, संवैधानिक प्रथाएं, भारतीय संविधान के प्रमुख तत्वों का संयुक्तागल राज्य, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों से तुलना। अधिकारों का विभाजन अधिकारों के पार्थक्य का सिद्धांत।

विधानांग—

विधायी अधिकार, विधानांग के विशेषाधिकार, विधायी अधिकारों का प्रत्यायोजन।

13. (ख) विधिशास्त्र

विधिशास्त्र—परिभाषा तथा क्षेत्र, विधिशास्त्र के विभिन्न मतवाद। विधिनियम, विधिनियम तथा आदर्श; विधि नियमों का विकास, प्राकृतिक नियम, राज्य के विधिनियम; विधिनियम की अनुलंघनीयता का सिद्धान्त; विधिनियम की सामाजिकतावादी सिद्धांत; विधिनियम के प्रकार; सिविल विधिनियम; दण्ड विधिनियम; स्थायी तथा प्रक्रिया संबंधी विधिनियम व्यवस्थित विधिनियम तथा सामाजिक विधिनियम; अंतर्राष्ट्रीय विधिनियम; विधिनियम तथा न्याय; विधिनियम तथा समानता; विधिनियम के अनुसार न्याय; न्याय-प्रशासन प्रभुता के बारे में मान्यताएं तथा सिद्धांत।

प्रथा, न्यायिक पूर्व निर्णय, विधान संहिताकरण विधि के तत्त्व—न्यायिक मान्यताओं का विश्लेषण तथा वर्गीकरण; व्यवस्थित; अधिकार, कर्तव्य, स्वतन्त्रता; शक्ति, उन्मुखित; अधोगत्या, स्तर, कब्जा, स्वामित्व; पट्टा, न्यास, सुविधाधिकार, सुरक्षा, हानि, उत्तरदायित्व, दायित्व; अधिनियम, नीयत, उद्देश्य, लापरवाही; स्वत्व, चिरप्रयोगाधिकार, उत्तराधिकार तथा वसीयतें। विधिनियम संबंधी मान्यताओं का विकास : संविदा का विकास, जिष्णु, अपराध, सम्पत्ति तथा वसीयतें, न्यायिक विचारधारा में वर्तमान विचारधारा।

14. (क) अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई०-1650 ई०)

इस प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जायेगी।

(ख) फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई०-1650 ई०)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जायेगी।

(ग) प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन शास्त्र

2000 ई० प्र० से 1200 ई० तक भारतीय सभ्यता, दर्शन और विचारधारा का इतिहास।

टिप्पण—इस प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की परीक्षा की जायेगी। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनमें पुरातत्त्व संबंधी खोजों की जानकारी अपेक्षित हो।

15. मानव विज्ञान—

(क) **भौतिक मानव विज्ञान**— इसकी परिभाषा और क्षेत्र। भौतिक मानव-विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध। मानवजाति का क्रम विकास, वानरगणों में मानव का स्थान—उसका पैरेन्थीकस से लगाकर आस्ट्रा लाइथैकस तक प्रोह्यूमन तथा प्रोटोह्यूमन जातियों से संबंध-पैलेओआन्थ्रोपिक मानव-पिथैसेन्थ्रोपस। सिनेन्थ्रोपस तथा नीएंडर्थल। नीन्थ्रोपिक मानव—क्रोमैगनन, ग्रिमालडी तथा चान्सेलेउ-होमोसेपियन्स।

मानव में जातिगत अन्तर तथा जातीय वर्गीकरण-शरीर रचना सम्बन्धी, रक्त वर्गीय तथा वायुवंशिक। जातियों के निर्माण में आनुवंशिकता तथा परिवेश का प्रभाव। मानव की उत्पत्ति के सिद्धान्त—मैडेलियन नियम जैसे कि वे मानव पर लागू होते हैं।

मानव का शरीर विज्ञान—आहार-पोषण, अन्तः प्रजनन तथा वर्ण-संकरिकरण के प्रभाव पाषाण काल से सिंधुघाटी सभ्यता तथा मध्य और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियों तक भारत में मानव के प्रसार का इतिहास। जातीय वर्ग और भारत में उनका वितरण।

(ख) **सामाजिक (सांस्कृतिक) मानव-विज्ञान**—क्षेत्र तथा कार्य। समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान तथा पुरातत्त्वशास्त्र से संबंध। सांस्कृतिक मानव-विज्ञान के विभिन्न मत—विकासवादी, ऐतिहासिक, कार्यात्मक और सांस्कृतिक। मानव समाज का गठन तथा विकास।

आर्थिक संगठन—प्रारंभिक शिकार तथा खाद्य-संग्रह की अवस्था, पशु-पालन, कृषि, परवर्ती कृषि, सघन कृषि, औजारों का प्रयोग।

राजनीतिक संगठन—दल, जनजातियां, तथा दुहरा संगठन, जनजाति-परिषदें, मुखियों के कार्य।

सामाजिक संगठन—विवाह तथा पारिवारिक रचना के प्रकार, मातृसत्ताक, पितृसत्ताक, बहुपत्नीत्व, बहुपतित्व, बहिजातीय विवाह तथा समोन्नविवाह, स्त्रियों की स्थिति, दायित्व तथा तलाक।

आर्य धर्म—टोटमवाद, निषेध, गर्भाधान के अधिकार, नर-हत्या तथा नर-बलि।

कला, संगीत, लोक नृत्य तथा खेलकूद। दलगत संबंध, विवाद निर्णय, न्याय तथा दण्ड-संबंधी मान्यताएं।

बौद्धिक विकास का स्तर, विशेष दक्षियां और योग्यताएं, आवि मानव के आचरण और प्रान्तपालों के केन्द्रीयतावाद की पृष्ठभूमि में भावार्थक आवश्यकताएं।

व्यक्तित्व का निर्माण तथा व्यक्तित्व और आदिम समाज में उसके योगदान का विकास।

आदिम जातियों का संस्कार तथा सम्पर्क का उन पर प्रभाव। वस्तियों का उजड़ना और उसके कारण। आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुण्ठन। अमरीका, अफ्रीका तथा ओशियाना में आदिम जनजातियों का ह्रास। भारतीय जनजातियों में जनसंख्या का ह्रास तथा उसकी रोकने के उपाय।

(ग) जातिव्यवस्था के आधार पर भारतीय जनजातियों में से किसी एक का गहन अध्ययन

1. भारत की उत्तर-पूर्वी सीमान्त वासी आदिम जनजातियाँ।
2. नागापहाड़ियों—तैवान सांग क्षेत्र की जनजातियाँ।
3. आसाम की स्वायत्तता प्राप्त जनजातियाँ—खसिया, गारो, मिकिर तथा जुशाई।
4. छोटा नागपुर तथा मध्य भारत की आण्डिक जनजातियाँ।
5. दक्षिण भारत की, नीलगिरि पर्वत निवासी जनजातियों सहित, जनजातियाँ।
6. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को भाग (ग) तथा (क) अथवा (ख) में से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

16. समाज विज्ञान

समाज विज्ञान का क्षेत्र। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ उसका संबंध। पद्धतियाँ।

समाज की उत्पत्ति, आदि जीवन, सामाजिक क्रम विकास की अवस्थाएँ, सामाजिक दाय, इसके तंत्र। पर्यावरण के क्रम। व्यवहार के प्रकार।

सामाजिक गठन, समूह, संस्थाएँ, साहचर्य, परिवार, विवाह, हैसियत, वर्ग समुदाय, युथ और भीड़, व्यवसाय, सम्पत्ति, व्यक्तित्व, संस्कृति और सभ्यता, पुराण, कथाएँ और उपाख्यान, भाषा और बोली, मूल वंशों के संविदा और उनके प्रकार, राज्य, नैतिक आचार और उनका क्रम-विकास। स्वभाव रूढ़ियाँ, लोकाचार और लोक-रीतियाँ।

सामाजिक परिवर्तन। प्राविधिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय शक्तियाँ।

मनोवैज्ञानिक कारक, अन्योन्यक्रिया, अनुकरण, विसरण, सांस्कृतिक कारक। विचारों का प्रभाव। नेतृत्व, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक वरण के नियम।

सामाजिक प्रक्रम। प्रतियोगिता। विभेदीकरण, सामूहिकीकरण। विरोध के प्रकार। धन का विभाजन, सामाजिक परिस्थिति-विज्ञान।

सामाजिक कुसमंजन, सामूहिक संस्कृति, नगर और गाव, अपराध, सामाजिक, बुराईयाँ।

सामाजिक नियंत्रण, अधिकरण। राज्य और विधि। कल्याणकारी राज्य। धर्म: कला। शिक्षा। लोकमत और प्रचार।

सामाजिक आयोजन, इसके सिद्धांत, भारतीय परिस्थितियाँ, सामाजिक कार्य और कल्याण।

सामाजिक सुरक्षा, प्रयोजन और प्रगति।

सामाजिक विचारधारा का इतिहास। भौतिकवादी और समाजशास्त्री सम्प्रदाय, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भारतीय योगदान।

प्रारंभिक सामाजिक माध्यिकी। सामाजिक सर्वेक्षणों की पद्धतियाँ।

खण्ड (घ)

[परिशिष्ट 2 का भाग 1 की उप-धारा (ख) के अनुसार]

व्यक्तित्व परीक्षा—एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा। इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा। उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे। यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र दिया है, उनके/उनके लिये वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभि-प्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण-शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, सन्तुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है।

2 इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है।

3 व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि ले जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका सक्षिप्त व्यौरा :—

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा—(क) नियुक्तियाँ परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) वेतन-मान—

जूनियर—रु० 400-400-500-40-700-कु० रो०-30-1000 (18 वर्ष)

सीनियर—

(i) समय-मान—रु० 900 (छठे या पहले)—50-1000-60-1600-50-1800 (22 वर्ष)

(ii) सलेक्शन ग्रेड—1800-100-2000।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2150/- से रु० 3500/- तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(छ) **भविष्य निधि**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) **छुट्टी**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(झ) **डाक्टररी परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टररी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टररी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

2. **भारतीय विदेश सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप कोसुल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया जाएगा। जिनकी भाषाएं उनके

लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उनकी नियुक्ति पर पक्का किया जाएगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (मस्टेंटिफ पोस्ट) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) वेतन-मान—

जूनियर—रु० 400-400-500-40-700-कु० रो०-30-1000।

सीनियर—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)—50-1000-60-1600-50-1800।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800/- से रु० 3500/- तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ) परख अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

तीसरे वर्ष—रु० 500 प्रति मास।

नोट—1. परखाधीन अधिकारी को परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान में वेतन वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

नोट—2. परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जबकि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हों) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा। विभागीय परीक्षाएं पास करके अधिम वेतन-वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैमियत (Status) के अनुसार विदेश-भरते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-वाफरों और जीवन-निर्वाह के बड़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इन्टरटेनमेन्ट)

संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सके। इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :—

- (i) हैसियत के अनुसार गुप्त सुसज्जित मकान।
- (ii) सहायता प्राप्त डाक्टरों की परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendance Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरों की परिचर्या की सुविधाएं।
- (iii) भारत आने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों (emergencies) में ही दिया जाएगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु या मूल बीमारी अथवा पुत्री का विवाह।
- (iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।
- (v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, शिक्षा-भत्ता।
- (vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पकका होने पर सज्जा-भत्ता (Out fit allowance) अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जाभत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जाभत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए।
- (vii) विदेश में कम से कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए, छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमियों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। विदेश में की गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी।

(झ) भविष्य निधि—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) सेवा-निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारभूत (Liberalised) पेंशन नियमावली, 1950 द्वारा शासित होते हैं।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

3. भारतीय पुलिस सेवा—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय

के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षण पास करनी होंगी।

(ख) }
(ग) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख)
(घ) } (ग) और (घ) में दिया गया है ?

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) वेतनमान :—

जूनियर—र० 400-400-450-30-600-35-670-

कु० र०-35-950 (18 वर्ष)

मीनियर—र० 740 (छठे वर्ष या पहले)-40-1100-50/2-1250-50-1300 (22 वर्ष)

सलेक्शन ग्रेड—र० 1400

पुलिस उप महा निरीक्षक—र० 1600-100-1800।

पुलिस कमिशनर, कलकत्ता और बम्बई—र० 1800-100 2000।

पुलिस महा निरीक्षक—र० 2500-125/2-2750

निदेशक, खुफिया ब्यूरो—र० 2750।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

(छ) }
(ज) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (छ),
(झ) } (ज), (झ) और (ञ) में दिया गया है।
(ञ) }

4. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी 2

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्कास सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पकका कर दिया जाएगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी। उससे भारत सरकार के किसी पुलिस-खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है।

(च) वेतन-मान।

ग्रेड I—(मलेक्शन ग्रेड)—रु० 900 नियत।

ग्रेड II—समय-मान—रु० 300-25-175-रु० 25-650-रु० 30-800।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति की नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतन-मान से बस-से-बस वेतन मिलेगा।

इस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली, 1965 के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारी उम्मीदर से महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समवक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होंगे।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहने-सहने के बड़े खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायते अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनु रूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

5. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड II (श्रेणी 1)---

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम-संगठनों (media organisation) में भारत भर में हैं। इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार-एजेन्सी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं-

ग्रेड	वेतन-मान
श्रेणी 1	
स्लैक्शन ग्रेड	रु० 2250 (नियत)
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1800-100-2000
(जूनियर मान)	रु० 1600-100-1800

ग्रेड	वेतन-मान
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1300-60-1600
(जूनियर मान)	रु० 1100-50-1400
ग्रेड I	रु० 700-40-1100-50/2-1250।
ग्रेड II	रु० 400-400-450-30-600-35-670-रु० 30-35-950।

श्रेणी 2 (राजपत्रित)

ग्रेड III	रु० 350-25-500-30-590-रु० 30-800।
-----------	-----------------------------------

श्रेणी 2 (राजपत्रित)

ग्रेड IV	रु० 270-10-290-15-410-रु० 15-485।
----------	-----------------------------------

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में, नीचे बताई गई प्रतिशतता के अनुसार खाली जगहों में सीधी भर्ती की जाती है :—

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	12%
ग्रेड I	25%
ग्रेड II	50%
ग्रेड III	100%

उपर्युक्त ग्रेडों का बाकी खाली जगहों और स्लैक्शन ग्रेड, सीनियर प्रशासनिक ग्रेड, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर मान) और ग्रेड III की खाली जगहों भी, ठीक निचले ग्रेडों के ड्यूटी पदों (duty posts) पर काम करने वाले अधिकारियों में से चुने गए व्यक्तियों की पदोन्नति करके भरी जाएगी।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधे भरती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा-काल में उन्हें भारतीय लोक संचार संस्थान (इंडिया इंस्टीट्यूट आफ माम कम्यूनिकेशन) किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 15 मास होगी। प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की “पाठ्य-क्रम संपूर्ति परीक्षा” (एंड-आफ-द-कोर्स-टेस्ट) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम और द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में भाषा-ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा मुक्त किया जा सकता है अथवा उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसकी पदधारिता हो।

(ii) परख अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हों तो सरकार सीधे भर्ती होने वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है। यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण संतोषजनक न रही तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उत्तम समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे। यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो तो उसे तत्काल सेवा मुक्त किया जा सकता है।

(iii) परिवीक्षाधीनों को प्रारंभ में ग्रेड II के वेतन-मान में न्यूनतम वेतन मिलेगा। प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद परिवीक्षाधीनों का वेतन बढ़ाकर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड II के वेतन क्रम में रु० 450 कर दिया जाएगा। द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसका वेतन रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। यदि कोई परिवीक्षाधीन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्य-क्रम-संपूर्ति-परीक्षा" में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि को, जिस तारीख को यह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जाएगा।

(ङ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी बि-शिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है।

(छ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जाएगा।

परिवीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा।

7. भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा।

8. भारतीय रक्षा लेखा सेवा।

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किए जाने (confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खरम कर दी जाएगी।

(ख) यदि, यथा-स्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य

या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है या यदि यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोष-जनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिये चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किये गए लेखा कार्यालयों के संघर्ष में अन्तिम रूप से रहना पड़ेगा।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है।

(च) वेतन-मान—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान—
रु० 400-400-450-30-510-रु० 700-40-1100-50-2-1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड-रु० 1300-60-1600।

महालेखापाल-रु० 1800-100-2000-125-2250।

नोट 1.— परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी।

नोट 2.— परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3.— परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारंभ होगी। यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो

उसकी रु० 450 तक ले जाने वाली वेतन वृद्धि एक माल के लिये उसकी वेतन वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़नेवाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी।

भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क सेवा

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन रु० 400-400-450-30-
शुल्क, क्लास-I, सहायक 510-६० रो०-700-40-
क्लकटर, केन्द्रीय उत्पादन 1100-50/2-1250।
शुल्क, सहायक क्लकटर,
सीमाशुल्क।

डिप्टी क्लकटर, सीमा रु० 1100-50-1300-60-
शुल्क डिप्टी क्लकटर, 1600।
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
अतिरिक्त क्लकटर
अपिलेट क्लकटर

क्लकटर, सीमा-शुल्क रु० 1800-100-2000-125-
क्लकटर, केन्द्रीय 2250।
उत्पादन-शुल्क

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परीक्षा के आधार पर की जाएंगी किन्तु यदि परीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके मक्षम अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरंत सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परीक्षाधीन अधिकारी का परीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है अथवा उसके परीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किए जाने पर स्थायीकरण संबंधी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

(घ) भारतीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही 'फील्ड सर्विस' भी करनी होगी।

नोट 1.—एक परीक्षाधीन अधिकारी को प्रारंभ में रु० 400-400-450-30-510-६० रो० 700-40-1100-50/2-1250 के समय वेतन

में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवाकाल को वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मानेगा।

नोट 2.—परीक्षाधीन अधिकारी को समय-वेतन-मान में रु० 400 से अधिक वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह, समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती।

नोट 3.—परीक्षा की अवधि में अधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग सीमा-शुल्क विभाग मदक पदार्थ (नारकोटिक्स) विभाग में तथा बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग) के लिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में नियुक्त किया जाएगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी। उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी। पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, उसका वेतन पहली अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर, रु० 450 कर दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि देकर रु० 480 कर दिया जाएगा। वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जानेवाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता।

यदि कोई परीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उससे एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जाएगा।

नोट 4.—परीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास-I के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय मान:—

रु० 400-400-450-480-कु० रो०-700-40-1100-1100-1150-1150-1200-1200-1250।
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—
रु० 1300-60-1600।

र० 1600-100-1800 (सिलेक्शन ग्रेड)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

र० 1800-100-2000-125-2250।

रक्षा लेखा महानियंत्रक—र० 2750 (नियत)

नोट—1. परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम-से-कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी।

नोट—2. परखाधीन अधिकारियों को 400 र० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय-समय पर लागू होनेवाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगे; इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर प्राप्त होता उसकी तिथि एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

9. भारतीय आयकर सेवा, श्रेणी-1 (क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिस की अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है; परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतनमान:—

आय-कर अधिकारी, श्रेणी-I

र० 400-400-450-30-510-कु० र० 700-40-1100-50/2-1250।

आयकर सहायक आयुक्त—र० 1100-50-1300-60-1600।

आयकर आयुक्त—र० 1800-100-2000-125-2250।

परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज नागपुर में प्रशिक्षण

प्राप्त करना होगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 र० कर दिया जायेगा। विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर र० 480 कर दिया जायेगा। र० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाय।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जायेगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट—1. परखाधीन अधिकारी को 400 र० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा।

नोट—2. परखाधीन अधिकारियों को भलोभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आय-कर सेवा श्रेणी-I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकार का दावा नहीं कर सकेगे।

10. भारतीय आर्डनेंस फैंक्टरी सेवा, श्रेणी 1 (गैर तकनीकी संवर्ग)

नियुक्तियां सहायक प्रबंधक (गैर-तकनीकी) के पदों पर की जाएंगी। उम्मीदवार दो वर्ष तक परख पर रहेगा। इस अवधि में उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय तथा भाषा की परीक्षाएं पास करनी होंगी।

परख की अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

चुने हुए उम्मीदवारों को, अपनी नियुक्ति के समय, इस आशय का एक बांड भरना होगा कि वह अपनी परख-अवधि को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद, कम से कम तीन वर्ष तक भारतीय आर्डनेंस फैंक्टरी सेवा में कार्य करता रहेगा।

सहायक प्रबंधक, जिनका पुनरीक्षित वेतनमान र० 400-400-450-30-600-35-670-कु० र० 700-40-1100-50/2-1250। गुणों (Merits) के आधार पर, भारतीय आर्डनेंस फैंक्टरी सेवा के ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:—

वेतन-मान

1. उप-प्रबंधक (गैर-तकनीकी) र० 700-40-1100-

उप-सहायक महानिदेशक, 50/2-1250।

आर्डनेंस फैंक्टरी।

2. प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) रु० 1100-50-1400
सौनियर उप-सहायक
महानिदेशक, आईनेन्स फैक्टरी।
3. सहायक महानिदेशक रु० 1300-60-1600
आईनेन्स फैक्टरी (ग्रेड 2)
4. सहायक महानिदेशक, आई- रु० 1600-100-1800
नेन्स फैक्टरी (ग्रेड I)
5. उप-महानिदेशक, आईनेन्स रु० 1800-100-2000
फैक्टरी।

विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समय मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

11. भारतीय डाक सेवा

- (क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
- (ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसने कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।
- (ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- (घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियाँ करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतन मानः—

समय-मान रु० 400-400-450-30-510 रु०
रो० 700-40-1100-50/2-1250

(प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे)।

डाक सेवा निदेशक रु० 1300-60-1600।

महापोस्टमास्टर रु० 1800-100-2000-125-2250।

सदस्य, डाक-तार बोर्ड रु० 2250-125/2-2750।

Senior Members, Posts & Telegraph Board:
Rs. 3000.

- (च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के परखाधीन अधिकारी रु० 400-400-450-30-480-510-रु० रो०-700-40-1100-50/2-1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी।

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समयमान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

- (छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी I, के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे। चुने गए उम्मीदवारों को, सरकार के निर्देशानुसार, सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा।

12. भारतीय रेलवे सेवा—

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परख-अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा।

सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता।

(ख) भारतीय रेलवे सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो। हालांकि, दो वर्षों का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा, की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिये। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो। किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उस का वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी (क) पेशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसने वर्ष के बाहर न हो, भारतीय रेलवे सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख अवधि में उसे दी गई सब रकम वापस करनी होगी।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसने कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ज) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(झ) वेतन मानः—

(क) जूनियर रु० 100-400-450-30-600-35-670-कु० रो०-35-950 (प्राधिकृत मान) सीनियर रु० 700 [छटे वर्ष या पहले-40-1100-50/2-1350 (प्राधिकृत मान)]

जूनियर प्रशासनिक मान 1300-60-1600 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर प्रशासनिक मान रु० 1800-100-2000-125-2250 (प्राधिकृत मान)।

(ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख-अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेंगे तो रु० 400 से रु० 450 तक की उसकी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अस्थायी मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्योंही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्योंही उसको रु० 400-950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्षों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय राज्यात्मिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमीत परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पंद्रहवीं वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए

स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतनवृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रति मास किया जा सकेगा।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखार्थीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

13. सैनिक भूमि और छावनी सेवा (श्रेणी I और श्रेणी II)

(क) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि छः महीने से कम नहीं होगी।

(ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परखार्थीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा।

(ii) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी के ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख-अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

(iii) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा।

(घ) यदि ऊपर उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रतिमास मानी जायेगी और दोनों

में से किसी भी ओर से एक कसेट्टर मास का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि, देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा। जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जायेगी।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) वेतन-मान इस प्रकार है :—

प्रशासनिक पद

(i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।

रु० 1800-100-2000।

(ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।

रु० 1600-100-1800।

(iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।

रु० 1300-60-1600।

(iv) सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।

रु० 1100-50-1400।

श्रेणी-I

(v) उप-सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां, सैनिक संपदा अधिकारी और कार्य-पालक अधिकारी	रु० 400-400-450-30-510-कु० रु०-700-40-1100-50/2-1250।
--	---

श्रेणी-II

(vi) कार्यपालक अधिकारी	रु० 350-25-500-30-590-कु० रु०-30-800-कु० रु०-830-35-900
(vii) सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी	रु० 350-25-500-30-590-कु० रु०-30-800-कु० रु०-830-35-900

(ज) (i) श्रेणी I के अधिकारियों को, सामान्यतया, उप-सहायक निदेशक, सैनिक सम्पदा अधिकारी, और श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जायेगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा-13 की उपधारा—(4) के खण्ड (ड) का उप-खण्ड (i) लागू होता है।

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यतया, उन छावनियों में नियुक्त किया जायेगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं।

(स) (i) सभी पदोन्नतियाँ, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (by selection) की जाएंगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जायेगा जबकि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे]। श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी-I में तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि श्रेणी-II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो।

(आ) समय-समय पर संशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना, कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से संबंधित न हो।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है।

14. भारतीय रेलवे यातायात सेवा

(क) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उनको परख-अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में, उन्हें पैरा (ड) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा। यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जायेगी तो उसके अनुसार, परख की कुल अवधि भी बढ़ जायेगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हों, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी, परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकम वापस करनी होगी।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियाँ परख पर की जायेंगी जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे, उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जायेगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएँ पास कर ली हों। ध्यान रहे कि ये परीक्षाएँ नियमतः प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जायें क्योंकि विशेष (एक्सेशनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी वेतन-वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायेगी। किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद, परखाधीन अधिकारियों को एक अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा

व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होगी। जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझ लिये जायेंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा। जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षाएँ पास करने और पक्का होने पर, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतन-वृद्धियाँ ली जा सकेंगी।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनु-मोहित स्तर की हिंदी की एक परीक्षा पहले ही या परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी :—

(क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदानरहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा। वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी।

(छ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी, भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार, छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी।

(ज) अधिकारियों को, आमतौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा। जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे। और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे। परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (project) या रेलवे में स्थानान्तरित कर सके।

(झ) नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपेक्षिक वरीयता (रिलेटिव सीनियरिटी) आमतौर पर, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (Order of merit) के अनुसार निश्चित की जाएगी। यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख-अवधि बढ़ानी पड़े तो इससे उसकी वरीयता (सीनियरिटी) भी बट सकेंगी। जैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित

करने का अधिकार है। उसको यह भी अधिकार है कि वह प्रति-योगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार बरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है।

(इ) वेतन मान—

जूनियर—रु० 400-400-450-30-600-35-670
रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)---40-1100
-50/2-1250 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)---40-1100
-50/2-1250 (प्राधिकृत मान)।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300-60-1600
(प्राधिकृत मान)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1800-100-2000-
125-2250 (प्राधिकृत मान) :

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी। और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

यदि परखाधीन अधिकारी अपनी परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अंतिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400 से 950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी को वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जायेगा।

यदि कोई पराधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनको नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

(ट) वेतन-वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी।

(3) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति स्थापना (establishment) में खासी जगहें होने पर ही की जायेंगी और पूर्णरूप से चुना (selection) के आधार पर ही की जायेंगी। एकमात्र बरीयता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता।

(इ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियां हो और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है। परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जायेगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जायेगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है। इसमें महा-प्रबंधकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु, सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए।

(1) पाठ्यक्रम की अवधि—दो वर्ष।

विषय	अवधि
	मास
1. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	4
2. एरिया स्कूल, गार्ड की ड्यूटी सीखने के लिए	1
3. गार्ड का काम	$\frac{1}{2}$
4. बड़ौदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण का पहला दौर	3
5. टिकट घर, पार्सल कार्यालय, माल-गोदाम और यान्त्रिक शौध	1
6. यातायात सेवा कार्य, जिसमें दौराकार लेखा-निरीक्षक के साथ काम करना और स्टेशन पर खुद संतुलन-पत्र बनाना भी शामिल है	1 $\frac{1}{2}$
7. एरिया स्कूल में, सहायक स्टेशन मास्टर की योग्यता प्राप्त करने के लिये	1
8. गार्डमास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, गार्ड फोरमैन और गाड़ी परीक्षक का काम	3
9. सहायक लोको फोरमैन का काम	$\frac{1}{2}$
10. सहायक नियंत्रक का काम	2

विषय	अवधि
11. बड़ौदा स्टेशन कालेज में प्रशिक्षण (दूसरा दौर)	1½
12 (क) डिस्ट्रिक्ट या डिविजन कार्यालय में प्रशिक्षण	1
(ख) सहायक विजली नियंत्रक का प्रशिक्षण	1½
13. मुख्यालय (परिचालन कार्यालय) में प्रशिक्षण	1½
14. मुख्यालय (वाणिज्य कार्यालय) में प्रशिक्षण	1½
	23½
विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों को करने के लिये की जाने वाली यात्रा के लिये और अपरिहार्य छुट्टियों के लिये नियत की गई अवधि	½
कुल	24 मास

(2) यदि परगवाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्यकारी पद का भार परग पर सौंप दिया जायेगा। परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निर्दिष्ट समय पर ली जायेगी।

नोट—किसी परगवाधीन अधिकारी को, स्वतन्त्र रूप से, गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के संबंध में उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाये।

15. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड है :—

ग्रेड	वेतनमान
सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	रु. 1100-50-1300-60-1600-100-1800
ग्रेड-I अवर सचिव	रु. 900-50-1200
अनुभाग अधिकारी ग्रेड-I	रु. 350-25-500-30-590-कु. 10-30-800-कु. 10-30-830-35-900।
सहायक ग्रेड	रु. 210-10-270-15-300-कु. 10-15-450-कु. 10-20-530।

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल-सचिवालय आधार पर गृह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड, सचिवालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परग पर रखा जायेगा। इस परग-अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, यदि परगवाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परग-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परग-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया “अनुभागों” का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को, सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड-I में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी पेशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे।

16. सीमा-शुल्क मूल्य-निरूपक सेवा, श्रेणी-II

(क) निर्धारित वेतनमान रु. 350-25-500-30-590-कु. 10-30-800-कु. 10-30-830-35-900 है। इस सेवा में सीधे भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों को दो वर्ष तक परग पर रखा जायेगा। इस परग-अवधि में उन्हें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षा पास करनी होंगी। प्रशिक्षण की अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकने पर या परीक्षा पास न कर सकने पर, परगवाधीन अधिकारियों का सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) परग-अवधि के समाप्त हो पर और विभागीय-परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने पर, अधिकारी पक्के किये जा सकेंगे, यदि स्थायी पद उपलब्ध होंगे। यदि सम्बन्धित सीमा-शुल्क समाहर्ता की राय में परगवाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न हो तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या उसकी परग-अवधि उतनी बढ़ाई जा सकती है जितनी कि संबंधित सीमा शुल्क समाहर्ता उचित समझे।

(ग) मूल्य-निरूपक के रूप में सेवा की अवधि समाप्त होने पर अधिकारी रु. 600-50-950 के वेतनमान में प्रधान मूल्य-निरूपक के ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र हो जायेंगे और उसके बाद वे सहायक समाहर्ता, श्रेणी-I के पदों पर पदोन्नत हो सकेंगे।

(घ) जहाँ तक छुट्टी, पेशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, वे श्रेणी-II के अन्य अधिकारियों के समान समझे जायेंगे।

नोट— उपर दिये गये वेतन और ग्रेड बदले जा सकते हैं।

17. **विलुप्त, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, श्रेणी-II।**

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी, जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएँ दनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण सतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी सतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पकवा कर दिया जायेगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी।

(ङ) वेतनमान —

ग्रेड I—(सलेक्शन ग्रेड) —र० 900-50-1200।

ग्रेड II—र० 300-30-510-रु० रो० 80-600-40-720-रु० रो० 40-800-50-850।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये व्यक्ति को नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतनमान में कम-से-कम वेतन मिलेगा। उक्त सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

(च) उक्त सेवा के अधिकारी उसी दर में महंगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे जो पञ्जाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्त हागी।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहना-महान के बड़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और जिन स्थानों के लिये वे भत्ते अनुमत्त होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों

द्वारा शासित होंगे जो मध्य के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनु रूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

18. **रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी-II**

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतनमान हैं :—

सेवा	वेतनमान
(i) सहायक निदेशक अवर सचिव	र० 900-50-1250
(ii) अनुभाग अधिकारी	र० 350-25-500-30-590- रु० रो०-30-800-रु० रो० 830- 830-35-900
(iii) सहायक	र० 210-10-270-15-300- रु० रो०-15-450-रु० रो० -20- 530 :

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख-अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएँ पास करनी होंगी। यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएँ पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पकवा कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको सामान्यता अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव की सामान्यता शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस श्रृंखला में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आवेश Privilege Ticket orders लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ज) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकारी भी)

(क) रेलवे पेंशन रूल से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अन्तर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिये दिये जा रहे हैं, ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि वे शारीरिक स्वास्थ्य के अपेक्षित स्तर तक आते हैं या नहीं। पर यह साफ-साफ समझ लेना चाहिये कि भारत सरकार अपने निर्णय से वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को शारीरिक दृष्टि से अक्षम मान कर स्वीकार कर सकती है और उसका निर्णय किसी भी प्रकार इन विनियमों से बंधा नहीं है। ये विनियम केवल मेडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिये हैं और इनसे उसका निर्णय किसी प्रकार भी सीमित नहीं होता।)

रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवा (ओं) की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जायेगी।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के लिये ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में निपमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार का योग्य अथवा अयोग्य करेगा।

(ख) निश्चित मंडाओं के लिये कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

कद छाती का घेर (पूरा फैला कर)	कद छाती का घेर (पूरा फैला कर)		
	में० मी०	से० मी०	से० मी०
(1) भारतीय रेल यातायात सेवा	152	84	5 (पुरुषों के लिए)
	150	79	5 (महिलाओं के लिए)
(2) भारतीय पुलिस, दिल्ली, हिमाचल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा, क्लास II	165	84	5 (पुरुषों के लिए)
	150	79	5 महिलाओं के लिए)

गोरखा, गढ़वाली, असमिया, आदिम जातियों आदि उम्मीदवारों के लिये, जिनका औसत कद विशेष रूप से कम होता है, कम-से-कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार मटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आयाम में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अंकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितंब और कंधे माप-दंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जायेगा।

(4) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (गोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती का अधिक-से-अधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम-से-कम और अधिक-से-अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84-89, 86-93, 5 आदि। नाम को रिकार्ड करने समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिये।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिये।

6. उम्मीदवार की नज़र की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा :—

(i) सामान्य जलरत्न—किमी रंग या विलक्षणता (एव-नार्मेलिटी) का पता लगाने के लिये उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जायेगी। यदि उम्मीदवार को ऐसा भेगापन या आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कॉन्जुअस स्ट्रक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिये उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ii) दृष्टि का पकड़ (विजुअल एक्विटी) —दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिये दो जांचें की जायेगी, एक दूर की नज़र के लिये और दूसरी नज़दीक की नज़र के लिये। प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जायेगी।

चश्मे के बिना नज़र (नेकेड आई विज़न) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नज़दीक की नज़र का मानक निम्नलिखित होगा :—

		नज़दीक की			
		दूर की नज़र		नज़र	
		अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
1. भारतीय रेलवे यातायात सेवा	अथवा	6/9	6/9	0.6	0.8
		6/6	6/12		
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड-II) श्रेणी-I, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, भारतीय रक्षा लेखा, सेवा, भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी-I) भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी-I (सहायक प्रबंधक,					

अतकनीकी) भार-
तीय डाक-सेवा, श्रेणी-I, सैनिक भूमि और छावनी सेवा श्रेणी-I, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II सीमाशुल्क मूल्य-निरूपक सेवा श्रेणी-II, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II, रेलवे बोर्ड सचिवानय सेवा, श्रेणी-II सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी II

6/9 6/9 0.6 0.8
अथवा
6/6 6/12

3. भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी-II

6/9 6/9 0.6 0.8
अथवा
6/6 6/12

नोट :—

ऊपर संख्या 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिए प्रत्येक आंख में मायोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत)—4.00 से अधिक नहीं होगी। हाइपरमेट्रोपिया की कुल मात्रा प्रत्येक आंख में—4.00 डी से अधिक नहीं होगी।

ऊपर संख्या में उल्लिखित सेवाओं के लिये प्रत्येक आंख में मायोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत)—8.00 से अधिक नहीं होगी। हाइपरमेट्रोपिया की कुल मात्रा प्रत्येक आंख में—6.00 डी से अधिक नहीं होगी।

(3) फंडस परीक्षा—जब कभी सम्भव होगा मेडिकल बोर्ड की इच्छा पर फंडस परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड किये जायेंगे।

(4) कलर विज़न —(i) ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिये रंगों के संबंध में नज़र की जांच जरूरी है।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होता चाहिए जो लैटर्न के द्वारक (एपचर) के आकार पर निर्भर हों।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतम ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतम ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 मैकंड	5 मैकंड

जनता की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिये जैसे पाइलट, डाइवर, गार्ड आदि, के लिये कलर विजन का हायर ग्रेड अनिवार्य है लेकिन अन्य सेवाओं के लिये कलर विजन का लोअर ग्रेड ही काफी समझना चाहिये।

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इजिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिनमें एड्रिज ग्रीन की लैटर्न जैसी उपयुक्त लैटर्न और अच्छी गेजनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिये बिल्कुल विश्वासनीय समझा जायेगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिये लैटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिये।

(5) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मेथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परीमापी (पेरीमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

(6) रतांधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतांधी की जांच नेमी रूप से जरूर नहीं है, रतांधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिये कोई नियत स्टेडंड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने चाहिये जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि की पकड़ रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिये किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिये।

(7) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएँ (आक्यूलर कंडिशन)—(क) आंख की उस बीमारी को या बकूनी हुई बर्तन छुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिये।

(ख) रोहे (ट्रैकोमा) —यदि रोहे जटिल न हों तो वे आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भेंगापन (स्क्वट) ऊपर 1 और 3 में लिखी सेवाओं के लिये द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजमी है। नियत

स्टैंडर्ड की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिये। दूसरी सेवाओं के लिये उस हाइत में भेंगापन को अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिये जब दृष्टि की पकड़ नियत स्टैंडर्ड की हो।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिये एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती।

7. ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय में काम लेगा। नार्मल उच्चतम मिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+ आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाये। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के मिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिये, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिये कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिये कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) है [ऐसे सभी केंसों में हृदय को एकमरे और विद्युत् हल्नेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक)] परीक्षण और रक्त यूरिया निकाम (लॉयरेम) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमन : पारेवाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रुमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह आरंभ विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ-कुछ हागरिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाना है। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अंदर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाता चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रैंकियल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूँढा जाता है और तब इस के ऊपर बीचों-बीच स्टेस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 m.m. Hg हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक

ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टोलिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हलकी दबी हुई गी लुप्त प्राय हो जाए, वह डायस्टोलिक प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कपल के लम्बे समय का दबाव होगी के लिए क्षोभकार होता है और इनसे रीडिंग गलत हो जाता है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिये और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिये। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा ग्लूकोज का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज) के घेतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह भ्रमधु मेही (नान डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिये बोर्ड के मामले स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। अपेक्षित के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकती है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए।

9. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए।

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ना है या नहीं और कान की बीमारी का कोई विह्वल है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को उस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। रेलवे सेवाओं के लिए यह बाल लागू नहीं है।

(ख) उम्मीदवार बांहने में हकलाला या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में है या नहीं; और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर तकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रफचर (हानिया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बड़ी हुई वेरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसकी छायाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरूपता या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं। जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

10. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से जात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अमेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

नोट :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है। किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अंदर पेश करना चाहिए, वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाणपत्र पेश करें तो इस प्रमाणपत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि इसमें संबंधित मेडिकल प्रेक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाणपत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका है।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या

नियुक्ति प्राधिकारी (अपार्टिंग अयारिटी) को, यह तय नहीं होगी कि उसे ऐसी बोर्ड बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (वाडिनी इन्फर्मिटी) नहीं है जिसे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने का सम्भावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगीयों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहाँ केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हानत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थिति में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिफाई करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टर बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टर बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत व्योरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहाँ डाक्टर बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहाँ डाक्टर बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिफाई किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह

खराबी दूर हो जाय तो एक दूसरे डाक्टर बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाय तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। मिश्रित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा:—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उस के साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेण) पर हस्ताक्षर करने चाहियें। नीचे दिये गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें.....

(माफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं.....

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियाँ (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी मूलाँ के दौरे, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था?

5. क्या आप को या आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार को तपेदिक, स्कोफ्यूला, गाऊट, दमा, दौरे (फिट्स) मिरगी (एपिलेप्सी) या पागलपन (इन्सेनिटी) हुआ है?

6. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

7. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा दें।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों को मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
--	--	---	--

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
--	---	---	---

8. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

9. यदि उपर के प्रश्न का उत्तर 'हाँ' हो तो बताइए कि सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

10. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

11. कब और कहाँ मेडिकल बोर्ड हुआ ?

12. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

मैं घोषित करता हूँ कि जहाँ तक मेरा विषय है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

नोट—उपयुक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो वाधक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेजुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) की शारीरिक परीक्षा की/

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा बीच का कम पोषण : पतला औसत मोटा कद (जूते उतार कर) वजन अत्युत्तम वजन कब था ? वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन तापमान छाती का घेरा

(1) पूरा सांस खींचने पर

(2) पूरा सांस निकालने पर

2. त्वचा—कोई ज़ाहिरा बीमारी

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी

(2) रतौंधी

(3) क्लर विजन का दोष

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ऑफ़ विजन)

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एंगिवटी)

दृष्टि की पकड़ चश्मे के बिना चश्मे की पावर

गोल मिलि० अक्ष

दूर की नज़र दा० ने०

बा० ने०

पाम की नज़र दा० ने०

बा० ने०

हाइपरमेट्रोपिया दा० ने०

(व्यक्त) बा० ने०

4. कान : निरीक्षण सुनना :

दायाँ कान बायाँ कान

5. ग्रंथियाँ थाइराइड

6. दातों की हालत

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेंटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्योरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (मर्क्युरेरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन) ?

गति (रेट) :

खड़े होने पर :

25. बार कुदाए जाने के बाद

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद

(ख) ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक

9. उदर (पेट) : घेरा दाव वेदना (टेंडरनेस)

हिनिया

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर तिल्ली

गुर्दे ट्यूमर

(ख) बवासीर के मम्मे फिस्चुला

10. तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)

कोई विलक्षणता

12. जनन-मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम) / हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत।

मूत्र परीक्षा

(क) कैसा दिखाई पड़ना है

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षक गुरुत्व)

(ग) एल्ब्यूमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को वक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है ?

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा

(ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I और II

(ii) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है —

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें) ।

(ग) भारतीय रेलवे के परिचहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें) ।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिये योग्य है ?

नोट—बोर्ड को अपना जांच-परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये ।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण

स्थान अध्यक्ष (प्रेसिडेंट)

तारीख सदस्य

सदस्य

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 1967

सं० 6-1/66-एस०ए०पी०—भारत सरकार के केन्द्रीय शुसक क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर के निदेशक को इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 6-1/66 एस० ए० पी० दिनांक 18 जून 1966 के अन्तर्गत स्थापित हुए केन्द्रीय मरुभूमि विकास बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं ।

पी० पी० आई०, वैद्यानाथन, अतिरिक्त सचिव

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1967

सं० 6-7/65-बी०सी०—इस विभाग के 22 जुलाई, 1965 के संकल्प संख्या 6-7/65-बी०सी० के सिलसिले में यह अधिसूचित किया जाता है कि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के सचिव के स्थान पर सहकारिता विभाग के अतिरिक्त सचिव, श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियों के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य नामांकित किए जाते हैं ।

आदेश

आदेश है कि इस अधिसूचना की प्रति सभी सम्बंधितों को भेजी जाए । यह भी आदेश है कि इस अधिसूचना को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

ए० सी० बंधोपाध्याय, संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1967

संकल्प

विषय—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबंधित संकल्प में संशोधन :

सं० एफ० 1-2/64-टी० 2—समय-समय पर (19 जुलाई, 1966 तक) संशोधित भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा विभाग के संकल्प सं० एफ० 16-10/44 ई० III दिनांक 30 नवम्बर, 1945 में संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति सहर्ष यह आदेश देते हैं कि उक्त संकल्प के खंड (1) के उप-खंड (एन) के पैराग्राफ 3 में, जिसके अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी, “दस” शब्द को “ग्यारह” पढ़ा जाए । उप-खंड इस प्रकार पढ़ा जाएगा:—

(एन) “व्यावसायिक निकायों के ग्यारह प्रतिनिधि”

आदेश

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

3. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दी जाए ।

ए० बी० चंदीरामाणी, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (टी)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1967

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड

सं० एफ० 23-87/65 (यू० 4) एच० ई० I—देश का पुस्तक उद्योग आम तौर पर और पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्य विशेष रूप से, काफी समय से पिछड़ा हुआ रहा है । भारतीय लेखकों की भारत में ही प्रकाशित प्रत्येक किस्म की उपयुक्त पुस्तकों की कमी की जानकारी के बारे में उत्तरोत्तर जागरूकता बढ़ रही है । इसलिए, भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह देश भर में पुस्तक उत्पादन और पुस्तक उद्योग के विकास के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक समन्वित नीति बनाए और उस पर अमल करें ।

2. राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड—इसलिए भारत सरकार ने प्रत्येक किस्म की पुस्तकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक-राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है । यह बोर्ड देश की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तक उद्योग के विकास के लिए कार्य-पद्धति निर्धारित करेगा । यह बोर्ड, जिनके पुस्तक उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के और पुस्तक कार्यक्रमों को

कार्यान्वित करने वाले विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों के प्रतिनिधि होंगे, पुस्तक उत्पादन के क्षेत्र में सभी कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए, सरकार तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के विचारार्थ और कार्यान्वयन के लिए ठोस सिफारिशें करेगा।

3. **बोर्ड के कार्य**—बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

- (क) उच्च अध्ययन के क्षेत्र को शामिल करते हुए, देश की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तक उद्योग के विकास के लिए कार्यपद्धति निर्धारित करना;
- (ख) लेखन, मंजी से संबंधित समस्याओं और विशेषकर निर्यात के क्षेत्र को हाथ में लेने, संगठन करने और अनुसंधान करने के बारे में मूल्यांकन करना तथा सलाह देना और इस बात का अध्ययन करना कि भारतीय पुस्तकों का यथासम्भव किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा वितरण किया जा सकता है;
- (ग) पुस्तक उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय सुझाना;
- (घ) भारतीय लेखकों को उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों लिखने और भारतीय प्रकाशकों को उनको प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहन देने के उपाय सुझाना;
- (ङ) ऐसे अन्य कार्य भी सम्पादन करना जो उपर्युक्त अधिकारों के अन्तर्गत हों अथवा नहीं, किन्तु जो उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों।

4. **बोर्ड का प्रधान कार्यालय**—बोर्ड का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. **बोर्ड का गठन**

- (क) अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा।
- (ख) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (ग) उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (घ) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (ङ) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (च) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि।
- (ज) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि।
- (झ) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का एक प्रतिनिधि।
- (ञ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक प्रतिनिधि।
- (ट) ऐसे अन्य व्यक्ति जो पुस्तक प्रकाशन, मुद्रण और व्यापार से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों में से, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामजद किये जाएं, किन्तु इसकी संख्या 20 से अधिक न होगी।

6. **सदस्यता की कार्यधि**—बोर्ड के प्रत्येक सदस्य की कार्यधि तीन वर्ष होगी, किन्तु उसकी दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। बोर्ड का ऐसा कोई सदस्य, जो अपने पद अथवा नियुक्ति के आधार पर बोर्ड का सदस्य होता है, यदि वह अपने पद अथवा नियुक्ति पर न रहे, तो वह बोर्ड का सदस्य भी न रहेगा।

सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थानों (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) पर नियुक्ति उस प्राधिकारी अथवा संस्था द्वारा की जाएगी जिसने उस सदस्य को नामजद किया हो, जिसके कारण स्थान रिक्त हुआ हो और आकस्मिक रिक्त स्थान पर नियुक्त व्यक्ति बोर्ड का सदस्य, उस बाकी अवधि के लिए होगा, जिस व्यक्ति का स्थान भरा जा रहा है, जिसने समय बह रहा।

7. **बैठकें तथा उप-समितियाँ**—बोर्ड की बैठक साधारणतया वर्ष में दो बार होगी। बोर्ड विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समितियाँ नियुक्त कर सकता है जिसकी आवश्यकतानुसार बैठकें होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और उसके विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय और आयोजना आयोग को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाए।

जी० के० खन्वीरामाणी, अवर सचिव

परिवहन तथा विमानन मंत्रालय

परिवहन तथा नौवहन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 1967

संस्ताव

अन्तर्वेसी जल परिवहन निदेशालय

सं० 4-आई० डब्ल्यू० टी० (55)/66—गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल परिवहन मंत्रालय संस्ताव संख्या 6-एम० (8)/51 दिनांक 8 मार्च, 1952 के अन्तर्गत गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में नौचालन से संबद्ध नियंत्रण सफाई तथा अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के लिये आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के लिये एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

2. चतुर्थ योजना काल में अन्तर्वेसी जल परिवहन सुविधाओं के शीघ्रतर विकास प्राप्त करने की आवश्यकता और गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल में उपलब्ध आदमियों, सामग्री और उपस्कर के क्लोटों को उपयोग में लाने की आवश्यकता जिससे अन्तर्वेसी जल परिवहन विकास के लिये स्कीमों की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिये एक सक्रिय संगठन उद्भूत हो सके, यह निश्चय किया गया है कि 1 मार्च, 1967 (पूर्वाह्न) से परिवहन तथा विमानन मंत्रालय के अन्तर्वेसी जल परिवहन निदेशालय में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल का बिलय कर दिया जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रति माननीय राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

के० सी० मादप्पा, संयुक्त सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 17th February 1967

No. F.15/12/66-CDN.—The National Planning Council was set up under Planning Commission Resolution No. F.15/1/65-CDN, dated February 26, 1965 as a small body of specialists to work in close and continuous association with the Planning Commission and its Members. Its term, which was initially for a period of two years, has been extended for a further period of one year.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

K. A. P. STEVENSON, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 4th March, 1967

No. 20/1/67-AIS(I).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in October, 1967, for the purpose of filling vacancies in the following services are with the concurrence of the Ministers concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service, published for general information:—

Category I

- (i) The Indian Administrative Service, and
- (ii) The Indian Foreign Service.

Category II

- (i) The Indian Police Service, and
- (ii) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II.

Category III

(a) Class I Services:

- (i) The Central Information Service, (Grade II), Class I.
- (ii) The Indian Audit & Accounts Service.
- (iii) The Indian Customs and Central Excise Service,
- (iv) The Indian Defence Accounts Service,
- (v) The Indian Income tax Service (Class I),
- (vi) The Indian Postal Service,
- (vii) The Indian Railway Accounts Service,
- (viii) The Indian Railway Traffic Service, and
- (ix) The Military Lands and Cantonments Service, Class I.

(b) Class II Services:

- (i) The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II,
- (ii) The Customs Appraisers' Service, Class II,
- (iii) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II,
- (iv) The Railway Board Secretariat Service, Class II, and
- (v) The Military Lands and Cantonments Service, Class II.

A candidate may compete in respect of any one or more of the categories of Services mentioned above (Please see Rule 4). He may specify in his application as many of the Services covered by the category/categories concerned, as he may wish to be considered for.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. The combined competitive examination for recruitment to I.A.S. etc. is to be treated as comprising three separate and distinct examinations for three categories of Services, viz., (i) I.A.S. and I.F.S. (ii) I.P.S. and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service and (iii) Central Services and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania formerly Tanganyika and Zanzibar shall be permitted to compete more than two times at the examination for each of the three categories of Services mentioned in Rule 4 above, but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

(2) For other services, a candidate must be either:—

- (a) citizen of India, or
- (b) a subject of Sikkim, or
- (c) a subject of Nepal, or
- (d) a subject of Bhutan, or
- (e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India, and if he belongs to category (f) the certificate of eligibility, will be issued for a period of one year after which such a candidate will be retained in service subject to his having acquired Indian citizenship.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories:—

- (i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.
- (ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution.
- (iii) Non citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

7. (a) (i) A candidate for the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service and for all the remaining services, excepting the Indian Police Service and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service mentioned in paragraph 1 above must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st August, 1967 i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1943 and not later than 1st August 1946.

(ii) A candidate for the Indian Police Service and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service must have attained the age of 20 years, and must not have attained the age of 24 years on the 1st August, 1967 i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1943 and not later than 1st August 1947.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable:—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;
- (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;
- (v) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vi) up to maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;
- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);
- (ix) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (xi) up to a maximum of three years in the case of the disabled ex-Defence services personnel; and
- (xii) up to a maximum of eight years in the case of the disabled ex-Defence Services personnel who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

8. A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed

before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

9. A candidate who is appointed to a Service in Category I (I.A.S. or I.F.S.) on the results of an earlier examination will not be eligible to compete at this examination.

A candidate who is appointed to a Service mentioned in col. (ii) below on the results of an earlier examination will be eligible to compete at this examination only for Services mentioned against that Service in col. (iii) below:

Sl. No.	Service to which appointed.	Services for which eligible to compete
(i)	(ii)	(iii)
1.	Indian Police Service	(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.). (ii) Central Services, Class I, in Category III.
2.	Central Services, Class I	(i) Category, I (I.A.S. and I.F.S.). (ii) I.P.S. in Category II.
3.	Central Services, Class II, Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands. Civil Service and Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.	(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.). (ii) I.P.S. in Category II. (iii) Central Services, Class I, in Category III.

10. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

11. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or a temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period:—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service.

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application, but the Government of India reserve the right to assign him to any Service for which he is a candidate.

Provided that a candidate who is appointed to a Service in Category I (I.A.S. or I.F.S.), on the results of an earlier examination, will not be considered for allotment to any other Service on the results of this examination.

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in col. (ii) below on the results of an earlier examination will be considered only for allotment to Services mentioned against that Service in col. (iii) below, on the results of this examination.

S. No.	Service to which appointed.	Service to which allotment will be considered.
(i)	(ii)	(iii)
1. Indian Police Service		(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.). (ii) Central Services, Class I, in Category III.
2. Central Services, Class I		(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.). (ii) I.P.S. in Category II.
3. Central Services, Class II, Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service and Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.		(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.). (ii) I.P.S. in Category II. (iii) Central Services, Class I, in Category III.

20. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

21. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

22. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

23. It will be open to the Government of India, not to appoint to the Indian Administrative Service/Indian Police Service/Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service/Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, a woman candidate who is married or to require such a candidate who is not married, to resign from the Service in the event of her marrying subsequently if the maintenance of the efficiency of the Service so requires.

24. For the Indian Foreign Service a woman candidate is eligible only if she is unmarried or a widow without encumbrances. If such a candidate is selected, she will be appointed on the express condition that she might be called upon to resign from the Service on marriage or re-marriage.

Under no circumstances, the officers appointed to the Indian Foreign Service will be allowed to marry persons other than of Indian nationality.

25. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into service.

26. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

A. N. BATASYAL, Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 8)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).
The National University of Dublin.
The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.
The Dacca University.
The University of Sind.
The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (*vide* Rule 8).

1. Alankar of Gurukul Vishwa Vidyalyaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kasbi Vidyapith, Banaras.
3. French Examination "Baccalaureat."
4. French Examination "Propedeutique."
5. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
6. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.
- Diploma in Commerce of All India Council for Tech. Education.
8. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Tech. Education.
9. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student."
10. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination comprises:—

(A) Written examination in—

- (i) three compulsory subjects (for all Services), Essay, General English, and General Knowledge, each with a maximum of 150 marks [see Sub Section (a) of Section II below];
- (ii) a selection from the optional subjects set out in Sub-Section (b) of Section II below. Subject to the provisions of that Sub-Section, candidates may take optional subjects up to a total of 600 marks for all Services except the Services under Category II (cf. Rules 1 & 4) for which optional subjects up to a total of 400 marks only may be taken. The standard of these papers will be approximately that of an Honours Degree Examination of an Indian University; and
- (iii) a selection from the additional subjects set out in Sub Section (c) of Section II below. Subject to the provision of that Sub Section, candidates may take additional subjects up to a total of 400 marks for the Indian Administrative Service and Indian Foreign Service (Category I). The standard of these papers will be higher than that prescribed for the optional subjects under Sub Section (A) (ii) above.

(B) Interview for Personality Test (*vide* Part D of the Schedule to the Appendix) of such candidates as may be called by the Commission, carrying maximum marks as follows:

Category I

Indian Foreign Service	400
Indian Administrative Service	300

Categories II & III

All Services	200
------------------------	-----

SECTION II

Examination Subjects

(a) *Compulsory subjects* (*vide* Sub-Section A(i) of Section I above) :—

	Maximum Marks
(1) Essay	150
(2) General English	150
(3) General Knowledge	150

Note.—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

(b) *Optional subjects* (*vide* Sub Section A(ii) of Section I above).

Candidates for Services under Category II (cf. Rules 1 and 4) may offer any two, and for all other Services any three of the following subjects :—

	Maximum Marks
(1) Pure Mathematics	200
(2) Applied Mathematics	200
(3) Statistics	200
(4) Physics	200
(5) Chemistry	200
(6) Botany	200
(7) Zoology	200
(8) Geology	200
(9) Geography	200
(10) English Literature	200
(11) Hindi	200
(12) One of the following — Arabic, Chinese, French, German, Latin Pali, Persian, Russian, Sanskrit and Spanish	200
(13) Indian History	200
(14) British History	200
(15) European History	200
(16) World History	200
(17) General Economics	200
(18) Political Science	200
(19) Philosophy	200
(20) Psychology	200
(21) Law	200
(22) Public International law	200
(23) Mercantile Law	200
* (24) Advanced Accountancy & Auditing	200
(25) Applied mechanics	200

Provided that the following restrictions shall apply to particular optional subjects:

- (i) Of the subjects 1, 2 and 3, not more than two can be offered for any Service.
- (ii) Candidates for Services other than the Indian Foreign Service may not offer more than one of the languages mentioned under item 12 above. For the Indian Foreign Service only, candidates are allowed to offer any two of these languages; but not candidate shall be allowed to offer both Pali and Sanskrit.
- (iii) Of the History subjects 13, 14, 15 and 16, not more than two can be offered for any Service but no candidate shall be allowed to offer both World History and European History.
- (iv) Of the subjects 19 and 20, not more than one can be offered for any Service.
- (v) Of the Law subjects 21, 22 and 23, not more than two can be offered for any Service.

- (vi) Subject 25 must not be offered for the Service under Category II.

*The subject "Advanced Accountancy & Auditing" will be deleted from the scheme of the examination to be held in 1968 and onwards.

NOTE.—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part B of the Schedule to this Appendix.

(c) Additional subjects (vide Sub Section A(iii) of Section I above).

Candidates competing for the Indian Administrative Service/Indian Foreign Service (Category I), must also select any two of the following subjects :—

	Maximum marks
(1) (a) Higher Pure Mathematics	200
or	
(b) Higher Applied Mathematics	200
(2) Higher Physics	200
(3) Higher Chemistry	200
(4) Higher Botany	200
(5) Higher Zoology	200
(6) Higher Geology	200
(7) Higher Geography	200
(8) English Literature (1798-1935)	200
(9) (a) Indian History (From Chandragupta Maurya to Harsha)	200
or	
(b) Indian History II (The Great Mughals 1526—1707)	200
or	
(c) Indian History III (From 1772 to 1950)	200
or	
(d) British Constitutional History (From 1603 to 1950)	200
or	
(e) European History (From 1871 to 1945)	200
(10) (a) Advanced Economics	200
or	
(b) Advanced Indian Economics	200
(11) (a) Political Theory from Hobbes to the present day	200
or	
(b) Political Organisation and Public Administration	200
or	
(c) International Relations	200
(12) (a) Advanced Metaphysics including Epistemology	200
or	
(b) Advanced Psychology including Experimental Psychology	200
(13) (a) Constitutional Law of India	200
or	
(b) Jurisprudence	200
(14) (a) Medieval Civilisation as reflected in Arabic Literature (570 A.D.—1650 A.D.)	200
or	
(b) Medieval Civilisation as reflected in Persian Literature (570 A.D.—1650 A.D.)	200
or	
(c) Ancient Indian Civilisation and Philosophy	200
(15) Anthropology	200
(16) Sociology	200

Provided that the following restrictions shall apply to particular additional subjects.

- (1) No candidate shall be allowed to offer both Indian History I [9(a)] and Ancient Indian Civilisation and Philosophy [14(c)].

- (2) No candidate shall be allowed to offer both European History [9(e)] and International Relations [11(c)].

NOTE.—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part C of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH, EXCEPT QUESTION PAPERS IN LANGUAGES WHICH, UNLESS SPECIFICALLY REQUIRED OTHERWISE, MAY BE ANSWERED IN ENGLISH OR IN THE LANGUAGE CONCERNED.

2. The duration of each of the papers referred to in Sub-Section (a), (b) and (c) of Section II above will be 3 hours.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. For the Indian Administrative Service and the Indian Foreign Service (Category I) the two additional papers of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in all the other subjects.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

[Vide Sub-Section (a) of Section II of Appendix II]

1. *Essay*.—Candidates will be required to write an essay in English. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

2. *General English*.—Candidates will be required to answer questions designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually be set for summary or precis. Credit will be given for concise and effective expression.

3. *General Knowledge*.—Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian History, and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

PART B

[Vide Sub-Section (b) of Section II of Appendix II]

1. *Pure Mathematics*.—The subjects included will be :—

Algebra, Trigonometry and Theory of Equations with Determinants.

Pure Plane Geometry and Analytical Geometry of two and three dimensions.

Differential and Integral Calculus and Differential equations.

2. *Applied Mathematics.*—The subjects included will be:—

Statics (including Theory of Attractions and Potentials) and Hydrostatics.

Dynamics of a particle and Elementary Rigid Dynamics.

3. *Statistics.*—Frequency distributions, average, percentiles, and simple methods of measuring dispersion, graphic methods, treatment of qualitative data, e.g., investigation of association by comparison of ratios, the practice of graphic and algebraic methods of interpolation.

Practical methods used in the analysis and interpretation of statistics of prices, wages and incomes, trade transport, production and consumption, education, etc., methods of dealing with population and vital statistics, miscellaneous methods used in handling statistics of experiments or observations.

Elements of modern mathematical theory of statistics, frequency curves and the mathematical representation of groups generally, accuracy of sampling as affecting averages, percentages, the standard deviation, significance of observed differences between averages of groups, etc., the theory of correlation for two variables.

4. *Physics.*—

General Properties of Matter and Mechanics.—Units and dimensions. Rotational motion and Moments of inertia. Gravity, Gravitation, planetary motion. Stress and Strain relationship, elastic moduli and their inter-relations. Surface tension, capillarity. Flow of incompressible fluids. Viscosity of liquids and gases.

Sound.—Forced vibrations and resonance. Wave motion. Doppler effect. Vibration of strings and air-columns. Measurement of frequency, velocity and intensity of sound. Musical scales. Acoustics of halls. Ultrasonics.

Heat and Thermodynamics.—Elements of the kinetic theory of gases. Brownian motion. Van der Waals' equation of state. Measurement of temperature, specific heat and thermal conductivity. Joule-Thomson effect and liquefaction of gases. Laws of thermodynamics. Heat engines. Black body radiation.

Light.—Geometrical optics, and simple optical systems. Telescope and microscope. Defects in optical images and their corrections. Wave theory of light. Measurement of velocity of light. Interference, diffraction and polarization of light. Simple interferometers. Elements of spectroscopy. Raman effect.

Electricity and Magnetism.—Calculation of field and potential in simple cases. Gauss's theorem. Electrometers. Electrical and magnetic properties of matter and their measurement. Magnetic field due to electric current. Galvanometers. Measurement of current and quantity of electricity. Potentiometer. Resistance, inductance and capacitance; and their measurement. Thermo-electricity. Elements of alternating currents. Dynamos and motors. Electrolysis. Electromagnetic waves. Radio valves and their simple applications, transmission and reception of wireless waves. Television.

Elements of Modern Physics.—Elementary properties of electron, proton and neutron. Planck's constant and its measurement. Bohr's theory of the atom. X-rays and their properties. Elements of radioactivity, and properties of alpha, beta and gamma rays. Nuclei of atoms. Elements of the special theory of relativity, mass and energy. Fission and fusion. Cosmic rays.

5. *Chemistry.*—

Inorganic Chemistry.—Structure of the atom. The Periodic Law. Radioactivity. Isotopes. Artificial transmutations of elements. Nuclear fission. Nature of chemical bonds. The inert gases of the atmosphere. Chemistry of the more common and useful elements and their compounds. Rare earth elements. Hydrides, oxides, oxyacids, peracids and persalts and carbides. Inorganic complexes. Basic principles of chemical analysis.

Organic Chemistry.—Petroleum and petroleum products. Chemistry of the following classes of aliphatic compounds: Saturated and unsaturated hydrocarbons, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, mono and di-carboxylic acids, esters, substituted carboxylic acids; thio, nitro and cyano compounds, amines, urea and ureides, organometallic compounds, monosaccharides (including structures) carbohydrates and proteins (general ideas). Simple alicyclic compounds. Strain theory.

Aromatic.—Benzene, naphthalene and anthracene and their principal derivatives; coal-tar distillation, phenols, aromatic alcohols, aldehydes, ketones. Aromatic acids and hydroxy acids. Steric hindrance. Arylamines. Diazo, azo and hydrazo compounds. Quinones. Heterocyclic compounds. Pyrrole, pyridine, quinoline, indole and indige. Azo, triphenyl-methane and phthalein dyes.

Simple molecular re-arrangements. Isomerism, stereoisomerism and tautomerism. Polymerisation.

Physical Chemistry.—The kinetic theory. Properties of gases. Equations of state (Van der Waals, Dieterici). The critical state. Liquefaction of gases. Physical properties of liquids in relation to their chemical constitution. Elementary Crystallography.

The first and second laws of thermodynamics and their application to simple physical and chemical processes. Chemical equilibrium and Law of Mass Action. Le Chatelier's Principle. The Phase Rule and its application to one-component systems and to the iron-carbon system.

Rate and order of a reaction. First and second order reactions. Chain reactions. Photochemical reactions. Catalysis. Adsorption.

Electrolytic dissociation. Ionic equilibria. Acid-base equilibria and indicators. Study of electrolytic conductance and its applications. Electrode potentials. E.M.F. of cells. Measurements of E.M.F. and their applications.

6. *Botany.*—

Form, structure, habit, economic importance, life-histories and inter-relationships of the important representatives of the various groups and sub-groups or families and sub-families of cryptogams (including bacteria and viruses) and phanerogams, with special reference to Indian plants.

The fundamental principles and processes of plant physiology.

A general knowledge of important diseases of crop plants in India and methods of their control and eradication.

The basic facts relating to ecology and plant geography, with special reference to Indian flora and the botanical regions of India.

Basic knowledge about evolution, cytology, genetics and plant breeding.

Economic uses of plants, specially flowering plants, in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products as food-grains, pulses, fruits, sugars and starches, oil-seeds, spices, beverages, fibres, woods, rubber, drugs, and essential oils.

A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

7. *Zoology.*—

The classification, bionomics, morphology, life-history, and relationships of non-chordates and chordates, with special reference to Indian forms.

Functional morphology (form, structure and function) of the integument, endoskeleton, locomotion, feeding, blood-circulation, respiration, osmoregulation, nervous system, receptors and reproduction. Elements of vertebrate embryology.

Evolution: evidences, theories and their modern interpretations. Mendelian inheritance; mutation. Structure of animal cell; basic principles of cytology & genetics. Adaptation and distribution.

8. *Geology.*—

Physical Geology and Geomorphology.—Origin, structure, interior and age of the Earth. Geosynclines and mountains. Isostasy. Origin of continents and oceans. Continental drift. Seismology. Volcanology. Geological action of surface agencies.

Structural and Field Geology.—Common structures of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Study of folds, faults, unconformities, joints and thrusts. Elementary ideas of methods of geological Surveying and Mapping.

Crystallography and Mineralogy.—Elements of crystal forms and symmetry; Laws of Crystallography; Crystal systems and classes; Crystal habits; twinning. Stereographic projections. Physical, chemical and optical properties of minerals. Study of more important rock-forming and economic minerals regarding their chemical and physical properties, crystallographic and optical characters, alterations, occurrence, and commercial uses.

Stratigraphy and Palaeontology.—Principles of Stratigraphy Indian Stratigraphy. Lithological and Chronological subdivisions of Geological record. Fossils—nature and mode of preservation: bearing on Organic evolution. Invertebrate and plant fossils.

Economic Geology.—Theories of Ore genesis; Classification, geology, occurrence, localities and resources of chief metallic and non-metallic minerals of India. Mineral industries in India. Principles of Geophysical prospecting and ore dressing.

Petrology.—Origin, constitution, structure and classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Study of common Indian Rock types.

9. Geography.—Physical and Human Geography of the world with special reference to India. Principles of Physical Geography comprising a detailed study of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, leading up to the modern views regarding cycle concepts, isostasy, processes of mountain formation, whether phenomena, surface and sub-surface movement of ocean waters, etc.

Principles of Human Geography comprising a detailed study of the distribution of man on the basis of culture, race, religion, etc., environment and mode of life, population trends, population movements.

Candidates are expected to have a detailed knowledge of physical, human and economic geography of India.

10. English Literature.—Candidates will be expected to show a general knowledge of the history of English Literature from the time of Chaucer to the end of the reign of Queen Victoria, with special reference to the works of the following authors :—

Shakespeare, Milton, Dryden, Johnson, Wordsworth, Keats, Dickens, Tennyson, Arnold and Hardy.

Evidence of first-hand reading will be required. The paper will be designed also to test the candidates' critical ability.

11. Hindi.—Candidates will be expected to have a general knowledge of the History of Hindi Literature from Chand Bardai to Premchand, as in paras. (2) & (3) below. They will also be expected to have a general idea of the evolution of Hindi language and its relationship to other Indian languages.

(2) Medieval Hindi Literature, with special reference to the works of Kabir, Nanak, Jayasi, Surdas, Tulsidas, Mira, Abdur Rahim Khankhana (Rahim), Keshava Das, Bihari and Bhushan.

(3) Modern Hindi Literature from Lalluji Lal to Premchand.

NOTE I.—Evidence of first-hand reading will be required. Candidates will also be expected to show general acquaintance with major literary works produced during the period in other Indian languages.

NOTE II.—Candidates will be expected to possess such knowledge of general social history as will enable them to understand the background of the development of the tendencies of Hindi literature during the last one hundred years.

12. Languages.—Candidates will be expected to show a knowledge of the principal classical authors and to be able to translate from and compose in the language.

NOTE.—Candidates for Arabic, Persian and Sanskrit may be asked to answer some questions in Arabic, Persian or Sanskrit as the case may be. Answers required to be written in Sanskrit must be written in the Devanagiri script.

13. Indian History.—From the beginning of the reign of Chandragupta Maurya to the establishment of Indian Republic. The paper will include questions on political, constitutional, economic and cultural developments.

14. British History.—The period of study will be from 1485 to 1945. The paper will include questions on political, constitutional, economic and cultural developments.

15. European History.—The period of study will be from 1789 to 1945. The paper will include questions on political, diplomatic, economic and cultural developments.

16. World History.—(From 1789 to 1945). Candidates will be expected to possess sound knowledge of the major political and economic developments in the world, with special reference to Europe, the U.S.A., the Far East, the Middle East and the African continent. There will be special emphasis on international events of world importance.

Candidates will also be expected to be familiar with cultural developments as reflected in contributions to civilization as a whole, in the fields of science literature and art.

17. General Economics.—Candidates will be expected to have a general knowledge of (a) the principles or economic analysis; and (b) the history of economic doctrines.

They should be able to apply their knowledge of theory to an analysis of the current economic problems of India.

18. Political Science.—Candidates will be expected to show a knowledge of political theory and its history, political theory being understood to mean not only the theory of legislation but also the general theory of the State. Questions may also be set on constitutional forms, (Representative Government, Federalism, etc.) and Public Administration, Central and Local. Candidates will be expected to have knowledge of the origin and development of existing institutions.

19. Philosophy.—The candidates will be expected to be familiar with History and Theory of Ethics, Eastern and Western, with special reference to the problems of Moral Standards and their application, Moral Judgement, Determinism and Free Will, Moral Order and Progress, relation between Individual, Society and the State, theories of Crime and Punishment, and relation of Ethics to Religion.

They will also be expected to be familiar with History of Western Philosophy, with special reference to nature of Philosophy and its relation to Science and Religion, theories of Matter and Spirit, Space and Time. Causation and Evolution, and Value and God, and with History of Indian Philosophy (including orthodox and heterodox systems), with special reference to theories of God, Self and Liberation, and Causation, Evolution and Appearance.

20. Psychology.—

Psychology : Its nature, scope and methods; experimental methods in psychology.

Factors in human development—heredity and environment.

Motivation, feelings and emotions; their nature and development; theories of emotions; development of character.

The cognitive processes, sensation, perception, learning, memory and forgetting, and thinking.

Intelligence and abilities—concepts and measurement; Personality—nature, determinants, theories, and assessment.

Group processes and group effect; crowd behaviour; leadership and morale; attitudes and prejudice; social change.

Concept of abnormality; symptoms and etiology of the main forms of psychoneurotic and psychotic disorders; social pathology and juvenile delinquency—cause and prevention; Main forms of therapeutic techniques.

21. Law.—Constitutional Law of the Republic of India and the United Kingdom, Jurisprudence, Torts, Indian Law of Contract, Indian Evidence Act, Indian Penal Code.

22. Public International Law.—

Nature and Sources of International Law. History of International Law. The School of International Law. International Law and Municipal Law.

States as persons of International Law. Acquisition and loss of international personality. State recognition. State succession.

Rights and duties of States. Principle of equality. Jurisdiction of States.

Treaties.

Agents of International intercourse. Privileges and immunities of diplomatic agents. The individual and international Law. Aliens. Nationality. Naturalisation. Statelessness. Extradition. War Criminals.

Modes of settlement of International disputes.

War : Declaration : effects.

Laws of Land, sea and aerial warfare.

War in self-defence. Collective security. Regional pacts. Outlawry of war. Laws of belligerent occupation. Belligerency and insurgency.

Methods of warfare. Prisoners of war. Right of visit and search. Prize courts.

Blockade and contraband.

Neutrality and neutralisation. Rights and duties of neutral states in war. Unneutral service. Neutrality under the Charter of the U.N.

The Charter of the U.N. and covenant of the League of Nations. Principal organs of the United Nations. Specialised International Organisations.

Candidates will be expected to show familiarity with cases including the pronouncements of the International Court of Justice.

23. *Mercantile Law.*—The main principles of the law relating to :

Agreements.

Contracts.

Bailment.

Pledge.

Sale of Goods.

Agency.

Partnership.

Indemnity and Guarantee.

Negotiable Instruments.

Company Law and Liquidation of Companies.

Life, Fire, Marine Insurance.

Common Carriers and Carriage of Goods by Land, Sea and Air.

Insolvency.

24. *Advanced Accountancy and Auditing.*—

Accounts relating to.—Partnership, Joint Stock Company, Amalgamation, Absorption and Reconstruction, Holding and Subsidiary Companies, Insolvency, Liquidation, Double Accounts system, Hire Purchase and Instalment Systems, and Non-trading organisations, Branch Accounts, Bank Accounts, Contract Accounts, Insurance Accounts, Royalty Accounts, Criticism of Published Accounts, Problems relating to Goodwill, Depreciation and Reserves, etc.

Cost Accounts.—Aims and objects of costing. Principal systems of ascertaining costs for different types of industries and their characteristics. Methods of apportionment of *on cost*, Treatment and Control of Materials, Stores and Stocks. Treatment of wages and other expenses. Pricing of Stores and Stocks, Forms of Cost Ledger, Stores-Ledger, Purchase Journal, Stores Requisition Note, Goods Received Book, Bin Card, Time Sheet Wages Summary, Cost Sheet and other necessary rulings, Ascertainment of Cost and ex-Works Price under Controlled Economy. Practical Problems relating to Cost Accounting.

Principles and procedure of auditing.—Audit of Firms, Joint Stock Companies and Public Utilities. Rights, Duties and Liabilities of Auditors, Internal Check, Auditor's appointment and qualifications. Auditor's Report, Investigation and their conduct. Divisible Profits and Dividends. Legal decisions relating to audit matters, problems relating to audits.

Income-tax.—Application of Income-tax Act and exemptions. Income-tax authorities. Heads of income and their assessment. Previous year, Assessment year, Depreciation. Free of tax and Less Tax. Set-off. Computation of Total Income and tax payable by assesses. Assessment of Individuals, Firms, Joint Stock Companies, Hindu undivided family. Association of persons. Assessment of new business and discontinued business. Method and principles relating to assessment to super-tax. Practical problems.

25. *Applied Mechanics.*—

BUILDINGS

Consideration of materials used in the construction of roof-trusses. Steel and Timber. Determination of stresses in trusses by various methods. Dead-loads and wind pressure. Factors of safety and working stresses.

Design of roof-trusses. Various types of roof-trusses and roof coverings; collar beam and hammer beam trusses.

Use of Euler's, Gordon's, Rankine's, Fidler's Johnson's and straight line formulae in the design of struts. Buckling factor of struts; curves showing comparative strength of struts obtained by various formulae. Choice of size of sections. Finish of steel work. Joints. Design of end-bearings; methods of fixing and supporting ends.

Application of circles and ellipse of stress and Clayeyron's theorem to design of structures.

Cast Iron and Steel columns.—Flange and web connections to steel Columns; caps; bases; transverse bracing of columns.

Foundations.—Safe pressures; foundations for columns. Slab foundations, cantilever foundations; grillage foundations. Wells. Piles.

Retaining Walls and Earth Pressures.—Rankine's theory, Wedge theory, Winkler's and Bligh's graphical constructions, with corrections. Design of various types of retaining walls in masonry.

Tall Masonry and Steel Chimneys.—Theory and design.

Design of steel and Masonry Reservoirs; with considerations of wind-pressures.

Deflection of framed structures and determination of stresses etc., in redundant frames.

Influence diagrams for bending moment and shear for uniformly distributed and irregular loads on trusses, built in beams, and three pinned parabolic; semi-elliptic and semi-circular arches.

General principles of dome design.

Principles of Building Design; consideration of loads on buildings; Steel-works, girders, etc., for buildings.

BRIDGES

Design of superstructure. Determination by graphical and analytical methods of bending moment due to moving loads, wind pressures.

Design of masonry bridges and culverts.

Plate-webb girders. Analysis of stresses.

Warren and lattice girders.

Three pinned arches; doubly pinned and rigid arches.

General considerations on the design of suspension, cantilevers and tubular bridges.

Steel arched bridges.

Swing bridges.

REINFORCED CONCRETE

Shear, bond and diagonal tension, its nature, evaluation and location of reinforcement.

Design of simple and doubly reinforced beams and continuous beams.

Theory and design of reinforced concrete columns and piles.

Design of slab foundations.

Design of simple cantilever and counterfort retaining walls.

Equivalent moments of inertia for reinforced concrete sections.

Theory of elastic deflections and outline of investigation of stresses in reinforced concrete arches.

GENERAL

Analysis of stress, analysis of strain, elastic limit and ultimate strength. Relation between the elastic constants. Lannhardt-Weyrauch formula for working stresses in a structural member and determination of its cross sectional area. Repetition of stresses. Bending moment and shearing force diagrams for dead loads. Graphical determination of stresses in frames; effect of wind pressure; method of sections. Stress in the cross-section of a beam due to bending ($M/I \cdot F/Y \cdot E/R$); compound and conjugated stresses. Rankine's theory of earth-pressure; depth of foundations strength of footings. Grillage foundations; Coulomb's theory of earth-pressure; modification due to Rebahn.

Bending moment and shearing force diagrams for live loads. Analysis of uniform and uniformly varying stresses; Elastic theory of bending of beams; bending and shear stresses in beams. Modulus of section and equivalent areas. Maximum and minimum stresses in a joint due to eccentric loading.

Stresses in dams and chimneys. Stability of block, work structures. Design of rivetted joints and stresses in boiler shells. Ruler's theory concerning struts, modifications due to Rankine, Gordon and others. Torsion, Combined torsion and bending deflections. Encastre beams. Continuous beams and theorem of three moments. Elastic theory of arches. Masonry arches.

PART C

[Vide Sub-Section (c) of Section II of Appendix II]

1(a) Higher Pure Mathematics.—

Infinite Series and Products

Tests for Convergence. Absolute, conditional and uniform convergence of infinite (real and complex) series. Differentiation and integration of infinite (complex) series. Fundamental properties of power series. Double series. Absolute and uniform convergence of infinite products.

Analysis—

Functions of a Real Variable. Dedekind's Section. Bounds and limits of sequences. Continuity and properties of continuous functions. Rolle's Theorem. Taylor's Theorem. Maxima and Minima of functions of two or more variables. Differentiability and differentials. Implicit functions. Properties of Jacobians. Riemann Integration. Mean Value Theorems. Differentiation and Integration under the integral sign. Improper integrals. Double, triple and surface integrals. Green's and Stokes' Theorems. Fourier's expansions of functions. Sum of the series at points of discontinuity. Sets of points. Measure. Measurable functions. The Lebesgue integral of a bounded function.

Functions of a Complex Variable. Bilinear transformations. Analytic functions. Cauchy's Theorem and its converse. Cauchy's integral formula. Taylor's and Laurent's series. Liouville's Theorem. Singularities. Zeros. Theory of Residues. Application to contour integration and the roots of algebraic equations. Conformal representation. Analytic continuation. Mittag-Leffler's Theorem. Weierstrass's factorisation Theorem. The maximum-modulus principle. Hadamard's three-circles Theorem.

Advanced Geometry

Plane Sections and Generating lines of Quadrics. The Quadric surface and its analysis. The circle at infinity. Confocal quadrics. Elementary theory of Pencils of Quadrics.

Curves in Space. Curvature and torsion. Frenet's formulæ. Envelopes. Developable Surfaces. Developables associated with a curve. Rules Surfaces. Curvature of surfaces. Lines of Curvature. Conjugate lines. Asymptotic lines. Geodesics.

1(b) Higher Applied Mathematics.—

Statics, including Attractions and Potentials.

Hydrostatics—Fluid pressure. Atmospheric pressure. Capillarity.

Particle Dynamics—Central orbits. Constrained motion. Motion in a resisting medium. Motion in three dimensions.

Rigid Dynamics—Motion in two dimensions. Momentum and vis-viva. Lagrange's equations of motion and their application to small oscillations.

Hydrodynamics, including the elementary theory of the motion of solids through a liquid, and surface waves.

Electricity and Magnetism.

Thermodynamics, Kinetic theory of gases. Radiation.

2. Higher Physics.—

General Properties of Matter and Sound. Mechanics of deformable bodies. Helical springs. Capillary phenomena. Viscosity. Acoustical measurements. Ultrasonics.

Heat and Thermodynamics. Brownian motion. Kinetic theory of gases, Transport phenomena in gases at low pressures. Thermodynamic functions and their applications. Specific heat of solids and gases. Production and measurement of low temperatures. Radiation and Planck's law of energy distribution.

Optics. Theory of co-axial symmetrical optical systems. Experimental spectroscopy. Electro-magnetic theory. Scattering of light. Raman effect. Diffraction. Polarisation.

Electricity and Magnetism. Gauss's theorem. Electrometers. Magnetic hysteresis. Theory of permanent magnets. Measurement of electrical quantities. Alternating current theory.

Cyclotron and other methods for production of high voltages. Transmission and reception of wireless waves. Television.

Modern Physics. Special theory of relativity. Dual nature of light and matter. Schroedinger's equation and its solution in simple cases. Hydrogen and helium spectra. Zeeman and Stark effects. Pauli's principle and periodic classification of elements. X-Rays and X-Ray spectroscopy. Compton effect. Conduction in metals. Supraconductivity. Thermionics. Thermal ionization. Properties of atomic nuclei. Mass spectroscopy. Elementary particles and their properties. Nuclear reactions. Cosmic rays. Nuclear fission and fusion.

3. Higher Chemistry.—

Inorganic Chemistry.—The structure of the atom. Radioactivity, natural and artificial. Fission and fusion of nuclei. Isotopes. Radioactive indicators. Radioactive series. Transuranic elements.

Chemistry of the elements and their principal compounds, with special reference to Be, W, Ti, V, Mo, Hf, Zr and rare earth elements.

Co-ordination compounds. Interstitial and non-stoichiometric compounds. Free radicals. Advanced Physico-chemical methods of analysis.

Organic Chemistry.—Theories of organic chemistry, including resonance and hydrogen bond formation. Mechanism of important organic reactions. Stereochemistry, including conformation.

Chemistry of different classes of organic compounds, with special reference to the following: Polysaccharides, terpenes, natural colouring matters, alkaloids, vitamins, important hormones, anti-malarials, chlorine insecticides, principal antibiotics, and synthetic polymers.

Physical Chemistry.—The kinetic molecular theory. The three laws of thermodynamics and their application to physical chemical processes. Physico-chemical properties in relation to and elucidating molecular structure. Quantum theory and its application to chemistry.

The mechanism and kinetics of chemical and photochemical reactions. Catalysis. Adsorption. Surface chemistry. Colloids. Electrochemistry.

4. Higher Botany.

Plant kingdom.—Advanced knowledge of the main groups of the vegetable kingdom both living and extinct (viz. Algae, Fungi, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms) with special reference to the Indian flora.

Systematic botany—Principles of classification and a general knowledge of the more important families of angiosperms.

Anatomy.—Origin, nature and development of plant tissues and their distribution from the ecological and physiological points of view.

Plant pathology.—An advanced knowledge of the important diseases of plant caused by bacteria, fungi, viruses, and physiological diseases. Methods of control.

Physiology.—An advanced knowledge of the important physiological processes in plant, including plant biochemistry.

Ecology.—Principal types of vegetation of India, their distribution and the importance of eco-physiological studies. Principles of plant geography.

Economic botany.—A study of the important economic plants of tropical and sub-tropical areas, with special reference to India.

General Biology.—Knowledge of the fundamentals of and recent developments in variation, heredity evolution, cytology, genetics and principles of plant breeding.

5. Higher Zoology.

The classification, bionomics, morphology, life-history and relationships of non-chordates and chordates, with special reference to Indian fauna.

Functional morphology (form, structure and function) of the organ systems. Outlines of vertebrate embryology.

The classification, ontogeny, phylogeny, adaptive divergence and convergence of animals, animal ecology, migration & colouration.

Evolution: evidences, theories and their modern interpretations. Adaptation; distribution of animals in space.

Recent advances in the knowledge of the cell, cytology, genetics, sex determination, and endocrinology.

Modern concept of the environment as a complex of physical chemical and biological factors, and of the organisms as individuals, populations and communities.

An essay relating to any of the following topics: Protozoa and disease; Insect and man; Parasitology. Freshwater and marine biology; Limnology and fishery biology; Contribution of great biologists to knowledge and civilization.

6. Higher Geology.

General Geology.—History and development of the Science of Geology, its different branches and contacts with other sciences. Origin, evolution, structure, constitution, interior and age of the Earth. Geomorphology; Radioactivity and its applications to Geology; Seismology; Volcanology; Geosynclines; Isostasy. Evolution of continents and ocean basins. Geological action of surface and subterranean agencies. Continental drift.

Structural and Field Geology.—Diastrophism; Rock deformation; Origin of mountains; Structures in relation to topography and mining. Tectonic history of India. Methods of Geological Surveying and Mapping.

Stratigraphy and Palaeontology.—Principles of Stratigraphy, and correlation. Details study of Indian Stratigraphy and outline of World Stratigraphy. Distribution of land sea, faunas and floras in different periods. Theories of organic evolution. Fossils—their importance. Index fossils and correlation. Detailed study and geological history of the invertebrate fossils and the principal groups of vertebrate and plant fossils with special reference to India.

Cr. " " " Mineralogy.—Crystal morphology; Laws " " " crystal systems and classes; habits; twinning " " " and X-ray study of crystals. Atomic structure. Detailed study of rock-forming minerals and of economic minerals with special reference to their occurrence in India.

Petrology.—Origin and evolution, structure, mineral constituents, texture and classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Petrogenesis including metamorphism. Petrochemistry. Study of meteorites. Important Indian rock types.

Economic Geology.—Ore-genesis; classification of economic minerals and controls of ore localization. Geology of economic mineral deposits with particular reference to India. Location of mineral industries. Evaluation of properties; Mineral economics; conservation and utilisation of minerals. National mineral policy. Strategic minerals. Geological, geophysical and geochemical prospecting techniques and their applications. Principal methods of mining, sampling, ore dressing and ore beneficiation. Soils and ground water. Application of Geology to common engineering problems.

7. Higher Geography.—The paper will consist of two parts :—

The first part will comprise an advanced study of Physical, Human and Economic Geography, with special reference to India.

The second part will comprise advanced study of the following special subjects, and a candidate will be expected to have knowledge of at least two of these subjects :

Geomorphology. Climatology (including modern methods of weather forecasting and analysis). Cartography (including solution of right-angled spherical triangles, use of Theodolite, advanced projections like the oblique zenithal nets, etc.) Historical geography. Political geography. History of geographical thought and discoveries.

8. *English Literature (1798—1935).*—The paper will cover the study of English Literature from 1798 to 1935, with special reference to the works of Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Lamb, Jane Austen, Carlyle, Ruskin, Thackeray, Robert Browning, George Eliot, G. M. Hopkins, Shaw, W. B. Yeats, Galsworthy, J. M. Synge, F. M. Foster and T. S. Eliot.

Evidence of first hand reading will be required. The paper will be designed to test not only the knowledge but also critical evaluation of the main literary trends during the period. Questions having a bearing on the social and cultural background of the period may be included.

9. (a) Indian History I (From Candragupta Maurya to Harsha).

The Mauryas. The rise and consolidation of the empire. Administration and economy. Decline of the empire.

The eclipse of Magadha. The Shungas and the Kanvas.

The Cholas, Cheras, and Pandyas.

Contacts with the West. North India—the Indo-Greeks. South India—Roman trade.

Central Asia and India. The Shakas. The Kushanas.

The Satavahanas.

Indian contacts with Asian countries—The spread of Buddhism.

The Imperial Guptas—The Creation of Classical Indian Culture. Further Indian contacts overseas. The decline of the Guptas. The Hunas.

Changing economic patterns in north India and their impact on politics.

The rise of the Vakatakas and the Chalukyas.

The emergence of the Pallavas.

Harshavardhana.

9. (b) Indian History II [The Great Mughals (1526-1707)]—

Political History.

Establishment of the Mughal Empire in India; its consolidation and expansion. The Sur interregnum. Mughal Empire at its zenith. Akbar, Jehangir & Shahjahan. Mughal relations with Persia and Central Asia. The development of administrative system. Europeans at the Mughal Court; early Portuguese, French and English settlements. The beginning of the decline. Aurangzeb, his wars and policies.

Cultural, Religious, Economic and Social Life

Cultural life, and promotion of art, architecture and literature.

Religious movements : Bhakti Movement, Sufism, Din-i-Ilahi. Religious policy of the Mughal Emperors.

Economic life : Agrarian life, Systems of land tenure. Industry. Trade and Commerce. Exports, imports. Means of transport. Wealth of India.

Social life . Court life; Urban life; Rural life. Dress, manners, customs, food and drink; amusements, recreations and festivals. Position of women.

9. (c) Indian History III (From 1772 to 1950).

Consolidation of British power in Bengal and South India. Expansion of British power in India. The East India Company and the British state. Evolution of the Civil Service, Judicial system, the police, and the army. Development of new land revenue systems and agrarian relations. British commercial policy. Economic impact of British rule in India. The Revolt of 1857. Relations with Indian States. Foreign policy, and relations with Burma and Afghanistan. Development of modern industry, and means of communication. Development of modern education. Growth of the Press.

Indian Re-awakening : Raja Rammohan Roy, Brahmo Samaj, and Vidya Sagar; the Arya Samaj; the Theosophists; Ramakrishna and Vivekananda; Sayyed Ahmed Khan. Social Reform. Development of modern Indian literature. The rise of Indian National Movement : The Indian National Congress (1885-1905), Dadabhai Naoroji, Ranade, and Gokhale; Growth of militant nationalism, anti-partition agitation. Swadeshi and Boycott, Tilak and Aurobindo Ghosh; the Home Rule League and the Lucknow Pact.

Constitutional Development : Acts of 1861 & 1892; Minto-Morley Reforms; the Montford Reforms, the 1935 Act.

Emergence of Mahatma Gandhi and the struggle for freedom. Transfer of Power : The Cripps Missions; the Cabinet Mission; Independence Act and Partition. The Constitution of 1950. Independent India : Foreign Policy, Non-alignment; Secularism; and Planning.

9. (d) British Constitutional History (From 1603 to 1950)—

Crown versus Parliament.

Relations between James I and Parliament. Petition of Rights. Charles I and the issue of prerogative versus common law. Civil War.

The Constitution makers.

Government by Long Parliament. The Little Parliament. The Protectorate. The Restoration. The Glorious Revolution. The Bill of Rights.

The Crown, the Executive and Parliament.—

The King and his Ministers. Influence of the Crown. The Cabinet and Parliament. The Monarchical Crisis of 1936.

The Reform of Parliament.—

Reform Acts and the House of Commons. The House of Commons and the House of Lords. The Reform of the House of Lords.

The Commonwealth.—

Origin and growth of the Commonwealth. The Statute of Westminster. The Machinery of Commonwealth Co-operation. The position of the Crown in the Commonwealth.

9. (e) *European History (1871-1945).—*

The Industrial Development of Europe—Growth of nationalism, and democratic and socialist movement.

The German Empire; the Third French Republic; the Habsburg Monarchy; Imperial Russia.

The policy of alignments and ententes.

The Eastern Question.

The rise of imperialism, and European imperial interests in the Near East, the Middle East, Africa and the Far East.

The origin and consequences of the First World War.

The Russian Revolution and its consequence.

The Versailles settlement; the League of Nations; efforts at World Disarmament; the March for the abolition of Fascism and Nazism and their international consequences.

The Second World War.

10. (a) *Advanced Economics.—*

Functions of economic analysis.

The theory of price. The theory of consumption and demand. Organization of production. Theory of the firm and industry. Imperfect competition. Theory of monopoly. Control of monopoly.

The theory of distribution. Rent. The theory of capital. The theory of money and interest. Savings and investments. Banking and credit regulation. The theory of wages and employment. Collective bargaining and industrial peace.

National income. Economic progress and distributive justice.

The theory of international trade. Foreign exchanges. Balance of payments.

Business cycles and their control. Economic role of Government. Economic welfare. Public utilities, pricing and regulation.

Theory of taxation. Incidence of taxation. Effects of Government taxation and expenditure. Deficit financing and inflation.

Planning for economic development.

10. (b) *Advanced Indian Economics.*

Economic developments during the War and Post-War period. Natural resources. Social institutions. Agricultural production and finance. Pricing and distribution of food grains and other agricultural products. Land reform. Place of cottage and small scale industries in a developing economy. Growth of modern organized industry. Regulation of public companies. Industrial relations and problems of labour. Mixed economy. Scope and efficiency of the public sector. Indian monetary and credit system. Role of the Reserve Bank. Population problems and population policy. Unemployment and under-employment. Computation of Indian national income. Regulation of foreign trade. Balance of payments. Indian taxation system. Federal finance. Planning for economic development. Size and structure of successive plans. Problems of resources and of implementation.

11. (a) *Political Theory from Hobbes to the Present Day.*

Theories of Contract and Natural Rights—Hobbes, Locke and Rousseau. Development of the Idea of Sovereignty. The Historians—Vico, Montesquieu and Burke. The Utilitarians. The Evolutionists. The Idealists—Kant, Hegel, Green, Bradley and Bosanquet. Conservatism and Liberalism. Marxism and Schools of Socialism and Communism. Pluralism. Fascism. The Impact of Psychology. Trends in twentieth century thought in the East.

11. (b) *Political Organisation and Public Administration.*

Political Institutions. The rise of Modern National States. Parliamentary and Presidential forms of Government. Unitary and Federal Governments. The Legislature. The Executive and the Judiciary. Methods of Representation. The Communist and Totalitarian forms of Government.

Public Administration. Public Administration in the Modern State. The formulation of policy and higher control—the Legislature and the Executive. Organization, Management, Methods and Tools. Regulatory Commissions and Public Corporations. Personnel Administration—The Civil Service and its Problems. The Budget and Financial Administration. Administrative Powers. Control by the Courts. The Public Services and the Public.

11. (c) *International Relations.**Part I*

Foundations and limitations of national power.

The place of power, ideology and ethics in International Relations.

The role of International Law in International Relations.

The role of national interest in the formulation of foreign policy.

The theory of Balance of Power.

The nature and functions of International Organisation.

The United Nations: purposes, structure and functioning.

Part II

The origins of the First World War and the nature of the peace Settlement.

The League of Nations and the efforts for the establishment of a collective security system in the inter-war years.

The origins of the Second World War.

The Nuclear age and its impact on traditional International Relations.

The Cold War and its effect on World Politics.

The Birth of New Nations and the changes in the pattern of International Relations.

The Foreign Policies of the United States, the U.S.S.R., China, India and one of the following:

Great Britain, Japan, Germany and France.

12. (a) *Advanced Metaphysics Including Epistemology.*—Candidates will be expected to be familiar with the views of prominent philosophers from Kant to the present day, e.g., Kant, Hegel, Bradley, Royce, Croce, Moore, Russell, James, Schiller, Dewey, Bergson, Alexander, Whitehead, Wittgenstein, Ayer, Heidegger and Marcel.

Questions may be set on any of the following topics:—

The sources, materials, varieties, limits, criteria and sociology of knowledge.

Truth, falsehood, error.

Theories of reality. Reality, subsistence and existence. Monism, dualism and pluralism. Naturalism, agnosticism, theism, absolutism and mysticism. Post-Hegelian idealism. New realism. Radical empiricism. Pragmatism.

Instrumentalism. Humanism—naturalistic and religious.

Logical positivism. Existentialism—atheistic and theistic. Recent trends of the philosophy of science in regard to the problems of induction, laws of nature, relativity, indeterminacy and God.

12. (b) *Advanced Psychology including Experimental Psychology.*

Subject-matter, scope and methods of psychology; its relation with other sciences.

Heredity and environment controversy—Experimental studies on the relative influence of the two on human development.

Problems of motivation, and emotion. Frustration and conflict; types of conflict; defence mechanisms—Studies in expressive movements; P.G.R., lie detection.

Sensation and Perception—Psychophysical methods; space perception, factors of perceptual organization; role of dynamic, personality and social factors; interpersonal perception.

Experimental methods in the study of learning, memory, forgetting and thinking—Theories of learning and forgetting; theories of sign-process—nature of meaning.

Psychology of personality—determinants, traits, types, dimensions, and theories; assessment of personality—behavioural measures of personality—rating scales, nominating techniques, questionnaires and inventories, attitude scales, projective tests.

Individual differences : nature and measurement of intelligence and aptitudes. Test construction—Item analysis. Test scales and norms—Reliability and validity of measures—Factor analysis—Theories.

Schools and systems of psychology—Traditional Schools and the main contemporary systems of psychology; Freudians, neo-Freudians, neo-Behaviourists, Gestalt and field theories.

13.(a) Constitutional Law of India.

Historical Background : The growth of the Indian Constitution with special reference to the development of representative and responsible Government from the Indian Councils Act of 1861 down to the Indian Constitution of 1950.

General Features : Welfare State Ideal; Preamble to the Indian Constitution and Directive Principles of State Policy : Concepts of Unitary and Federal Government, Cabinet System, Due Process of Law, Judicial Review, Constitutional Conventions; Comparison of the Salient Features of the Indian Constitution with those of the U.K., the U.S.A., Canada and Australia.

Division of Powers : Theory of separation of powers.

The Legislature.—Legislative procedure; Privileges of Legislature; Delegation of legislative power.

The Executive.—Presidential and Parliamentary Executives; Provisions relating to Services and Public Service Commissions; The doctrine of Rule of Law.

The Judiciary.—Judicial control of administrative and quasi-judicial authorities; Scope of Writ Jurisdiction; Independence of the Judiciary.

Distribution of Legislative Powers : Principles of distribution of powers with special reference to Treaty Power, Commerce Power, Taxing Power, Constituent (Constitution-Amending) Power and Residual Power. Judicial doctrines relating to distribution of powers.

Fundamental Rights : Nature and scope of the various fundamental rights guaranteed under the Constitution.

Note : Candidates will be expected to be conversant with the text of the Indian Constitution, amendments thereto, and leading decisions of the Supreme Court.

13.(b) Jurisprudence.

Jurisprudence : Definition and scope; various Schools of Jurisprudence; Concepts and doctrines regarding Sovereignty.

Law : Law and Morals; Evolution of Law; Law of Nature. Law of the State; Imperative theory of Law; Pure theory of Law; Sociological theory of Law; Kinds of Law; Civil Law, Criminal Law; Substantive Law and Adjective Law : Private Law and Public Law; International Law; Law and Justice; Law and Equity; Justice according to Law; Administration of Justice.

Sources of Law : Customs, Judicial Precedent. Legislation; Codification.

Elements of Law : Analysis and classification of Juristic concepts : Personality; Right, Duty, Liberty, Power, Immunity, Disability; Status, Possession, Ownership; Lease, Trust, Easement, Security; Wrong, Liability, Obligation; Act, Intention, Motive, Negligence; Title : Prescription; Inheritance and Wills.

Evolution of Legal Concepts : Evolution of Contract, Tort, Crime, Property, and Wills. Current trends in Juristic thought.

14.(a) *Medieval Civilisation as Reflected in Arabic Literature* (570 A.D.—1650 A.D.).—The paper will test the candidate's knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments.

14. (b) *Medieval Civilisation as Reflected in Persian Literature* (570 A.D.—1650 A.D.).—The paper will test the candidate's knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments.

14. (c) Ancient Indian Civilisation and Philosophy.

The history of the Civilisation, Philosophy and Thought of India from 2000 B.C. to 1200 A.D.

Note.—The paper will test the knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments. Questions may be set which require an acquaintance with archaeological discoveries.

15. Anthropology.

(A) *Physical Anthropology*.—Definition and scope. The relation of Physical Anthropology to other sciences. The evolution of Man, his exact place among the Primate Group—his relationship to Prehuman and Protohuman forms from Parapithecus to Australopithecus. Early types of Man—Palaeolithic man—Pithecanthropus. Synanthropus and Neanderthal. Neanthropic man—Cro Magnon, Grimaldi and Chancelade—Homo Sapiens.

Racial differentiation of Man and bases of racial classification—Morphological, serological and genetic. Role of heredity and environment in the formation of Races. Principles of human genetics—Mendelian laws as applicable to Man.

Human Biology—The effects of nutrition, inbreeding and hybridisation.

History of distribution of Man in India from the lithic ages to the Indus Valley civilization and Megalithic cultures of Central and Southern India. Racial types and their distribution in India.

(B) *Social (Cultural) Anthropology*.—Scope and functions. Relation with Sociology, Social Psychology and Archaeology. Different schools of Cultural Anthropology—Evolutionary, Historical, Functional and Kultur Kreis. The structure and development of Human society.

Economic organisation—Early stage of hunting and food gathering, domestication of animals, agriculture, shifting cultivation, terracing intensive cultivation, implements used.

Political Organization—Clan, tribe, and dual organization, tribal council, function of headman or chief.

Social Organization—Marriage and kinship forms. matriarchy, patriarchy, polygyny, polyandry, exogamy and endogamy. Position of women, inheritance and divorce.

Primitive religion—Totemism, Taboo, magical and fertility rites, head hunting and human sacrifice.

Art, Music, Folk dance and sports.

Group relationship, adjudication of disputes, concept of justice and punishment.

Intelligence level, special aptitudes and abilities, emotional needs underlying primitive behaviour and ethnocentrism.

Structure of personality and development of personality and its role in primitive society.

Acculturation and the effects of contact on primitive tribes. Depopulation and its causes. Economic and psychological frustration. Decline of primitive tribes in America, Africa and Oceania. Depopulation among Indian tribals and remedial measures.

(C) *Intensive study of any one of the ethnic divisions of tribal India* :

1. The tribes of the N.E.F.A. or North Eastern Frontiers of India.
2. The tribes of the Naga Hills—Tewansang Area.
3. The autonomous tribes of Assam—the Khasis, the Garos, Mikirs and the Lushai.
4. The Australoid tribes of Chotanagpur and Central India.
5. The tribes of Southern India including the tribes of the Nilgiri Hills.
6. The tribes of the Andaman and the Nicobar Islands.

Note.—Candidates will be required to answer questions on (C) and (A) or (B).

16. Sociology.

Scope of Sociology, Relations with the social and natural sciences. Methods.

Origins of Society, Primitive life, Stages of social evolution, Social heritage; its mechanisms. Orders of environment. Types of behaviour.

Social Structure, Groups, Institutions, Association, Family, Marriage, Status, Class, Community, Herd and Crowd, Occupation, Property, Personality, Culture and Civilization, Myths

and Legends, Language and Speech, Race Contracts and their types, States, Morals and their evolution. Habits, Customs, Mores and Folkways.

Social Change. Technological, economic, demographic forces.

Psychological factors, Interaction, imitation, diffusion. Cultural factors. Role of ideas. Leadership. Laws of social change and social selection.

Social Processes, Competition. Differentiation. Collectivisation. Types of Conflict. Distribution of wealth, social ecology.

Social maladjustment, Mass culture, City and Village, Crime. Social Evils.

Social Control. Agencies. The State and the Law. Welfare State. Religion. Art. Education. Public opinion and Propaganda.

Social Planning, its principles, Indian conditions, Social Work and Welfare.

Social Security, Purpose and Progress.

History of Social Thought. Materialistic and Sociological schools, Indian contribution in the light of Indian Culture.

Elementary Social Statistics. Techniques of Social Surveys.

PART D

[Vide Sub-Section (B) of Section I of Appendix II]

Personality test.—The candidate will be interviewed by a Board who will have before them a record of his career. He will be asked questions on matters of general interest. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for the Service or Services for which he has applied by a Board of competent and unbiased observers. The test is intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also social traits and his interest in current affairs. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate.

3. The personality test is not intended to be a test either of the specialised or general knowledge of the candidates which have been already tested through his written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subject of academic study but also in the events which are happening around them both within and without their own state or country, as well as in modern currents of thought, and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this Examination.

1. **Indian Administrative Service.**—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may

exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Administrative Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000 (18 years).

Senior Scale :

(i) *Time Scale.*—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—50—1,600—50—1,800 (22 years).

(ii) *Selection Grade.*—Rs. 1,800—100—2,000.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2,150 and Rs. 3,500 to which Indian Administrative Service Officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will start on the junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) *Leave.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955.

(i) *Medical Attendance.*—Officers of the Indian Administrative Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

2. **Indian Foreign Service.**—(a) Appointment will be made on probation for a period which will not ordinarily exceed 3 years. Successful candidates will be required to pursue a course of training in India for approximately twenty months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Missions whose languages are allotted to them as compulsory languages. During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examinations before they become eligible for confirmation in Service.

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed examinations, the Probationer is confirmed in his appointment. If, however, his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service, Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(d) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000.

Senior Scale.—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 1,800 and Rs. 3,500 to which I.F.S. Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation :—

First Year.—Rs. 400 per mensem.

Second Year.—Rs. 400 per mensem.

Third Year.—Rs. 500 per mensem.

NOTE 1.—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

NOTE 2.—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed tests, if any, and showing progress to the satisfaction of Government. Increments can also be earned in advance by passing the departmental examinations.

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India.

(g) During Service abroad I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment. In addition, the following concessions are also admissible to I.F.S. officer during service abroad :—

- (i) Free furnished accommodation according to status.
- (ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.
- (iii) Return air passage to India up to a maximum of two, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.
- (iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions.
- (v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.
- (vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted at various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules. Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.
- (vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad.

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For Service abroad I.F.S. Officers are entitled under the I.F.S. (PLCA) Rules, 1961, to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(i) *Provident Fund*.—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits*.—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Government servants of equal and similar status.

3. *Indian Police Service*.—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine.

- (b) } As in clauses (b), (c) and (d) for the Indian
(c) }
(d) } Administrative Service.

(e) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (18 years).

Senior Scale.—Rs. 740 (6th year or under)—40—1,100—50/2—1,250—50—1,300. (22 years).

Selection Grade.—Rs. 1,400.

Deputy Inspector General of Police.—Rs. 1,600—100—1,800.

Commissioners of Police, Calcutta and Bombay.—Rs. 1,800—100—2,000.

Inspector General of Police.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

Director Intelligence Bureau.—Rs. 2,750.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

- (g) }
(a) } As in clauses (g), (h), (i) and (j) for the Indian
(i) } Administrative Service.
(j) }

4. *Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II*.—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories. He may also be required to serve in any police/intelligence organisation of the Government of India.

(e) Scales of Pay :—

Grade I.—Selection Grade.—Rs. 900 fixed.

Grade II.—Time scale.—Rs. 300—25—475—EB—25—650—EB—30—800.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are at present entitled to get dearness allowance at the rates admissible to officers of comparable status employed under the Government of Punjab.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places, either for training or on duty, where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

5. *The Central Information Service, Grade II (Class 1)*.—

(a) The Central Information Service consists of posts all over India, in various media organisations of the Ministry of Information and Broadcasting, requiring journalistic and similar professional qualifications with previous experience of work on a newspaper or news agency or publicity organisations. The service was constituted with effect from 1st March, 1960.

(b) The Service has at present the following grades :—

Grade	Scale of Pay
Class I	
Selection Grade	Rs. 2,250/- (fixed)
Senior Administrative Grade	
(Senior Scale)	Rs. 1,800—100—2,000.
(Junior Scale)	Rs. 1,600—100—1,800.
Junior Administrative Grade	
(Senior Scale)	Rs. 1,300—60—1,600.
(Junior Scale)	Rs. 1,100—50—1,400.
Grade I	Rs. 700—40—1,100—50-2-1,250.
Grade II	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.
Class II (Gazetted)	
Grade III	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.
Class II (Non-Gazetted)	
Grade IV	Rs. 270—10—290—15—410—EB—15—485.

(c) Direct recruitment is made to the percentage of vacancies, as specified below, in the following grades of the Service :—

Junior Administrative Grade (Junior Scale)	12½%
Grade I	25%
Grade II	50%
Grade IV	100%

The remaining vacancies in the above grades and also vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade (Senior Scale) and Grade III are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades.

(d) (i) Direct Recruits to Grade II will be on probation for two years. During probation they will be given training in the Indian Institute of Mass Communication, on a newspaper or news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting and at the National Academy of Administration. The total period of training will be about 15 months. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the training, they will have to pass the 'end-of-the-course-test' at the National Academy of Administration and first and second departmental tests at the Indian Institute of Mass Communication, which will include a language test. Failure to pass the departmental test during the training period involves liability to discharge from service or reversion to substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(ii) On the conclusion of period of probation Government may confirm the direct recruits in their appointments in accordance with the rules in force. If the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may be discharged from service or his period of probation extended for such period as the Government may deem fit. If his work or conduct is such as to show that he is unlikely to become efficient, he may be discharged forthwith.

(iii) Probationers shall start on the minimum of the time scale of Grade II. On passing the first departmental test, the pay of probationers will be raised to Rs. 450 in the scale of pay of Grade II of the Central Information Service. On passing the second departmental test, the pay will be fixed at the stage of Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless they have completed 4 years of service, subject to other conditions as may be found, necessary. In case any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(e) Government may require any member of the Service to hold for a specified period a post in the publicity organisation of a Union Territory.

(f) Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting.

(g) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Central Information Service will be treated like other Class I and Class II officers.

NOTE.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Central Information Service which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

6. Indian Audit and Accounts Service.

7. Indian Customs and Central Excise Service.

8. Indian Defence Accounts Service.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms, the constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Offices under the Central or State Government or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service require it in the cadres on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments may be borne.

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in or out of India.

(f) Scales of Pay :—

Indian Audit and Accounts Service :

Time Scale of I.A. & A.S.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Junior Administrative Grade.—Rs. 1,300—60—1,600.

Accountants General.—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

NOTE 1.—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A.S. and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—In the case of probationers who do not pass the End-of-the-Course Test at the National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450 shall be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or up to the date on which under the Department regulations, the second increment accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test again.

Indian Customs and Central Excise Service.

Time Scale :—

Superintendent of Central Excise.	Rs. 400—400—30—510— EB—700—40—1100—50/2—1250
Class I Assistant Collector of Central Excise	
Assistant Collector of Customs.	
Deputy Collector of Customs	Rs. 1,100—50—1,300—60 1,600.
Deputy Collector of Central Excise	
Additional Collector	
Appellate Collector.	
Collector of Customs	Rs. 1,800—100—2,000—125 —2,250.
Collector of Central Excise	

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of the Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his/her period of probation, Government may confirm the officer in his/her appointment or if his/her work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him/her from the service or may extend his/her period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) The Indian Customs and Central Excise Service, Class I carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

NOTE 1.—A probationary officer will start on the minimum of the time scale of pay of Rs. 400—400—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250, and will count his/her service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—An Officer on probation will not be allowed pay in the time scale above the stage of Rs. 400 unless he/she passes the prescribed departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—During the period of probation, an officer will be posted to Central Excise Department/Customs Department/Narcotics Department for departmental training and to the National Academy of Administration, Mussoorie for a Foundational Course training. At the end of the training at Mussoorie he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. He/she will have to pass part I and Part II of the Departmental Examination. On passing the 'end-of-the-course' test and one of the parts of the Departmental Examination, he/she will be granted a first advance increment raising his/her pay to Rs. 450. On passing both the parts of the Departmental Examination, he/she will be granted the second advance increment raising his/her pay to Rs. 480. His/her pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she has completed 4 years of service subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, a probationer does not pass the 'end-of-the-course' test at the Academy, his/her first advance increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second advance increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 4.—It should be clearly understood by the probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs & Central Excise Service, Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such change.

Indian Defence Accounts Service :

Time Scale :—

Rs. 400—400—450—480—510—EB—700—40—1,100—1,100—1,150—1,200—1,200—1,250.

Junior Administrative Grade.

Rs. 1,300—60—1,600.

Rs. 1,600—100—1,800 (Selection Grade).

Senior Administrative Grade.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Controller General of Defence Accounts.—Rs. 2,750 (fixed).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the time scale and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules in force from time to time; provided further that in the case of an officer who does not pass the end-of-the-course test at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment shall be postponed by one year from the date on which he would have drawn it on passing Part I of the Departmental Examination or up to the date on which the second increment accrues to him on passing Part II of the aforesaid examination, whichever is earlier.

9. *Indian Income-tax Service Class I.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forth with.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(c) Scales of Pay :—

Income-tax Officer, Class I.—

Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Assistant Commissioner of Income-tax.

Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600.

Commissioners of Income-tax.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(f) During the period of probation, an officer will undergo training at the National Academy of Administration, Mussoorie and the Income-tax Training College, Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. In addition, I & II departmental examinations will also have to be passed during the period of probation. On passing the end-of-the-course test and the I Departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs. 450. On passing the 2nd departmental examination, the pay will be raised to Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 4 years of service subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, he/she does not pass the end-of-the-course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—The officer on probation will not be allowed to pay above the stage of Rs. 400 unless he passes the departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 2.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Income Tax Service Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

10. *Indian Postal Service*.—(a) Selected candidates will be under training in this department for a period which will not ordinarily exceed two years. During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Time Scale :—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250 (Officers under training will draw pay in this time scale).

Directors of Postal Services : Rs. 1,300—60—1,600.

Postmaster-General : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2,500—125/2—2750.

Senior Members, Posts and Telegraphs, Board : Rs. 3,000.

(f) The probationers in the Indian Postal Service, Class I, would draw pay in the prescribed pay scale of Rs. 400—400—450—30—480—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the National Academy of Administration, Mussoorie, in a foundational course of training. At the end of training at Mussoorie, they will have to pass the 'end of the course test'. They will also have to pass the Departmental examination as prescribed under the Departmental Rules. On passing the 'end of the course test' and the Departmental examination, their pay will be raised to Rs. 480. On confirmation, if they are confirmed on completion of the probationary period of two years, their pay will be fixed at the stage of Rs. 480. Further regulation of their pay will, however, be determined by their position in the time scale.

In case, any of the probationers does not pass the 'end of the course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which, under the Departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service, Class I, which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

"(h) Selected candidates will be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad as required by Government."

11. *Indian Railway Accounts Service*.—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations.

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within three years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo a course of training at the Railway Staff College, Baroda, and to pass the test prescribed by the College authorities. The test in the College is compulsory and a second chance, in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officer is such that such a relaxation may be made. They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the test at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs, or one of the equivalent Examinations recognized by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund; as amended from time to time.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the leave rules for the time being in force as applicable to officers of Indian Railways.

The leave rules are, however, liable to revision in the light of the Pay Commission's recommendations. They will not be permitted to retain the present leave rules, if so decided by the Government.

(f) If for any reason not beyond his control, a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(g) If, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(h) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(i) Scales of pay :—

(a) Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700 (6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

(b) Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examinations within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as

the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

12. *Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II).*—(a) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be required to undergo such course of training as may be prescribed by Government."

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination.

(c) (i) If in the opinion of Government the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub-para (b) above, Government may, in its discretion, either discharge him from service, or if the circumstances of the case so warrant, extend the period of probation for such period not exceeding one year as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds out of which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed, or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(d) If no action is taken by Government under Sub-para, (c) above, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month, terminable on either side on the expiration of one calendar month's notice in writing, provided that the Officer shall have no claim to confirmation.

(e) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his probation, unless he has passed the departmental examination. An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing of the departmental examination.

(f) In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) The scales of pay are as under :—

Administrative Posts

- (i) Director Military Lands and Cantonments. Rs. 1,800—100—2,000—125—2250.
- (ii) Joint Director, Military Lands and Cantonments. Rs. 1,600—100—1,800.
- (iii) Deputy Director, Military Lands and Cantonments Rs. 1,300—60—1,600

- (iv) Assistant Director, Military Lands and Cantonments. Rs. 1,100—50—1,400.

Class I

- (v) Deputy Assistant Directors, Military Lands and Cantonments, Military Estates Officers and Executive Officers. Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1250.

Class II

- (vi) Executive Officers. Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.
- (vii) Assistant Military Estates Officers. Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.

(h) (i) Class I Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers, and as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II Cantonments to which sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable. (ii) Class II Executive Officers will normally be appointed to Cantonments other than those mentioned in (i) above.

(i) (i) All promotions will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government. On promotion from Class II to Class I, pay will be regulated under the Fundamental Rules.

(ii) No officer will normally be promoted to Class I unless he has completed three years of service in Class II.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply.

(k) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government.

(l) The Military Lands & Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

13. Indian Railway Traffic Service :—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Indian Railway Traffic Service for a period of three years during which they will undergo the training as indicated in para. (m) and put in a minimum period of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case, due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended.

(b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Indian Railway Traffic Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side. Probationary Officers will be required to undergo practical training for the first two years. Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable will be placed in charge of a working post, provided they have passed the prescribed departmental and other examinations. It must be noted that these examinations should, as a rule, be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed. Failure to pass any of the examinations may result in the termination of service and will, in any case, involve stoppage of increment.

At the end of one year in a working post, the Probationary Officers will be required to pass a final examination, both practical and theoretical, and will

as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary period is extended for any reason, the drawal of the first and subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

- (d) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils the requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

- (e) Officers (including probationers) of the Indian Railway Traffic Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund, as amended from time to time.

- (f) Pay will commence from the date of joining service. Service for increments will also count from that date.

- (g) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the rules for the time being in force applicable to officers of Indian Railways.

The Leave Rules are liable to revision in the light of the accepted recommendations of the Pay Commission. They will not be permitted to retain the present Leave Rules, if so decided by the Government.

- (h) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway. But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India..

- (i) The relative seniority of officers appointed will ordinarily be determined by their order of merit in the competitive examination; if the period of training and consequently the period of probation has to be extended in any particular case due to the training having not been completed satisfactorily, the officer will be liable to lose in seniority. The Government of India, however, reserve the right of fixing seniority at their discretion in individual cases. They also reserve the right of assigning to officers appointed otherwise than by a competitive examination positions in the seniority list at their discretion.

- (j) Scales of pay :—

Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700—(6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that on

which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale, with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

- (k) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department.

- (l) Promotions to the administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion.

- (m) Courses of training for probationers in the Indian Railway Traffic Service.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion, the period of training in the case of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer is such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case, the officers will not be confirmed till they pass the tests, their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below have been drawn up chiefly for the purpose of guidance; they may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed.

- (1) Length of course—two years.

Item	Period
1. National Academy of Administration, Mussoorie	4 month(s)
2. Area School, to learn Guard's duties	1 ..
3. Working as Guard	$\frac{1}{2}$..
4. Training in Baroda Staff College (1st phase).	3 ..
5. Booking Office, Parcel Office, Goods Shed and Transhipment shed	1 ..
6. Traffic Accounts including a period with the Travelling Inspector of Accounts & Personal preparations of balance sheets at stations	1 $\frac{1}{2}$..
7. Area School to qualify as Asstt. Station Master	1 ..
8. Working as Yard Master, Asstt. Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner	3 ..

Item	Period
9 Working as Asst. Loco Foreman . . .	1/2 ..
10. Working as Assistant Controller . . .	2 ..
11. Training at Baroda Staff College (Ind phase) . . .	1 1/2 ..
12. (a) Training in District or Divisional Office . . .	1 ..
(b) Training as Assistant Power Controller . . .	1/2 ..
13. Training in Headquarters Office (Operation) . . .	1 1/2 ..
14. Training in Headquarters Office (Commercial) . . .	1 1/2 ..
	23 1/2 ..
Periods set apart for journey time for taking up various items for training and inescapable leave . . .	1/2 ..
TOTAL . . .	24 months

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years' training, a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE.—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller, he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

14. The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II—

(a) The Central Secretariat Service has, at present, the following grades :—

Grade	Scales of pay
Selection Grade—Deputy Secretary or equivalent . . .	Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800.
Grade I—Under Secretary . . .	Rs. 900—50—1250.
Section Officer's Grade . . .	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
Assistants Grade . . .	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Selection Grade and Grade I are controlled by the Ministry of Home Affairs on an all-Secretariat basis. Section Officers'/Assistants' Grades, however, are controlled by the Ministries.

Direct recruitment is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been

unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of 'Sections' while officers of Grade I will normally be incharge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Class I and Class II Officers.

15. Customs Appraisers' Service Class II—

(a) The prescribed scale of pay is Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Officers recruited direct to this service will be on probation for two years, during which period they will undergo such training and pass such departmental test as may be prescribed by the Central Board of Excise and Customs. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test will result in the discharge of the probationer from service.

(b) On the conclusion of the period of probation and the successful passing of the Departmental Test the Officers will be eligible for confirmation subject to the availability of permanent post. If his work or conduct has, in the opinion of the Collector of Customs concerned, been unsatisfactory he may be discharged from service or his period of probation may be extended as the Collector of Customs concerned may think fit.

(c) After a period of Service as Appraisers the Officers will be eligible for promotion to the Grade of Principal Appraiser in the scale of Rs. 600—35—950—and thereafter to the posts of Assistant Collectors, Class I.

(d) As regards leave, pension and other conditions of service, they will be treated like other Class II, Officers.

NOTE.—The scales of pay and grades given above are liable to revision.

16. Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories.

(e) Scales of pay—

Grade I—Selection Grade—Rs. 900—50—1,200.

Grade II—Rs. 300—30—510—EB—30—600—40—720—EB—40—800—50—850.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are at present entitled to get dearness allowance at the rates admissible to officers of comparable status employed under the Government of Punjab.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places either for training or on duty where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

17. The Railway Board's Secretariat Service, Class II—

(a) The Railway Board Secretariat Service consists of the following :—

Service	Scale of pay
(i) Assistant Director/Under Secretary.	Rs. 900—50—1750.
(ii) Section Officer	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
(iii) Assistant	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants.

(b) Officers recruited direct as Section Officers will be on probation for two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the Probationer from service.

(c) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers who have acquired sufficient experience by working in the sections in the Secretariat will normally be heads of Sections while Assistant Director/Under Secretary will normally be incharge of branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion as Assistant Director/Under Secretary in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Assistant Director/Under Secretary will be eligible for appointment to higher posts in the Railway Board's Secretariat.

(h) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(i) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and Privilege Ticket Orders on the same scale as admissible to Railway Officers.

(j) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the Rules of that fund as amended from time to time.

(k) As regards leave and other conditions of service, officers of the Railway Board Secretariat Service will be treated similar to other Class I and Class II Officers on Railways but in the matter of Medical facilities they will be governed by the Rules applicable to other Central Government employees headquartered at New Delhi.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. But it must be clearly understood that the Government of India reserve to themselves an absolute discretion to reject as unfit any candidate whom they may consider on the report of the Medical Board, to be physically disqualified and that their discretion, is in no respect limited by these regulations. These regulations are intended merely for the guidance of Medical Examiners and are not meant to restrict their discretion in any way for the disabled *ex-Defence Services* personnel the standards will be relaxed consistent with requirements of the Service(s)].

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However, for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

	Height	Chest girth (fully expanded)	Expansion
(1) Indian Railway Traffic Service	152 cms	84 cms	5 cms (For men)
	150 cms	79 cms	5 cms (For women)
(2) Indian Police Service, Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II	165 cms	84 cms	5 cms (For men)
	150 cms	79 cms	5 cms (For women)

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Tribals, etc., whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other

sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of a half of a kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(i) *General*.—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sort as to render or likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity*.—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

	Distant vision		Near vision	
	Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
1	2			
1. Indian Railway Traffic Service	6/9	6/9	Sn. 0.6	Sn. 0.8
	6/6	6/12		
2. I.A.S., I.F.S., Central Information Service (Grade II), Class I, Indian Audit & Accounts Service, Indian Customs & Central Excise Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Income-tax Service, (Class I), Indian Postal Service, Indian Railway Accounts Service, Military Lands and Cantonment Service, Class I, Central Secretariat Service, Section Officers' Grade Class II, Customs Appraisers' Service, Class II, Delhi & Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II, Railway Board Secreta-				

1	2			
riat Service, Class II Military Lands and Cantonment Service, Class II.	6/9	6/9	Sn. 0.6	Sn. 0.8
	6/6	6/12		
3. Indian Police Service and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service (Class II)	6/9	6/9	Sn. 0.6	Sn. 0.8
	6/6	6/12		

NOTE :—

(1) In respect of Services mentioned at 1 and 3 above, total amount of Myopia (including the cylinder), shall not exceed —4.00D in each eye. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D in each eye.

(2) In respect of Services mentioned at 2 above, total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —3.00D in each eye. Total amount of Hypermetropia shall not exceed +6.00D in each eye.

(3) *Fundus Examination*.—Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

(4) *Colour Vision*.—(i) The testing of colour vision shall be essential in respect of services mentioned at 1 and 3 above.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidates	4.9 metres	4.9 metres
2. Size of aperture	1.3 mm.	13 mm.
3. Time of exposure	5 sec.	5 sec.

For the services concerned with the safety of the Public, e.g., pilots, drivers, guards etc., the higher grade of colour vision is essential but for other the lower grade of colour vision should be considered sufficient.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

(5) *Field of vision*.—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(6) *Night Blindness*.—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests, e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been therefor 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(7) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma, unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—For services mentioned at 1 and 3 above where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of the prescribed standard should be considered as a disqualification. For the other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7. Blood Pressure

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic press is as follows :—

- (i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.
- (ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm. and diastolic over 90 mm. should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise of excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 m.m. The Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as a pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his

opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. The following additional points should be observed :—

- (a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has not progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services;
- (b) that his/her speech is without impediment;
- (c) that his/her teeth, are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);
- (d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;
- (e) that there is no evidence of any abdominal disease;
- (f) that he is not ruptured;
- (g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;
- (h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;
- (i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;
- (j) that there is no congenital malformation or defect.
- (k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;
- (l) that he bears marks of efficient vaccination; and
- (m) that he is free from communicable disease.

10. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing, appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise of field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters)
2. State your age and birth place
3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent of any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks rheumatism, appendicitis ?
- Or
- (b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?
4. When were you last vaccinated ?
5. Have you or any of your near relations been afflicted with consumption, scrofula, gout, asthma, fits, epilepsy, or insanity ?
6. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause ?

7. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at, and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at, and cause of death

8. Have you been examined by a Medical Board before ?
9. If answer to the above is, Yes, please state what Service/Services you were examined for ?
10. Who was the examining authority
11. When and where was the Medical Board held ?
12. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known
- I declare all the above answers to be, to the best of my beliefs true and correct.

Candidate's signature

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination

1. General development : Good.....Fair.....
Poor.....
Nutrition : Thin.....Average.....Obese.....
Height (Without shoes).....Weight.....
Best Weight.....When ?.....Any recent change
in weight ?.....Temperature.....

Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin : Any obvious disease

3. Eyes :

(1) Any disease

(2) Night blindness

(3) Defect in colour vision

(4) Field of vision

(5) Visual acuity

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glass Sph. Cyl. Axis
Distant vision	R.E. L.E.		
Near vision	R.E. L.E.		
Hypermetropia (Manifest)	R.E. L.E.		

4. Ears : Inspection Hearing : Right Ear.....
Left Ear.....

5. Glands Thyroid

6. Condition of teeth

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesions ?

Standing

After hopping 25 times

2 minutes after hopping

(b) Blood Pressure : Systolic Diastolic

9. Abdomen : Girth Tenderness.....
Hernia.....

(a) Palpable : Liver Spleen
Kidneys..... Tumours

(b) Hemorrhoids..... Fistula

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities

11. Loco-Motor System : Any abnormality

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele. Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance

(b) Sp. Gr.

(c) Albumen.....

(d) Sugar

(e) Casts

(f) Cells

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

15. (i) State the Services for which the candidate has been examined :—

(a) IAS & IFS

(b) IPS & Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service—

(c) Central Services, Class I & II.....

(ii) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in :—

(a) IAS & IFS

(b) IPS and Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service—

(see especially height, chest girth, eye sight, colour blindness and locomotive system).

(c) Indian Railway Traffic Service.

(see especially height, chest, eye sight, colour, chest, eye sight, colour, blindness).

(d) Other Central Services Class I/II

(iii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE.....

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :—

(i) Fit

(ii) Unfit on account of

(iii) Temporary unfit on account of

Place

Date

Chairman

Member

Member

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY
DEVELOPMENT AND COOPERATION**
(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 16th, February 1967

*No. 6-15/66-Soil Cons. (Pl).—*The question of control of further spread of ravines into a vast area of fertile agricultural lands and proper utilisation of the extensive tracts already ruined by the network of ravines in the States of Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat has been under the consideration of the Government of India for some time. These areas have not received adequate attention in the past because of lack of adequate inter-state coordination, the large financial outlays required and the long-term nature of the investment for productive benefits. The Government of India have therefore decided to constitute a Central Ravine Reclamation Board to ensure ravine control on proper lines and a more rapid development of the areas. The Board will consist of the following :—

Chairman

1. Secretary to the Government of India, Department of Agriculture.

Members

2. One representative from the State Government of Uttar Pradesh.
3. One representative from the State Government of Madhya Pradesh.
4. One representative from the State Government of Rajasthan.
5. One representative from the State Government of Gujarat.
6. Joint Secretary in-charge of the subject in the Department of Agriculture.
7. Inspector General of Forests, Department of Agriculture.
8. Agricultural Production Commissioner.
9. Soil Conservation Adviser Department of Agriculture.
10. Deputy Adviser Soil Conservation (Forestry) Department of Agriculture.
11. One representative of the Planning Commission.
12. One representative of the Ministry of Finance, Government of India.
13. One representative of the Ministry of Irrigation & Power, Government of India.
14. Surveyor General of India or his nominee.

Member-Secretary

15. Deputy Adviser Soil Conservation (Engineering) Department of Agriculture, Government of India.
2. The functions of the Board will be :—
- (i) to advise on the formulation of national policies and objectives on ravine lands in order to ensure that such areas receive the attention they deserve.
 - (ii) to keep under constant review the preparation of plans and programmes for carrying out the implementation of the agreed policy of ravine control and reclamation.
 - (iii) to keep under review the execution of these schemes through the various agencies of the State and Central Governments.
 - (iv) to assist in close inter-state coordination and remove administrative bottlenecks hindering the progress of the schemes.
 - (v) to arrange for collection of basic data and training of personnel required for the execution of the schemes.
 - (vi) to review the progress of the schemes.

3. The Board will meet at least once in a year and may meet as often as may be decided by the Chairman.

4. The Chairman of the Board may invite to its meetings any person associated with the problem of ravine reclamation.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all members of the Central Ravine Reclamation Board, all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. SIVARAMAN, Secy.

New Delhi, the 21st February 1967

*No. 6-1/66-SAP.—*The Government of India nominate the Director, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur as an Additional Member of the Central Desert Development Board set up vide this Ministry's Resolution No. 6-1/66-SAP, dated the 18th June, 1966.

P. P. I. VAIDYANATHAN, Additional Secy.

(Department of Co-operation)

New Delhi, the 14th February 1967

*No. 6-7/65-B.C.—*In continuation of this Department's Resolution No. 6-7/65-B.C., dated the 22nd July, 1965, it is notified that Additional Secretary, Department of Co-operation is nominated as a member of the National Advisory Board for Labour Contract and Construction Cooperatives vice Secretary, Ministry of Community Development and Co-operation.

ORDER

ORDERED that copy of the Notification be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

A. C. BANDOPADHYAY, Jr. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd February 1967

SUBJECT :—National Book Development Board

*No. F.23-87/65-(U.4)-HE-I.—*The development of book industry in general and of textbook production in particular has been lagging in the country for a long time. There has been an increasing awareness of the paucity of suitable books of all types by Indian authors published in India. Consequently, there has been a growing demand for the Central Government to play a more positive role in the whole field of book production. It has become necessary that the Government should evolve and implement a coordinated policy on an all-India basis for promotion of book production and development of book industry, as a whole, in the country.

2. *National Book Development Board.*—Therefore, in order to stimulate production of books of all types, the Government of India has decided to set up a National Book Development Board which would lay down the guidelines for the development of the book industry in the context of the overall requirements of the country. The Board which will have on it representatives of the different sectors of the book industry as well as of the various governmental and non-governmental agencies dealing with implementation of book programmes, will, after taking a total view of the activities in the sphere of book production, make concrete recommendations for consideration and action by the Government and other concerned bodies.

3. *Functions of the Board.*—The functions of the Board shall be as follows :—

- (a) To lay down the guidelines for development of the book industry in the context of the overall requirements of the country, including those in the field of higher education;
- (b) To assess and advise in undertaking, organising and carrying out research into writings, marketing problems, particularly in export areas, and to study how best the widest possible distribution of Indian books could be obtained;

- (c) To advise on measures for the promotion of the book industry and trade;
- (d) To advise on measures for encouraging Indian authors to write suitable textbooks and Indian publishers to publish them;
- (e) To perform such other functions, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be required in order to further its objects.

4. *Headquarters of the Board*: The Headquarters of the Board shall be at New Delhi.

5. *Composition of the Board*:

- (a) Chairman to be nominated by the Government of India.
- (b) One representative of the Ministry of Education.
- (c) One representative of the Ministry of Industry.
- (d) One representative of the Ministry of Commerce.
- (e) One representative of the Ministry of Information and Broadcasting.
- (f) One representative of the Ministry of Finance.
- (g) One representative of the University Grants Commission.
- (h) One representative of the Council of Scientific and Industrial Research.
- (i) One representative of the NCERT.
- (j) One representative of the National Book Trust.
- (k) Such other persons, not exceeding twenty as may be nominated by the Government of India from time to time, from among the various interests connected with book publishing, printing and trade.

6. *Tenure of Membership*: The tenure of each member of the Board shall be three years, but he will be eligible for re-appointment. Where a member of the Board becomes a member by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Board shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

All casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) shall be filled by the authority or body who nominated the member whose place has fallen vacant and the person appointed to a casual vacancy shall be a member of the Board for the residue of the term for which the person whose place was filled would have been a member.

7. *Meetings and Sub-committees*: The Board shall ordinarily meet twice a year. The Board may set up Committees for specific purposes which may meet as frequently as required.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories, all Ministries of the Government of India and their Departments, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

G. K. CHANDIRAMANI, Additional Secy.

Technical Division

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd February 1967

SUBJECT: *All-India Council for Technical Education—Amendment to the Resolution of the—*

No. F.1-2/64-T-2.—In modification of the Government of India in the late Department of Education Resolution No. F. 16-10/44-E.III dated the 30th November, 1945, as amended from time to time (upto 19th July, 1966), the President is pleased to order that in Sub-Clause (n) of Clause (i) of paragraph 3 in the Resolution, establishing the All India

Council for Technical Education, the word "Ten" may be amended to read as "Eleven". The Sub-Clause will then read as follows:—

"(n) Eleven representatives of Professional Bodies."

ORDER

ORDERED that the Resolution may be published in the Gazette of India.

ORDERED also that copies may be communicated to all the State Governments including Union Territories and Ministries of Government of India.

A. B. CHANDIRAMANI, Jt. Educational Adviser

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Transport and Shipping)

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th February 1967

No. 42-MD(4)/67.—The Government of India have decided that the composition of the Maritime Freights Commission set up under the Resolution of the Government of India in the Ministry of Transport and Communications, Department of Transport (Transport Wing), No. 24-MD(7)/62, dated the 12th December, 1962, shall be modified as follows:—

- (1) Shri K. B. Lal, Secretary, Ministry of Commerce, will be a Member *vice* Shri D. S. Joshi.
- (2) Shri S. Chakravarti, Secretary, Ministry of Transport & Aviation, will be a member *vice* Dr. Nagendra Singh.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to:

1. The Ministry of Commerce, New Delhi.
2. The Directorate General of Shipping, Bombay. (5 copies).
3. Shri Y. N. Sukthankar, Government Director on the Board of Directors of Indian Shipping Cos., C.G.O. Buildings, Queens Road, Bombay-1.
4. Shri K. B. Lal, Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi.
5. Shri S. Chakravarti, Secretary, Ministry of Transport & Aviation.
6. Shri D. S. Joshi, Cabinet Secretary, New Delhi.
7. Dr. Nagendra Singh, Secretary to the President, Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. MADAPPA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th February 1967

No. 36/14/67-NCL.—In partial modification of the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Resolution No. 36/14/66-1&E, dated the 24th December, 1966, Shri B. C. Ganguli is appointed as a member of the National Commission on Labour *vice* Shri G. D. Khandelwal.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and others concerned.

K. I. VIDYASAGAR, Jt. Secy.

